मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

बुधवार, दिनांक 04 मार्च 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्यालयों में शौचालय निर्माण

1. (*क्र. 2974) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एस.आर. (कारपोरेट सोशल रिसर्पोसबिलिटी) के तहत शिवपुरी जिले में कितनी व कौन-कौन सी कंपनियों/पी.एस.यू. को स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु किस आधार पर चयनित किया गया है? (ख) इन कंपनियों/पी.एस.यू. द्वारा कुल कितनी धनराशि शिवपुरी जिले में व्यय की जानी है व इस अभियान के तहत कुल कितने विद्यालयों को चयनित किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विद्यालयों में बनने वाले शौचालयों पर प्रति यूनिट कितनी धनराशि व्यय की जा रही है व शौचालय निर्माण का तकनीकी प्रस्ताव/प्राक्कलन किस एजेंसी द्वारा निर्मित कराये जा रहे हैं या कराये जावेंगे। (घ) इन निर्माण कार्यों की एजेंसी किसे निर्धारित किया गया है व उक्त निर्माण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सी.एस.आर. (कारपोरेट सोशल रिसर्पोसबिलिटी) के तहत शिवपुरी में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की साइट पर ब्लॉक किये गये हैं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) इन कंपनियों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 251 विद्यालयों में 330 शौचालय निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु ब्लॉक किये गये हैं। चयनित शौचालयों का निर्माण केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कारपोरेट सोशल रिसर्पोसबिलिटी के तहत उनके स्वयं के खर्च पर किया जाना है। अतः व्यय की जाने वाली धनराशि बताना संभव नहीं है। विकासखण्डवार जानकारी निम्न है :-

विकासखण्ड	विद्यालय की संख्या	बालिका शौचालय	बालक शौचालय	योग
शिवपुरी	32	5	28	33
कोलारस	86	42	60	102
पोहारी	44	41	36	77
नरवर	14	14	10	24

करैरा	06	07	06	13
पिछोर	58	09	55	64
खनियाधाना	11	07	10	17
योग	251	125	205	330

(ग) विद्यालयों में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा बनने वाले शौचालयों के निर्माण पर निम्न इकाई लागत अनुसार व्यय होना संभावित है :-

50 सीटर बालिका/बालिका शौचालय	लगभग रुपये 1.40 लाख
80 सीटर संयुक्त बालक बालिका शौचालय	लगभग रुपये 3.40 लाख

शौचालय निर्माण का तकनीकी प्रस्ताव/प्राक्कलन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा उनके स्वयं के द्वारा तैयार कर संपादित किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक प्रावधान राज्य शिक्षा केन्द्र के दिशा निर्देश अनुरूप हैं। (घ) सी.एस.आर. अंतर्गत कंपनियों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लॉक किये गये शौचालय का निर्माण उनके द्वारा निर्धारित एजेंसी के द्वारा किया जावेगा। उक्त निर्माण दिनांक 30.06.2015 तक पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन

2. (*क्र. 1999) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री को सम्बोधित पत्र क्रमांक 59 दिनांक 23.05.2014 एवं पत्र क्रमांक 150 दिनांक 06.07.2014 के द्वारा माध्यमिक शाला झिरिया, कटकी एवं दादर को हाई स्कूल में उन्नयन हेतु अनुरोध किया गया था एवं इस बात को भी संज्ञान में लाया गया था कि उक्त ग्रामों में लड़कियों की शिक्षा माध्यमिक के बाद इसलिये रोक दी जाती है कि हाई स्कूल हेतु लड़कियों को गांव से दूर भेजना पड़ता है? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या उक्त माध्यमिक विद्यालयों का हाईस्कूल में उन्नयन हो रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) - जी हाँ। वर्ष 2014-15 में प्रावधानित सभी 50 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन आदेश जारी किए जा चुके हैं, इनमें ये विद्यालय शामिल नहीं हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रति वर्ष सीमित संख्या में ही उन्नयन संभव हो पाता है। प्रतिवर्ष स्कूलों के उन्नयन की स्थिति परिवर्तनशील हो जाती है। कोई निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

उपस्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

3. (*क्र. 1215) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन निर्देशानुसार मानपुर उपस्वास्थ्य केन्द्र उन्नयन की सारी शर्तें भी पूरी करता है, इसके बावजूद वर्तमान जनसंख्या के मान से मानपुर उपस्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन न करने के क्या कारण हैं? (ख) क्या वर्तमान में संचालित मानपुर उपस्वास्थ्य केन्द्र में जनसंख्या के मान से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन, वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर उपस्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार करवाकर उसे स्वीकृति प्रदान करेगा एवं स्वीकृत राशि का प्रावधान वर्ष, 2015-16 के वार्षिक बजट में करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, जनसंख्या के निर्धारित मापदण्ड के मान से उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र के मान से मानपुर में पर्याप्त सुविधायें हैं। (ग) प्रश्न भाग (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लिफ्ट खराब होने से मृतक के परिवार को मुआवजा

4. (*क्र. 2680) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेता जी सुभाष चंद बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की सुरक्षा व्यवस्था संचालन, संधारण किसके अधीन है? क्या मेडिकल कॉलेज की एक लिफ्ट दिनांक 31/01/2015 को तीसरी मंजिल पर पहुंच कर खराब हो गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो अगर लिफ्ट बंद थी तो प्रबंधन द्वारा किसी तरह के हादसे से बचने हेतु क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? क्या लिफ्ट का चेंबर बंद कर दिया गया था? (ग) क्या इस बंद पड़ी लिफ्ट के नीचे गड्डे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई? यदि हाँ, तो मृतक का नाम, ग्राम क्या था एवं वह मेडिकल कॉलेज में क्या कर रहा था? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि चेंबर बंद नहीं किया गया, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है, इस वजह से लिफ्ट के चेंबर में गिरने से मृत हुये व्यक्ति के परिवार को शासन द्वारा समुचित मुआवजा प्रदान करते हुये शासन इसकी जाँच कराकर पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की सुरक्षा व्यवस्था का संचालन एवं संधारण आउटसोर्स के माध्यम से मेसर्स श्री बर्फानी सिक्यूरिटी सर्विसेस जबलपुर तथा मेसर्स एक्स सर्विसमैन सिक्यूरिटी फोर्स जबलपुर के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, दिनांक 31 जनवरी, 2015 की रात्रि से पैसंजर लिफ्ट बन्द हैं। (ख) दिनांक 31 जनवरी, 2015 की रात्रि से पैसंजर लिफ्ट खराब

होने के बाद लिफ्ट के चारों मंजिल के दरवाजें एवं चैम्बर बन्द थे। (ग) दिनांक 02 फरवरी, 2015 को लिफ्ट सर्विस इंजीनियर द्वारा जब लिफ्ट का सुधार कार्य किया जा रहा था तब उनके द्वारा सूचना दी गई, कि लिफ्ट के नीचे कोई व्यक्ति गिरा है। मृतक का नाम ओमप्रकाश वाजपेयी पिता स्व. श्री देवीदास वाजपेयी एवं माँ का नाम श्रीमती शकुन्तला वाजपेयी निवासी ग्राम खाजरी खैरिया पुलिस थाना जबलपुर है। मृतक चिकित्सालय के वार्ड नं. 13 में भर्ती मरीज अपने भाई विनोद वाजपेयी को देखने आया था। (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में एवं पुलिस द्वारा दर्ज मर्ग क्रं. 12 दिनांक 02 फरवरी, 2015 कायम कर विवेचनाधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बी.आर.सी.सी. के रिक्त पदों की पूर्ति

5. (*क्र. 2901) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.आर.सी.सी. के पद में नियुक्ति हेतु क्या-क्या आवश्यक योग्यता है? इस पद पर किन व्यक्तियों को पदस्थ किया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या उक्त पद पर संविदा के आधार पर भी नियुक्ति हो सकती है? यदि हाँ, तो प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर संविदा के आधार पर किस नाम के किस स्थान पर कब से नियुक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत किन-किन स्थानों पर निर्धारित योग्यता न रखने वालों को नियुक्त किया गया है? निर्धारित योग्यता न रखने वालों को कब तक हटा दिया जायेगा? (घ) प्रदेश के कितने स्थानों पर बी.आर.सी.सी. के पद रिक्त हैं? इन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संविदा आधार पर विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक के पदों पर नियुक्ति की गई थी, जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत इन कर्मचारियों को बी.ए.सी. के पदों पर समयायोजित किया गया। वर्तमान में उक्त आदेश के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर 4 कर्मचारी संविदा आधार पर बी.आर.सी.सी. के पदों पर कार्यरत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक तत्समय की निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) 9 स्थानों पर। राज्य शिक्षा सेवा के प्रावधानों के अंतर्गत पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है

परिशिष्ट - "एक"

जातियों को माझी जनजाति के समक्ष सम्मिलित किया जाना

6. (*क्र. 144) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा धीमर, कहार, भोई, केवट, कीर, मल्लाह, निषाद आदि को माझी जनजाति के समक्ष सम्मिलित करने संबंधी किन्हीं गठित समिति के प्रतिवेदनों पर आधारित शासन की अनुशंसा पर आ.जा.अ. संस्था द्वारा कभी कोई अभिमत दिये गये हैं और जिनके आधार पर ओ.आर.जी.आई. ने अपने किन्हीं पत्रों द्वारा अपनी कोई कमेंट्स दी है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अभिमत एवं कमेंट्स पर प्रश्नकर्ता ने मा. मुख्यमंत्री जी को दिनांक 01.09.2013/10.09.2013 एवं 07.07.2014 को दस्तावेजों सहित दिये गये स्पष्टीकरण प्रतिवेदनों में किन प्राचीन संदर्भ साहित्यों, जनगणनाओं, मंत्री-परिषद की संक्षेपिका, विधि विभाग के अभिमत और किसी संस्था के प्रतिवेदनों के किन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) पर आ.जा.अ. संस्था ने वर्ष 2013 व 2014 के किन्हीं दिनांकों को कोई वस्तुस्थिति व अभिमत विभाग को प्रस्तुत किया है और उसमें किन तथ्यों को किन तर्कों से अमान्य किया गया है जो किन आधारों पर न्यायोचित हैं? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने किन्हीं दस्तावेजोंयुक्त पत्र दिनांक 08.12.2014 द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी को कोई लेख कर की गयी अपेक्षा पर प्रश्नांश (क) (ख) (ग) तथ्यों पर विधि विभाग से विधि सम्मत अभिमत प्राप्त किया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। (घ) दिनांक 07/02/2015 से विभागीय अभिमत, मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित किया गया है।

बीड़ी श्रमिकों के कार्ड वितरण में विलंब

7. (*क्र. 1667) श्री संजय पाठक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 93) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 के उत्तरांश (ग) अनुसार 429 परिचय पत्र वितरित किये जा चुके हैं एवं 9 परिचय पत्र अवितरित हैं? (ख) क्या प्रश्नाधीन प्रश्न में उल्लेखित क्षेत्र में फरवरी-मार्च वर्ष 2014 में भी बीड़ी श्रमिकों के कार्ड बनाये जाने हेतु शिविर आयोजित किये गये थे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) 9 परिचय पत्र एवं प्रश्नांश (ख) वर्ष में आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदनों के परिचय पत्र वितरित कर दिये गये? यदि नहीं, तो दो वर्ष पश्चात कार्ड न वितरित किये जाने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सिहोरा, मझौली, पनागर तहसील में आयोजित शिविरों में बीड़ी श्रमिकों को कार्ड एक महीने के अंदर वितरित कर दिये गये? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के प्रश्न के उत्तरांश (ख) में कल्याण आयुक्त जबलपुर (भारत सरकार) द्वारा जो समय-सीमा न होने का उल्लेख किया है वह गलत है, जबकि जब कल्याण आयुक्त के द्वारा कैंप लगाये जाने संबंधी आदेश दिये जाते हैं तो उसमें कार्ड वितरण की दिनांक भी उल्लेखित होती है? फरवरी मार्च 2014 में विजयराघवगढ़ क्षेत्र में शिविर आयोजित किये जाने हेतु दिये गये शासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ड.) क्या संबंधित अधिकारी की मनमानी को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) कल्याण आयुक्त, भारत सरकार श्रम मंत्रालय जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 9 परिचय पत्रों का निराकरण/वितरण किया जा चुका है। 9 में से एक श्रमिक की मृत्यु हो चुकी है एवं एक श्रमिक निवास स्थान से स्थानांतरित हो चुका है शेष परिचय पत्र वितरित किये जा चुके हैं। (ख) हाँ, प्रश्नानुसार दिनांक 24 फरवरी, 2014 को बंजारी, 26 फरवरी, 2014 को बरही एवं 28 फरवरी, 2014 को कैमोर में शिविर आयोजित किये गये थे। (ग) (अ) परिचय पत्रों का निराकरण/वितरण किया जा चुका है। (ब) फरवरी, 2014 में आयोजित किये गये शिविरों में संबंधित परिचय पत्रों का वितरण वैद्य प्रभारी की सेवा निवृत्ति के दौरान अवकाश पर जाने, मंत्रालय से आवास, छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर संपन्न करने, कर्मचारियों की कमी, वाहनों की कमी एवं लोक सभा, विधानसभा चुनाव, आचार संहिता के कारण परिचय पत्र वितरण में विलंब हुआ। फरवरी, 2014 में शिविरों के माध्यम से पात्र आवेदनों के परिचय पत्र यथा बंजारी शिविर-185 बरही शिविर-124 एवं कैमोर शिविर 159 निर्मित किये जा चुके हैं। दिनांक 01.12.2014 से वैद्य प्रभारी को कटनी औषधालय में पदस्थ किया जा चुका है तथा उन्हें यथाशीघ्र परिचय पत्र वितरण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। (घ) उपरोक्तानुसार कार्यालयीन आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 पर है। (ड.) संगठन में कर्मचारियों की कमी, वाहनों की सीमित उपलब्धता के संबंध में मंत्रालय को समय-समय पर अवगत कराया जाता

रहा है। पुनः इस संबंध में संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर पत्राचार करने को कहा गया है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पद की पूर्ति

8. (*क्र. 290) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नागौद में चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? पदवार जानकारी दें। (ख) क्या स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद विगत कई वर्षों से रिक्त है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई लेडीज की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के अभाव में 2-3 दिनों तक पोस्टमार्टम कक्ष में पड़ी रहती है, जब सतना से स्त्री रोग विशेषज्ञ आती हैं तभी पोस्टमार्टम होता है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक स्थाई स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना कराकर गरीब जनता को राहत प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, मृत महिलाओं की बॉडी का पोस्ट मार्टम तत्काल उसी दिन व्यवस्था की जाकर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरुद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

समग्र छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

9. (*क्र. 2388) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के सभी कक्षाओं के छात्रों की आई.डी. मैपिंग का कार्य वर्ष 2014-15 का पूर्ण हुआ या नहीं सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्या आई.डी. मैपिंग के कारण छात्रों को समग्र छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति फरवरी 2015 तक प्राप्त नहीं हो सकी है? कारण सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) समग्र छात्रवृत्ति योजना का समय पर क्रियान्वयन होने के लिये शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार विकासखण्डवार जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों को दी गई? उनके नाम पद सहित पूर्ण जानकारी दी जावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 4, 86, 660 (98.6%) छात्रों की आई.डी मैपिंग

कार्यपूर्ण हो चुका है, शेष छात्रों की कार्रवाई प्रचलन में है। (ख) छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीन"

छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति

10. (*क्र. 2626) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 में केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, तत्संबंध में अभी तक म.प्र. शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) छिन्दवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 19/2/2014 द्वारा छिन्दवाड़ा में जिला अस्पताल का उन्नयन कर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है। (ख) निश्चित समय अवधि दी जाना सम्भव नहीं है, अतएव शेष प्रश्न प्रस्तुत नहीं होता।

नियम विरुद्ध अनियमित कृत्यों की जाँच

11. (*क्र. 2838) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार द्वारा म.प्र. शासन के राजपत्र में प्रकाशित नियमों के विरुद्ध असंवैधानिक एवं मनमाने ढंग से बोर्ड के निर्वाचन कराए जाने एवं आर्थिक अनियमितता जैसे रजिस्ट्रार द्वारा नियम विरुद्ध एन.पी.ए. प्राप्त करना, सालाना बजट वर्षान्त (31 मार्च) की स्थिति में पारित नहीं किया जाना आदि के संबंध में विगत 02 वर्षों में किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी शिकायतें शासन स्तर पर एवं संचालनालय आयुष को प्राप्त हुई? (ख) उक्त शिकायतों की जाँच कब-कब, किस-किस अधिकारी के द्वारा कराई गई एवं जांचोपरांत दोषी अधिकारी के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों तथा क्या रजिस्ट्रार से नियम विरुद्ध लिए एन.पी.ए. की राशि की वसूली की जावेगी? (ग) क्या रजिस्ट्रार द्वारा बोर्ड द्वारा दिनांक 26.03.2010 की बैठक में पारित अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव के अनुरूप नियुक्ति न की जाकर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को नियम विरुद्ध सेवावृद्धि प्रदान की गई? क्या दिनांक 27.08.2014 को बोर्ड निर्वाचन समिति द्वारा बोर्ड रजिस्ट्रार नियुक्ति का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो बोर्ड के उक्त निर्णय के बावजूद भी प्रभारी रजिस्ट्रार के स्थान पर अन्य अधिकारी की नियमित पदस्थापना क्यों नहीं की गई? (घ) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त प्रश्नांश के संबंध में जाँच कराई जाकर दोषी रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित सरल क्र. 1 से 4 तक की शिकायतों की जाँच संचालनालय पत्र क्र./1/विजां/शिका/सीआर/1773-74, दिनांक 03/09/2014 से संभागीय आयुष अधिकारी, भोपाल से कराई गई। जाँच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया था, शिकायतकर्ताओं ने बताया कि यह शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई है, साथ ही यह भी बताया कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत की गई है। अंत में जाँच अधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में निम्नानुसार अभिमत दिया है- "उक्त शिकायतें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर की गई हैं, जिन्हें बिना सबूत एवं कथन के सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। "जाँच प्रतिवेदन एवं शिकायत एवं शिकायत में उल्लेखित बिन्दु संचालनालय स्तर पर परीक्षाधीन हैं। इसी अनुक्रम में शिकायती बिन्दुओं के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। परिशिष्ट "अ" के सरल क्रमांक 5 से 12 पर अंकित शिकायतों के बिन्दु सरल क्रमांक 1 से 4 पर उल्लेखित शिकायतों के बिन्दुओं के समान प्रकृति के होने से इनकी जाँच पृथक से नहीं कराई गई है। एन.पी.ए. नियमानुसार दिये जाने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 26.03.2010 की बैठक में रिक्त पदों को भरने के संबंध में पारित प्रस्ताव इस प्रकार है :- रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने संबंधी प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर रिक्त पदों की पूर्ति करने की अनुमति प्रदाय की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। जून 2014 की बैठक में दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक वर्ष की सेवावृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार दिनांक 27/08/2014 की बैठक में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में पारित प्रस्ताव इस प्रकार है :- बोर्ड के निष्पक्ष निर्वाचन के लिये बोर्ड अपना रजिस्ट्रार स्वयं नियुक्त करें। अधिनियम पाँचवा अध्याय नियम 20 के आधार पर बाई एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जो बोर्ड सचिव के रूप में कार्य करेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। दिनांक 27.08.2014 के कार्यवाही विवरण में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख है कि दिनांक 26/03/2010 की बैठक में बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया जबकि 26/03/2010 की बैठक में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रंथपालों को शिक्षकीय वेतनमान

12. (*क्र. 2966) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के राजपत्र क्रमांक 356 दिनांक 04.08.12 के सरल क्रमांक 13 में ग्रंथपालों को भी शिक्षक संवर्ग में घोषित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या

प्रश्न दिनांक तक ग्रंथपालों को न ही शिक्षकीय वेतनमान और न ही सेवानिवृत्त आयु 62 की गयी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो दोनों का लाभ कब तक दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। ग्रंथपालों हेतु अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमाविद्यालयर्तयर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 है। ग्रंथपालों को शिक्षक संवर्ग में घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रंथपालों द्वारा शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। (ख) एवं (ग) उत्तर "क" के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन तथा नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाना

13. (*क्र. 1499) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत है, उक्त पदों पर कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी कब से कार्यरत है? सूची दें। (ख) उक्त जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? कारण बतायें। उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त जिलों में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन तथा नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिये माननीय मंत्री जी तथा विभाग को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। विभाग में विशेषज्ञों एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी हैं। चिकित्सा अधिकारियों हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा पैरामेडिकल के 900 पदों पर सीधी भर्ती हेतु मांग पत्र व्यापम को प्रेषित किया गया है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

भवन विहीन हाई स्कूलों का भवन निर्माण

14. (*क्र. 1964) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भवन विहीन हाई स्कूलों के भवन बनाये जाने के संबंध में क्या प्रावधान है? विवरण उपलब्ध करावें। (ख) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में कितने-कितने हाई स्कूल संचालित हैं? शालावार सूची उपलब्ध करावें। कितने हाई स्कूल कब से भवनविहीन हैं? भवन निर्माण की क्या योजना है? (ग) क्या विकास खण्ड सिहोरा अंतर्गत हाई स्कूल गुनहरू, मोहसाम एवं मढा परसवारा भवनविहीन होने के कारण माध्यमिक शाला के भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है? इन स्कूलों के भवन कब तक बना दिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) हाईस्कूलों के भवन निर्माण का प्रस्ताव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार की स्वीकृति तथा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** प्रश्नांश "क" में दिए गए उत्तर अनुसार भवन निर्माण संभव होता है। (ग) शालाएं माध्यमिक शाला भवनों में विधिवत संचालित होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। शाला भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। उक्त दोनों शालाओं में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 04 अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

परिशिष्ट - "चार"

नसबंदी के दौरान मृतक महिला के परिवार को मुआवजा

15. (*क्र. 182) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 में जिला सिंगरौली के अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये थे, इनके भवन निर्माण की स्थिति क्या है? इन भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण कब तक कराया जायेगा तथा विभिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं तथा इनकी पूर्ति कब तक की जायेगी? (ख) क्या दिनांक 16.01.2015 को जिला स्वास्थ्य केन्द्र बैढन में नसबंदी के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो मृतक के परिवार को क्या नौकरी या मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो शासन द्वारा मृतक के आश्रित परिवार को नौकरी एवं मुआवजा के संबंध में क्या निर्णय लिया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2013-14 में जिला चिकित्सालय सिंगरौली के अंतर्गत 45 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये थे, सभी भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। यथाशीघ्र, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 20 ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। मृतिका के परिवार को राशि रुपये 2 लाख का मुआवजा दिया गया है, नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) तीन चिकित्सकों के दल द्वारा मृतिका का शव परीक्षण किया गया। इसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होना बताया है। किसी चिकित्सक के दोषी होने का उल्लेख नहीं किया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

योजना राशि के उपयोग में अनियमितता

16. (*क्र. 3007) पं. रमेश दुबे :क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा को वित्तीय वर्ष 2011-12 से अगस्त 2014 तक आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम. योजना के तहत कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि में से किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी? वर्षवार प्राप्त राशि, कार्यवार खर्च राशि की जानकारी दें। (ख) क्या छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में उक्त वर्षों में उक्त योजना के तहत प्राप्त राशि का मोबिलिटी वाहनों पर एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम पर अव्यवहारिक रूप से खर्च किया गया है, जिसका विधिवत हिसाब भी नहीं रखा गया है? (ग) क्या उक्त योजनाओं की राशि का भुगतान दो जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर से व्यय करने के शासन के आदेश-निर्देश हैं फिर भी शासनादेशों के आदेश निर्देश के विरुद्ध जाकर विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से चैक जारी कर भारी अनियमितता की गयी है? (घ) क्या शासन आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम. योजना की राशि का नियम विरुद्ध अव्यवहारिक खर्च, उक्त प्रकार की अनियमितता शासन स्तर से जाँच करवाकर दोषियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौराई एवं अमरवाड़ा को वित्तीय वर्ष 2011-12 से अगस्त 2014 तक आर.सी.एच.

एवं एन.आर.एच.एम योजना के साथ प्राप्त राशि एवं खर्च का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	वर्ष	योजना/कार्य	चौरई		अमरवाड़ा	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2011-2012	आर.सी.एच	65,00,000	65,31,310	78,50,000	78,93,529
		एन. आर. एच. एम	35,25,000	40,70,600	40,25,000	49,58,267
		ईम्यूनाईजेशन	3,30,000	3,70,250	3,30,000	3,48,930
2	2012-13	आर.सी.एच	95,42,800	86,70,988	1,07,04,	82,71,

					100	583
		एन. आर. एच. एम	3567201	21, 17, 0460	24, 39, 040	82, 71, 583
		ईम्यूनाईजेशन	12, 07, 000	3, 46, 925	12, 03, 000	11, 07, 090
3	2013-2014	आर.सी.एच	1, 13, 00, 000	98, 15, 228	1, 03, 00, 000	1, 16, 24, 312
		एन. आर. एच. एम	67, 00, 000	46, 80, 333	60, 00, 000	57, 48, 445
		ईम्यूनाईजेशन	8, 78, 580	10, 18, 860	10, 18, 860	11, 58, 175
4	2014-2015 (अगस्त 2014 तक)	आर.सी.एच	38, 00, 000	22, 00, 466	45, 00, 000	20, 76, 237
		एन. आर. एच. एम	37, 00, 000	5, 85, 7800	32, 00, 000	5, 92, 776
		ईम्यूनाईजेशन	2, 00, 000	1, 18, 850	3, 00, 000	87, 250

(ख) छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा में उक्त वर्षों में उक्त योजना के तहत प्राप्त राशि का मोबिलिटी वाहनों पर एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यावहारिक रूप से खर्च किया गया है, जिसका विधिवत हिसाब रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में उक्त वर्षों में उक्त योजना के तहत प्राप्त राशि का मोबिलिटी वाहनों पर एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का अव्यवहारिक रूप से खर्च होना सम्भावित है। (ग) जी हाँ, उक्त अवधि में विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी चौरई के द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से चैक जारी कर अनियमितता की गई है। (घ) जी हाँ। पायी गई अनियमितताओं की जाँच कराई जायेगी। जाँच प्रतिवेदन में गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मलेरिया, डेंगू व स्वाइन फ्लू की रोकथाम के उपाय

17. (*क्र. 2567) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में विगत तीन वर्षों में बुखार, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हुईं? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें। (ख) सीहोर जिले में पिछले तीन वर्षों में सरकारी अस्पतालों में बुखार, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू के कितने मरीजों का इलाज हुआ? अस्पतालवार, माहवार जानकारी दें। (ग) म.प्र. में प्रश्नांश (क) बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए? सीहोर जिले में रोकथाम हेतु कितनी राशि व्यय की गई? अस्पतालवार विगत तीन वर्षों की जानकारी दें। (घ) म.प्र. में प्रश्न दिनांक तक स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हुईं? कितने मरीज पाए गए?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) म.प्र. में विगत तीन वर्षों में बुखार, मलेरिया 118, डेंगू 28 एवं स्वाइन फ्लू से 66 मौतें हुई हैं। वर्षवार जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) स्वास्थ्य विभाग बीमारियों के नियंत्रण के लिए पूर्ण रूप से सजग है एवं नियंत्रण की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जन सामान्य में बीमारियों के नियंत्रण के लिए आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स तथा टी.व्ही. चैनल के माध्यम से प्रसारण करवाया गया है। समाचार पत्रों में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जनहित में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। सभी शासकीय चिकित्सालयों/अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। मरीजों के प्लेटलेट काउंट करने के लिए सेल काउंटर एवं हिमेटोक्र्रीट की जाँच की व्यवस्था सभी जिलों में है। आवश्यक सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रदेश के 11 जिलों में 15 स्थानों पर मेक-एलाइजा से डेंगू की जाँच की सुविधा उपलब्ध है, इसी प्रकार स्वाइन फ्लू की जाँच के लिए भोपाल (एम्स), ग्वालियर (डी.आर.डी.ए.लैब), जबलपुर (आई.सी.एम.आर.) में व्यवस्था है। निजी चिकित्सालयों व शासकीय चिकित्सालय भोपाल के चिकित्सकों को डेंगू के उपचार हेतु मार्गदर्शन के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेस, भारत सरकार से विशेषज्ञ दल भी बुलाया गया था, जिन्होंने उपचार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसी प्रकार मेडीकल कॉलेज के विशेषज्ञों द्वारा संभाग स्तर पर जिलों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी डेंगू के उपचार के संबंध में प्रशिक्षण कराया गया है। दल ने राज्य में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। वैक्टर जनित बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में पूर्व से ही समस्त तैयारियां की गई थीं, इसके अंतर्गत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक दिनांक 07/05/2014 तथा 26-27 मई 2014 को जिला मलेरिया अधिकारियों/जिला व्हीबीडी सलाहकारों/आईडीएसपी के एपिडिमियोलॉजिस्ट के साथ बैठक आयोजित कर लार्वा विनिष्टिकरण एवं वैक्टर विनिष्टिकरण का प्रशिक्षण दिया गया था। मलेरिया/डेंगू के प्रभावी

नियंत्रण हेतु प्रदेश स्तर से प्रोटोकॉल तैयार किया गया है जो सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिलों से इसे ग्राम स्तर तक भेजा गया है तथा उसी के अनुरूप नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को भी डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव तथा राज्य के समस्त 52000 ग्रामों में आवश्यक औषधियों के भण्डारण के निर्देश दिए गये थे, इस कारण राज्य के सभी ग्रामों में वर्षा ऋतु के पूर्व ही आगामी छःमाहों की आवश्यक औषधियों को भण्डारित कर लिया गया था। राज्य में डेंगू एवं मौसमी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह प्रमुख चरण था। प्रदेश में 5000 सेक्टर, 59285 आशा कार्यकर्ता, 16000 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष/महिला) के माध्यम से बीमारियों के नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम स्तर से जिला स्तर एवं जिला स्तर से राज्य स्तर पर आउटब्रेक की सूचना प्राप्त करने हेतु कॉलसेंटर संचालित हैं तथा किसी भी ग्राम से किसी भी बीमारी की आउटब्रेक की रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू के मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में सर्दी जुकाम (स्वाइन फ्लू H1N1) काउंटर बनाए गए हैं, जो 24X7 घंटे कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सभी मेडीकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू (H1N1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आईसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वाइन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेडीकल कॉलेज अस्पतालों औषधियां/सामग्रियां आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी गई हैं। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम/हेल्प लाइन नं. सामान्य जन मानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए हैं। प्रचार-प्रसार मशाल रैली, होर्डिंग्स, पम्पलेट्स, वॉल पेंटिंग्स, रेडियो जिंगल्स, टी.व्ही. स्कॉल आदि के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा समुदाय के लिए स्वाइन फ्लू जागरूकता हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से अपील की गई है। जिला सीहोर में मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए वृहद कार्ययोजना बनाकर कार्य किया गया है। मलेरिया जाँच एवं निदान हेतु समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय में सुविधा उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू के लिए जिला चिकित्सालय में एक आईसोलेशन वार्ड बनाया जाता है और अलग से सर्दी खाँसी के मरीजों की ओपीडी की जाती है। मलेरिया व डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए पायरेथ्रम, टेमोफॉस दवा का छिड़काव किया जाता है, मलेरिया जाँच के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट एवं रक्तपट्टी द्वारा जाँच सीहोर जिले के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में की जाती है एवं डेंगू जाँच के लिए सैम्पल भोपाल स्थित मेडीकल कॉलेज, बी.एम.एच.आर.सी, जेपी अस्पताल एवं मलेरिया लैब में भेजे जाते हैं। सीहोर जिले में मलेरिया रोकथाम हेतु विगत तीन वर्षों में व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है- वर्ष 2012 में भोपाल एवं सीहोर जिले में मलेरिया, डेंगू नियंत्रण का अभियान संयुक्त रूप से भोपाल जिले से संचालित हुआ है, क्योंकि मलेरिया, डेंगू नियंत्रण हेतु

सीहोर जिले में मलेरिया कार्यालय नहीं था। अतः सीहोर का व्यय भोपाल जिले के व्यय में सम्मिलित है तथा वर्ष 2012 में व्यय रु. 53471280, सीहोर जिले में वर्ष 2013 में रु. 989025/- एवं वर्ष 2014 के रु. 2183951/- व्यय हुआ है। राशि जिला मलेरिया अधिकारी को दी जाती है, जिनके द्वारा समस्त अस्पतालों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। (घ) म.प्र. में 01 जनवरी 2015 से दिनांक 21/02/2015 तक स्वाइन फ्लू से 109 मौतों की सूचना प्राप्त हुई है एवं 565 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं।

पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति/फीस

18. (*क्र. 594) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इंदौर एवं भोपाल जिलों में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान निजी महाविद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति/फीस दी गई? (ख) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/मेडीकल/नर्सिंग/बी.एड./एम.बी.ए./बी.ए./एम.ए./अन्य प्रकार के) करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है? (ग) क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के पिछड़ा वर्ग में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान कमी की गई है? अगर हाँ, तो किस कारण से?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 12 वीं कक्षा के बाद के कोर्स हेतु (इंजीनियरिंग/मेडीकल/नर्सिंग/ बी.एड./एम.बी.ए./बी.ए./एम.ए./अन्य प्रकार के) पाठ्यक्रमों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति संशोधित नियम-2013 अनुसार फीस उसी सीमा में दी जाती है जो किसी शासकीय संस्था में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर दी जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में वर्गवार स्वीकृत छात्रवृत्ति की दरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं।

विद्यालय की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना

19. (*क्र. 2079) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अतां. प्रश्न क्रं. 375, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 के उत्तर में

प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था कि नामली में 40 दुकानें, शामगढ़, पिपलिया मण्डी में दुकान तथा नीमच में शा.बा.उ.मा.वि. की विद्यालय भूमि पर दुकानें बना कर नगर निकाय द्वारा बेच दी गई, जो उत्तर अनुसार वैधानिक नहीं है? इन दुकानों को विद्यालय समितियों को पुनः सौंपने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में संदर्भित अतिक्रमित दुकानों के निर्माण के समय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर निर्माण कार्य रूकवाने हेतु आग्रह किया गया था? यदि हाँ, तो तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टरों को विद्यालय की जमीनों को मुक्त कराने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) उक्त प्रश्न के उत्तर में अतिक्रमित दुकानों एवं 143 विद्यालयों की भूमि को कब तक मुक्त करा लिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) दुकानों का निर्माण करने से पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग, जिला स्तर पर कलेक्टर एवं अन्य स्तर से शासन की अनुमति नहीं ली गई थी। (ख) प्रत्याशा में दुकानों के निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है। प्रकरणवार पूर्ण विवरण भेजने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। जानकारी प्राप्त होने पर ही उचित कार्यवाही संभव है। (ग) नियमित रूप से जिला कलेक्टर्स को समुचित निर्देश दिये जाते रहे हैं।

हेडस्टार्ट योजना का अनियोजित क्रियांवयन

20. (*क्र. 1403) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मिडिल स्कूलों के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा दिलाये जाने हेतु हेडस्टार्ट योजना किस शिक्षा सत्र से प्रारंभ हुई थी? इस योजना के तहत सागर संभाग के किन-किन जिलों के कितने-कितने मिडिल स्कूलों को हेडस्टार्ट योजना के लिये चिन्हित किया जाकर कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये थे? (ख) क्या वर्तमान में उक्त हेडस्टार्ट योजना के तहत मिडिल स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को विभागीय अमले की उदासीनता के कारण, कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध न होने से तथा कम्प्यूटर खराब हो जाने से कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी जा पा रही है? योजना पूर्णतया धराशायी हो चुकी है? (ग) यदि हाँ, तो शासन की अति महत्वाकांक्षी, बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जाने वाली योजना पर कम्प्यूटर क्रय करने में लाखों रूपयों का व्यय व्यर्थ हो गया है और बच्चे भी कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित हो गये हैं? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (घ) यदि नहीं, तो वर्तमान में सागर जिले में चयनित हेडस्टार्ट मिडिल स्कूल केन्द्रों में से कौन कौन से हेडस्टार्ट केन्द्रों में कम्प्यूटर सही हालत में संचालित हैं तथा किन-किन कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा कितने-कितने बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) हेडस्टार्ट योजना सत्र 2000-01 से प्रारम्भ हुयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में हेडस्टार्ट केन्द्र के संचालन हेतु भारत सरकार से हेडस्टार्ट आकस्मिक निधि की राशि अप्राप्त होने के कारण हेडस्टार्ट के संचालन में कठिनाई आ रही है। 67 हेडस्टार्ट केन्द्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति तथा 385 कम्प्यूटर के विरुद्ध 144 कम्प्यूटर खराब होने के कारण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। (ग) भारत सरकार से हेडस्टार्ट आकस्मिक के अप्राप्त होने की वजह से वर्ष 2015-16 की सर्व वार्षिक कार्ययोजना में राशि का प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया जा रहा है कोई उत्तरदायी नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।

बिना जाँच के अमानक दवाओं का मरीजों को वितरण

21. (*क्र. 750) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की दवा क्रय नीति के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्नांकित दिनांक तक राज्य स्तर से कितने प्रकार की दवाओं के क्रय आदेश किस-किस कंपनी को कितनी-कितनी कीमत के जारी किए गए? वर्षवार बतावें। (ख) क्या क्रय की जाने वाली दवा के प्राप्त होने पर उन दवाओं की जाँच राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रयोगशालाओं में कराई जाकर क्रय दवाओं का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में क्रय की गई दवाओं में कितनी दवाओं की गुणवत्ता की जाँच किस-किस प्रयोगशाला से कराई गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कराई गई जाँच में कितनी दवाएँ अमानक स्तर की पाई गई? क्या जाँच रिपोर्ट आने से पूर्व ही उक्त दवाओं का वितरण मरीजों को कर दिया गया एवं प्राप्त अमानक दवाओं के देयकों का भुगतान भी संबंधित प्रदायकर्ता कंपनी को कर दिया गया? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संदर्भ में अमानक दवाओं की सप्लाई एवं गलत भुगतान के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाकर संबंधितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क), से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परियोजना क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

22. (*क्र. 2762) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना को 275 (1) अंतर्गत विभाग द्वारा कितना आवंटन प्रदान किया गया था? (ख) यदि आवंटन प्रदाय

किया गया था, तो परियोजना क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से कार्य विकासखण्डवार स्वीकृत किये गये थे? (ग) यदि कार्य स्वीकृत किये गये हैं, तो उक्त कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन सा विभाग है एवं वर्तमान में कार्यों की क्या स्थिति है एवं वर्तमान तक स्वीकृत कार्यों पर कितना व्यय हुआ है? (घ) विकासखण्ड वार विस्तृत जानकारी दें। यदि कार्य अपूर्ण है तो क्या कारण हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रु. 415.09 लाख का आवंटन प्रदान किया गया। (ख) वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-चार से सात अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-नौ अनुसार है।

जन-जातियों हेतु विकास के कार्यों में अनियमितता

23. (*क्र. 2140) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में बैगा, भारिया, पनिका, सहरिया, भील, अगरिया आदि जन-जातियां निवासरत हैं? वर्ष 2003 के उपरांत इनके संवर्धन, संरक्षण व विकास हेतु कौन-कौन सी योजनायें बनाकर कार्य किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित जनजातियों के समुचित विकास व संरक्षण संवर्धन हेतु केंद्र व राज्य से वर्षवार कितनी-कितनी राशि किस प्रयोजन हेतु जिलावार प्राप्त हुई? (ग) क्या उक्त अवधि में संबंधित जिलों में राशि के व्यय व कार्यों में अनियमितता को लेकर विभाग/शासन/संबंधित कलेक्टरों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतवार जाँच, परिणाम व निराकरण की स्थिति बतावें। (घ) संरक्षण सह विकास योजना अंतर्गत व भारिया विकास परियोजना में अनियमितता की जाँच किन-किन जिलों में चल रही हैं? अब तक जाँच के परिणाम क्या रहे हैं? अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही न होने व आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा संरक्षण दिये जाने के क्या कारण हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है तथा शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) जिला बालाघाट में वर्ष 2009-10 स्वीकृत विशेष पिछड़ी जनजाति के आवासगृह की जाँच आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा की जा रही है। जाँच उपरांत दायित्व निर्धारित किया जावेगा। शेष अन्य जिलों के संबंध में जानकारी संकलित की जा रही है।

कंपनियों पर अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों के लंबित भुगतान

24. (*क्र. 3022) श्री बाला बच्चन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रतलाम जिले में दिनांक 01.01.13 से 31.01.15 तक कंपनी छोड़ कर गए/निकाले गए अधिकारियों/कर्मचारियों एवं श्रमिकों का कितने समय का वेतन व अन्य भत्ते का भुगतान संबंधित कंपनियों पर बाकी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन कंपनियों में ऐसे भुगतान शेष नहीं हैं, उनके द्वारा स्व-प्रमाणित पत्र की प्रति देवें। जिन कर्मचारियों के देयक शेष हैं उन कंपनियों के नाम, कर्मचारी जिसका भुगतान बाकी है नाम, राशि सहित बतावें। (ग) शासन इन कर्मचारियों/अधिकारियों/श्रमिकों का भुगतान कब तक करवायेगा? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले संबंधित जिलों के अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) प्रश्नांकित अवधि में देवास जिले में एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड देवास कंपनी द्वारा 17 श्रमिकों को सेवापृथक किया गया है। इन श्रमिकों की कुल बकाया वेतन राशि रु. 8, 73, 256/- है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। रतलाम जिले में खेतान केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड यूनिट खेतान एग्री रतलाम के 41 कर्मचारी काम छोड़कर गये हैं, जिन्हें वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान हो चुका है। कोई लंबित भुगतान शेष नहीं है। (ख) देवास जिले में स्थित एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। रतलाम स्थित खेतान केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर यूनिट खेतान एग्री रतलाम द्वारा दिया गया स्वप्रमाणित पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। (ग) देवास जिले में स्थित एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड देवास के प्रबंधन के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है :- 1. श्रमिकों के बोनस भुगतान नहीं करने के संबंध में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में आपराधिक अभियोजन प्रकरण दायर। 2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत बगैर अनुमति संस्थान बंद करने के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आपराधिक अभियोजन प्रकरण दायर। 3. पांच श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उनके अवैध सेवापृथक्करण तथा अन्य देय सहायता संबंधी प्रकरण श्रम न्यायालय को न्याय निर्णायार्थ संदर्भित किये गये। 4. अन्य श्रमिकों के वेतन एवं भत्तों आदि के भुगतान हेतु वैधानिक कार्यवाही प्रचलित। प्रश्नांश ख के उत्तर के प्रकाश में रतलाम के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश ग के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय सुविधा एवं पद पूर्ति

25. (*क्र. 2303) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं मिनि स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं सूची देवें एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या-क्या चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सामुदायिक स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वा. केन्द्र एवं मिनि स्वा. केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? केन्द्रवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उक्त पदों में कौन-कौन कब से पदस्थ हैं और कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उक्त पदों को भरने हेतु शासन स्तर पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

निजी उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि

1. (क्र. 220) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन ने निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है? यदि कर दी है, तो नागदा, जिला उज्जैन में स्थित उद्योगों में इस नियम का पालन हो रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) नागदा, जिला उज्जैन में स्थित उद्योगों में सेवा निवृत्ति आयु बढ़ाने के पश्चात कितने कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया गया है? जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया गया है, उन कर्मचारियों को वापस काम पर रखवाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) नियम लागू होने के पश्चात इस नियम का पालन नहीं करने वाले उद्योगों पर (नागदा, जिला उज्जैन स्थित) शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। नागदा जिला उज्जैन में स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (स्टेपल फायबर डिवीजन एवं इंजीनियरिंग डिवीजन) द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा इस बाबद विधिक प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है। (ख) ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज नागदा द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेश में सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.10.2014 द्वारा लागू मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अध्यादेश, 2014 के पश्चात प्रमाणित स्थायी आदेशों में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने का प्रावधान लागू हुआ है। इसके पश्चात 31 जनवरी 2015 तक ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (स्टेपल फायबर डिवीजन) नागदा द्वारा 18 तथा ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (इंजीनियरिंग डिवीजन) द्वारा 1 कर्मचारी को निर्धारित आयु के पूर्व सेवानिवृत्त किया गया है। उक्त समस्त कर्मचारियों को निर्धारित आयु के पूर्व सेवानिवृत्त करने की वैधता तथा इस संबंध में उन्हें देय सहायता संबंधी प्रकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद को रूप में श्रम न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 20.02.2014 को अधिनिर्णयार्थ संदर्भ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.06.2014 द्वारा मानक स्थायी आदेशों में सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से संशोधित कर 60 वर्ष की गयी थी किन्तु ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा इसका पालन नहीं किये जाने के कारण सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, उज्जैन द्वारा पूर्व में ही दिनांक 07.08.2014 को प्रबंधन के विरुद्ध मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1961, के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु 2 आपराधिक अभियोजन प्रकरण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायालय उज्जैन में दायर किये जा चुके हैं। मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अध्यादेश, 2014 के दिनांक 25.10.2014 से लागू

होने के पश्चात निर्धारित आयु के पूर्व सेवानिवृत्त किये कर्मचारियों के संबंध में श्रम कार्यालय, उज्जैन द्वारा दिनांक 23.01.2015 एवं दिनांक 20.02.2015 को निरीक्षण किये गये हैं। जिनमें पाये गये उल्लंघन के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त श्रम कार्यालय, उज्जैन द्वारा इस संबंध में 4 श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कार्यवाही पंजीबद्ध कर ली गयी है। (ग) वैधानिक कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश (ख) के उत्तर में दी गई है।

मझगंवा, जि. सतना में पदस्थ चिकित्सक के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण

2. (क्र. 291) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय चिकित्सालय-मझगंवा, जिला सतना में पदस्थ चिकित्सक डॉ. तरुण कांत त्रिपाठी को भोपाल के न्यायालय ने अपराधिक प्रकरण क्र. आर.टी.11512/08 में दिनांक 17 जुलाई 2014 को दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है? (ख) क्या उक्त चिकित्सक ने सतना की एक कोर्ट में एक अन्य अपराधिक प्रकरण क्रं. 3003/14 में दि. 27 अक्टूबर 2014 को कोर्ट में जमानत व मुचलका देकर जमानत प्राप्त की है? (ग) क्या उक्त चिकित्सक ने कंडिका (क) और (ख) में वर्णित अपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही की जानकारी से संबंधित विभाग को तत्समय अवगत कराया है? (घ) यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कब-कब क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। डॉ. तरुण कांत त्रिपाठी, पुलिस अभिरक्षा में नहीं रहे हैं एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल ने प्रकरण क्रमांक आर.टी. 11512/08 में दिनांक 17 जुलाई 2014 को 02 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया परंतु दशम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा सश्रम कारावास की सजा को अपील के निराकरण तक स्थगित रखा है। अतः डॉ. त्रिपाठी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न्यायालयीन निर्णय आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति

3. (क्र. 387) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र कसरावद तहसील मुख्यालय वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही भूमि का चयन कर अस्थाई स्कूल प्रारंभ करने के लिए भवन का भी चयन करने के उपरांत भी उक्त विद्यालय को प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है? कारणों का उल्लेख करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही समय रहते पूर्ण नहीं करने में कौन-कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी है, के

खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो बतायें? नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें? (ग) उक्त विद्यालय कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा, दिनांक सहित जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने का संबंध मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में न होकर केन्द्र शासन के क्षेत्राधिकार में है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भर्ती परीक्षा का आयोजन

4. (क्र. 419) कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2013 में राज्य शिक्षा सेवा आयोग के अंतर्गत ऐरिया एज्युकेशन ऑफीसर के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी? इसमें शामिल होने की योग्यताएं/अर्हताएँ क्या-क्या थीं? क्या अब इसमें कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और क्या? (ख) 24.8.2013 की स्थिति में जबलपुर संभाग में ऐसे कितने उच्च

श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक/अध्यापक हैं, जिनको सेवा में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण कार्य का अनुभव है? जिलेवार संख्यावार जानकारी दें? इनमें से कितने परीक्षा में शामिल हुए हैं एवं कितने शामिल नहीं हुए? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 जनवरी, 2015 को जारी पत्र क्र./एफ13-24/2014/20-1 में माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं? वे क्या हैं? क्या 24.8.2013 की स्थिति में ऐसे कर्मचारी भी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके पास 24.8.2013 की स्थिति में निर्धारित योग्यताएं नहीं थीं? इनके परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और क्यों? (घ) क्या वर्तमान में परिवर्तित नियमों के अनुसार पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को परीक्षा का अवसर दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पूर्व परीक्षा को निरस्त कर नवीन परिवर्तित नियमों के अनुसार परीक्षा पुनः आयोजित करवाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब" अनुसार है। एमपी ऑन लाईन से प्राप्त जानकारी अनुसार जबलपुर परीक्षा केन्द्र में 5 वर्षों का या उससे अधिक शिक्षण अनुभव रखने वाले परीक्षार्थियों में उच्च श्रेणी शिक्षक 626, प्रधानाध्यापक 516 एवं अध्यापक 3406, ए.ई.ओ. की परीक्षा में शामिल हुये। (ग) जानकारी उत्तरांश "क" अनुसार है। निर्धारित अर्हताएँ न रखने वाले भी शामिल हुए थे। प्रकरण में विभाग स्तर पर समग्र स्थिति पर विचार प्रचलन में हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभाग स्तर पर समग्र रूप से विचार प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाना

5. (क्र. 440) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी विद्यालय खोलने हेतु विद्यालय प्रबंधक को विधिवत मान्यता प्राप्त करनी होती है? यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार अशासकीय विद्यालय खोलने हेतु क्या-क्या मापदण्ड पूरे किये जाने होते हैं? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार इन्दौर जिले में अनेक अशासकीय विद्यालय निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करते हैं और उन्हें संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो जिला प्रशासन द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान अनुसार अशासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को विद्यालय संचालन की विधिवत मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। शेषांश लोकशिक्षण संचालनालय से संबंधित। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय संचालन के मान और मानकों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लोकशिक्षण संचालनालय से संबंधित।

परिशिष्ट- "पांच"

शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्वीकृत पद

6. (क्र. 441) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत इन्दौर जिले के शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो वर्तमान में पदस्थ व्यावसायिक शिक्षक का नाम व रिक्त पद की सूची विद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र संख्या के साथ उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र नहीं हैं फिर भी इन पदों पर व्यावसायिक शिक्षक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो क्यों स्पष्ट करें व ऐसी स्थिति में विद्यालय में पदस्थ शिक्षक से क्या कार्य लिया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) 8 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्र न होने के पश्चात भी व्याख्याता कार्यरत है। विद्यालय में पदस्थ इन व्याख्याताओं से योग्यतानुसार अन्य विषयों का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।

परिशिष्ट- "छः"

ढाबा (भोजनालय) की सामग्री की जाँच

7. (क्र. 509) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र भौरा से बैतूल तक कितने ढाबा (भोजनालय) संचालित है? (ख) क्या खाद्य सामग्री की जाँच की जाती है? यदि हाँ तो विगत एक वर्ष में खाद्य निरीक्षण द्वारा कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? (ग) कितने ढाबा शाकाहारी तथा मांसाहारी चल रहे हैं? क्या ढाबा में अवैध शराब परोसी जाती है? (घ) क्या ढाबा में शौचालय व्यवस्थायें हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र, भौरा से बैतूल तक 26 ढाबा (भोजनालय) संचालित है। (ख) जी हाँ। विगत एक वर्ष में खाद्य निरीक्षकों द्वारा 8 निरीक्षण एवं 2 नमूने लेकर जाँच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये, जाँच के उपरांत नमूने मानक स्तर के होने के कारण प्रकरण दर्ज नहीं किये गये। (ग) 26 ढाबों में 19 महासारी एवं शाकाहारी तथा 07 शाकाहारी ढाबा चल रहे हैं। जाँच के समय अवैध शराब परोसी जा रही है अथवा नहीं यह विषय विभाग से संबंधित नहीं है। (घ) शौचालय की 4 ढाबों में व्यवस्था है।

अवैध कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

8. (क्र. 601) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि म.प्र. के जिला चिकित्सालयों में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों में साफ-सफाई की निविदाओं में क्या यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/प्रा.लिमिटेड फर्म/सोसायटी एन्ड फर्म/लिमिटेड कम्पनी फर्म ही निविदाओं में भागीदारी कर सकती थी? अगर हाँ तो प्रदेश के किन-किन जिला चिकित्सालयों में इस नियम का उल्लंघन हुआ? जिलेवार जानकारी दें? (ख) क्या प्रोपराइटर शिप फर्म का अधिनियम 1908 है? पार्टनरशिप फर्म का एक्ट 1932 है? प्रा.लि.कम्पनी का एक्ट 1956 है? क्या निविदा शर्तों में यह उल्लेखित किया गया था? अगर हाँ, तो प्रोपराइटर शिप/पार्टनरशिप फर्म/प्रा.लि./लिमिटेड फर्म के अधिपत्य की जानकारी क्या विभाग को उपलब्ध कराई गई? अगर हाँ तो क्या दस्तावेज विभाग में जमा किये गये? (ग) नगर पालिक निगम 1956 की धारा 366 एवं 427 के अन्तर्गत जो पंजीकृत है उन्हें विभाग (स्वास्थ्य) कैसे प्रोपराइटर मान सकता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के निर्देशों में नहीं बल्कि संचालनालय द्वारा जारी मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेंट में उपरोक्त निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार यह निर्देश दिये गये थे कि मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेंट के अनुसार जिला स्तर पर खुली निविदा जारी कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चिकित्सालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था की जाये। टेण्डर डॉक्यूमेंट की शर्त के अनुसार

कोई फर्म (प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप)/कम्पनी (प्रायवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड), सोसायटी/ट्रस्ट जो विहित भारतीय कानूनी विधान के तहत पंजीकृत हो, ही निविदाओं में भागीदारी कर सकती है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जी नहीं। पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 नहीं बल्कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है तथा प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी का एक्ट 1956 नहीं बल्कि कम्पनीज एक्ट 1956 है। निविदा शर्तों में उल्लेख किया गया था कि कोई फर्म (प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप) /कम्पनी (प्रायवेट लिमिटेड या पब्लिकलिमिटेड), सोसायटी/ट्रस्ट जो विहित भारतीय कानूनी विधान के तहत पंजीकृत हो, निविदाओं में भागीदारी कर सकती है। जी नहीं। संबंधित जानकारी विभाग/संचालनालय स्तर पर नहीं बल्कि संबंधित जिला स्तर के निविदाकर्ता अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है। अतः संबंधित जानकारी संचालनालय स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई जाती। (ग) नगर पालिक निगम 1956 की धारा 366 एवं 427 के अंतर्गत जो पंजीकृत हैं उन्हें भी प्रोपराइटरशिप के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, बशर्ते टेण्डर डॉक्यूमेंट की अन्य शर्तों की पूर्ति निविदादाता द्वारा पूरी की जावे।

देवास जिले में कर्मचारियों की पदोन्नति

9. (क्र. 716) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रतिवर्ष की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) क्या देवास जिले के शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, तथा वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है? (ग) विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं? क्या टायपिंग व कम्प्यूटर का ज्ञान होने पर प्राथमिकता दी जाती है या नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ख) विभागान्तर्गत जिला देवास अंतर्गत वर्ष 2015 के रिक्त पदों के लिए पदोन्नति पूर्व की आवश्यक कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य योग्यता हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं 05 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। पदोन्नति प्रक्रिया में टायपिंग व कम्प्यूटर का ज्ञान होने पर प्राथमिकता दिए जाने संबंधी कोई प्रावधान नियमों में नहीं है।

प्रदेश में डेंगू मलेरिया, स्वाइन फ्लू में मौतों के संबंध में

10. (क्र. 751) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के परि. अतां. प्रश्न (क्रमांक 234) दिनांक 12.12.14 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में बताया गया है कि दिनांक 1 जनवरी 14 से 15 नवम्बर 14 की अवधि में प्रदेश में मलेरिया के 84494 प्रकरण, स्वाइन फ्लू

के 13 पाजिटिव प्रकरण, डेंगू के 1609 प्रकरण प्रकाश में आए? उक्त अवधि में मलेरिया से 23, स्वाईन फ्लू से 7, डेंगू से 12 मरीजों की मृत्यु हुई? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 16 नवम्बर 14 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में मलेरिया, स्वाईन फ्लू, डेंगू से पीडित कितने मरीज चिन्हित किए गए? कितने मरीजों की मृत्यु इन बीमारियों के कारण हुई? क्या यह सही है कि श्योपुर एवं मुरैना जिले में डेंगू एवं स्वाईन फ्लू की जाँच की सुविधा नहीं होने से ब्लड सैम्पल ग्वालियर भेजे जाते हैं एवं रिपोर्ट आने तक मरीज गंभीर रूप से पीडित होकर मृत्यु तक हो जाती है? यदि हाँ, तो क्या विभाग श्योपुर एवं मुरैना जैसे छोटे जिलों में भी इन बीमारियों की जाँच की सुविधा उपलब्ध करायेगा? (ग) प्रदेश में कौन-कौन से जिले मलेरिया, डेंगू एवं स्वाईन फ्लू की दृष्टि से हाई रिस्क जोन में सम्मिलित किए गए हैं? इन जिलों में इन बीमारियों की रोकथाम हेतु क्या-क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? (घ) चंबल संभाग में 15 नवम्बर 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक 0-6 वर्ष एवं 06-12 वर्ष तक के कितने बच्चों की मृत्यु हुई जिलेवार बतावे? साथ ही मृत्यु के क्या कारण हैं, जैसे-मीजल्स, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, स्वाईन फ्लू एवं अन्य बीमारी (नाम सहित) तथा कुपोषण? कृपया पृथक-पृथक जिलेवार जानकारी योग सहित दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) 16 नवम्बर से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में मलेरिया के 13464, स्वाईन फ्लू 677, डेंगू से 586 पीडित मरीज चिन्हित किए गए हैं। मलेरिया से 03, स्वाईन फ्लू से 125 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है एवं डेंगू से कोई मृत्यु की जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है। श्योपुर एवं मुरैना जिले में वर्तमान में डेंगू एवं स्वाईन फ्लू की जाँच की सुविधा उपलब्ध न होने से ब्लड सैम्पल ग्वालियर भेजे जाते हैं। शीघ्र ही मुरैना जिले में डेंगू की जाँच की व्यवस्था की जा रही है। श्योपुर जिले में एलाईजा रीडर वर्तमान में उपलब्ध न होने से डेंगू की जाँच की व्यवस्था की जाना संभव नहीं हो रहा है। चूँकि डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है एवं इसमें लक्षण के आधार पर ही उपचार दिया जाता है। जाँच के पश्चात यदि डेंगू सत्यापित होता है तो भी उपचार वही होता है। स्वाईन फ्लू की जाँच बायो सेफ्टी लेवल दो लैब में ही की जाती है। इस तरह की लैब जिला स्तर पर अपग्रेड नहीं है, इसलिए वर्ष 2009 से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित दो प्रयोगशाला क्रमशः रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ग्वालियर तथा भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद, जबलपुर को स्वाईन फ्लू सैम्पल जाँच के लिए भेजे जाते रहे हैं एवं 22 फरवरी 2015 से एम्स भोपाल में भी स्वाईन फ्लू सैम्पल की जाँच की जा रही है, इन प्रयोगशाला द्वारा 24 घण्टे के भीतर जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है एवं मरीजों का इलाज सैम्पल लेने के बाद तत्काल शुरू कर दिया जाता है। जिला मुरैना एवं श्योपुर की लैब को स्वाईन फ्लू की जाँच के लिए अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) प्रदेश में झाबुआ, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, अलीराजपुर, मण्डला, बैतूल, होशंगाबाद, भिण्ड एवं अनूपपुर मलेरिया के हाईरिस्क, जिला इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर,

ग्वालियर, सागर, मण्डला, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, रायसेन एवं बैतूल डेंगू के हाईरिस्क तथा जिला इंदौर एवं भोपाल से ही स्वाईन फ्लू के प्रकरण अधिक प्रकाश में आए हैं इसलिए इन्हें स्वाईन फ्लू के हाईरिस्क जोन में चिन्हित किया गया है। मलेरिया से प्रभावित जिलों में आशा स्तर तक जाँच हेतु रैपिड डायग्नोस्टिक किट प्रदाय की गई है, जिससे ग्राम में ही जाँच होकर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। एंटी मलेरियल दवाईयां उपचार हेतु सभी स्तर ग्राम आरोग्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज पर उपलब्ध हैं। मलेरिया के संक्रमण काल में प्रभावित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कीटनाशी दवाई का छिड़काव भारत सरकार की नीति के अनुसार माह जून से अक्टूबर में किया जाना तय किया गया है। डेंगू के नियंत्रण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है, अभी से मच्छरों की उत्पत्ति घरों में रोकने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार प्रारंभ कर दिया गया है। जिलों में डेंगू के उपचार के लिए संभाग स्तर पर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ये गतिविधियां निरंतर रखी जावेंगी। जिलों में डेंगू के नियंत्रण हेतु कीटनाशी छिड़काव की व्यवस्था की गई है। स्वाईन फ्लू के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जिला चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज, अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में सर्दी-जुकाम (स्वाईन फ्लू एच 1 एन 1) काउंटर बनाए गए हैं, जो 24x7 घण्टे कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त सभी मेडीकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू (एच 1 एन 1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आईसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेडीकल कॉलेज अस्पतालों में औषधियां/सामग्रियां आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी गई हैं। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम/हैल्प लाइन नं. सामान्य जन मानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए। प्रचार प्रसार (मशाल रैली, होर्डिंग्स, वाल पेंटिंग्स, पम्पलेट्स, रेडियो जिंगल्स, टी. व्ही. स्कॉल) के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वाईन फ्लू जागरूकता के लिए की गई अपील समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। (घ) चंबल संभाग में 15 नवम्बर 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक 0-6 वर्ष एवं 06-12 वर्ष तक के बच्चों में मीजल्स, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, स्वाईन फ्लू एवं कुपोषण व अन्य बीमारी की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- "सात"

प्राचार्य सरस्वती कन्या उ.मा.वि. गोरमी के प्राचार्य विरुद्ध कार्यवाही

11. (क्र. 1079) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्र. 1583/1093 2013/20-4 दिनांक 13.12.2013 श्री रामबहादुर सिंह भदौरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रश्नांश दिनांक तक क्या की गई? (ख) माननीय उच्च न्यायालय

जबलपुर अपील नं. 327 के अनुसार प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रथम सूचना प्रतिवेदन धारा 157 क्र. 4602/15 दिनांक 30.01.2014 के अनुसार आ.अ. प्रकोष्ठ भोपाल में प्रश्नांश दिनांक तक क्या समुचित कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित व्यक्ति के विरुद्ध आज तक कार्यवाही नहीं की गई है? कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभाग के पत्र दिनांक 13.12.2013 द्वारा कलेक्टर भिण्ड को प्रकरण की जाँच हेतु लिखा गया है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त होने से विभागीय पत्र दिनांक 24.2.2015 द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) रिट याचिका क्रं. 327/2007 मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में नहीं अपितु मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में दायर की गई। उक्त याचिका में पारित निर्णय के विरुद्ध एस.एल.पी.क्रं. 9682/2009 दायर की गई, जो कि वर्तमान में सिविल अपील में परिवर्तित होकर मान. उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मान. उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 8.3.2010 के परिपालन में याचिका से संबंधित विद्यालय के संचालन को यथास्थिति बनाये रखते हुए कार्यरत पात्र शिक्षकों/कर्मचारियों को संविदा पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश का संबंध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल से होने के कारण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल से प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा रही है। (घ) प्रकरण की जाँच कलेक्टर जिला भिण्ड को सौंपी गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जाँच के निष्कर्षों के आधार पर सक्षम स्तर से यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति

12. (क्र. 1216) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ौदा का उन्नयन सन्, 2005 में हुआ था? तभी से ही यह केन्द्र वर्षों पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के छोटे भवन में ही संचालित हो रहा है? (ख) क्या यह भी सच है कि उक्त भवन में जगह के अभाव में चिकित्सकों के बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं है? 30 बिस्तरीय सुविधा से मरीज वंचित बने हुए हैं? भर्ती मरीज गैलरी में नीचे लेटकर उपचार कराते हैं? इसके अतिरिक्त भी कई अन्य अव्यवस्थाएं केन्द्र में विद्यमान हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त अव्यवस्थाओं के मद्देनजर नवीन भवन का कोई प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार करके शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हाँ, तो उसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार करवाएगा एवं उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर वर्ष, 2014-15 के वार्षिक बजट में इस हेतु प्रावधान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोदा का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडौदा का वर्ष 2006 में उन्नयन हुआ था। जी हाँ। (ख) जी नहीं, चिकित्सकों के बैठने की व्यवस्था अलग कमरों में कराई गई है। जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडौदा में 10 पलंग की सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ। (ग) जी नहीं। विभाग द्वारा भवनों के निर्माण का प्राक्कलन तैयार करने हेतु आर्कीटेक्ट के चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। आर्कीटेक्ट के चयन उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोदा के नवीन भवन का प्राक्कलन तैयार कराकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्न भाग (ग) के उत्तर में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ट्रामा सेंटर की स्थापना

13. (क्र. 1316) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिविल अस्पताल ब्यावरा में चिकित्सा संसाधनों के अभाव में अति गंभीर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को भोपाल या इंदौर रेफर किया जाता है जिससे अधिकतम पीड़ित व्यक्तियों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है? (ख) यदि हाँ तो क्या शासन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को समय पर त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से ब्यावरा में ट्रामा सेन्टर स्थापित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। सिविल अस्पताल ब्यावरा से अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2014 तक एल.एस.ए/वी.एल.एस.ए. से रेफर 62 प्रकरणों में से केवल 03 प्रकरण के रास्ते में वायटल रिकार्ड नहीं हो रहे थे। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय हाईस्कूल गांगाहोनी का उन्नयन

14. (क्र. 1317) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विकासखण्ड ब्यावरा के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल गांगाहोनी तहसील मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु अनेक योजनाएँ संचालित हैं किन्तु ग्राम गांगाहोनी से निकटतम हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी भी लगभग 20 कि.मी. है ऐसी स्थिति में सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष इस विद्यालय से हाईस्कूल पास होकर अगली शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? ग्रामीण परिवेश एवं गरीबी के कारण संबंधित विद्यार्थियों के पालक हायर सेकेण्डरी एवं आगे की शिक्षा के लिए शहरों में नहीं भेज पाते हैं? (ख) क्या शासन ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य

को देखते हुये आगामी शैक्षणिक सत्र के पूर्व ग्राम गांगाहोनी के हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में प्रौन्नत करेगा? यदि नहीं तो ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य के लिये कौन जिम्मेदार है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय हाईस्कूल गांगाहोनी से निकटस्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनवास 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रति वर्ष सीमित संख्या में ही उन्नयन हो पाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश स्काउट संघ में आर्थिक अनियमितता

15. (क्र. 1364) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश स्काउट संघ में भारी आर्थिक अनियमितता की शिकायत कई बार हुयी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुयी? यदि हाँ तो क्या 31.1.15 की स्थिति में कोई जाँच की जा रही है? यह जाँच कब प्रारंभ हुई और जाँचकर्ता कौन है? (ख) क्या इस आर्थिक अनियमितता की जाँच आर्थिक अपराध अनुसंधान को नहीं दी जा सकती? वहाँ जाँच व्यवस्थित हो सकेगी? (ग) वर्तमान में 31.1.15 की स्थिति में उसके प्रदेश पदाधिकारियों के नाम और उनकी पद ग्रहण दिनांक बतावे? वे कब तक पद पर बने रह सकते हैं? पदावधि कितनी निर्धारित है? (घ) प्रदेश कार्यकारिणी किन आधारों पर और किस इकाई द्वारा भंग किये जाने का प्रावधान है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जी हाँ। भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक डी 5-18/3089/2014-15, दिनांक 02.01.2015 द्वारा भी जाँच दल गठित कर माह जनवरी, 2015 में जाँच प्रारंभ की गई है। भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा गठित जाँच दल में निम्नांकित पदाधिकारी है - 1. श्री के. सुकुमारा, संयुक्त संचालक, अध्यक्षक समिति, 2. श्रीमती दर्शना पावरकर, संयुक्त सचिव, 3. श्री कृष्ण स्वामी आर. उप संचालक प्रशासन (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर में वर्णित राज्य शासन एवं राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जाँच कराये जाने के कारण आर्थिक अपराध अनुसंधान को जाँच सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है। (ग) वर्तमान में प्रदेश पदाधिकारियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार** है। इन पदाधिकारियों का पद ग्रहण दिनांक 24.01.2013 है। इनकी पदावधि 03 वर्ष है। (घ) यदि प्रदेश कार्यकारिणी एवं प्रदेश इकाई भारत स्काउट एवं गाइड की प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य न करे या फिर कोई गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाए तो यह सिद्ध पाये जाने पर भारत स्काउट एवं गाइड राज्य परिषद दिनांक 19.11.2012 में लिये निर्णय एवं पारित नियमों के नियम 14 (4) (T) (1) के प्रावधान अनुसार भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट गाइड नई दिल्ली द्वारा इकाई भंग किये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट- "आठ"

उपसंचालक के रिक्त पद की पूर्ति

16. (क्र. 1365) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पदोन्नति हेतु वर्ष में दो बार डी.पी.सी. का प्रावधान है अगर पद रिक्त हो तो? यदि हाँ, तो संचालनालय में अपर संचालक के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त है? (ख) पद रिक्त होते हुये भी डी.पी.सी. नहीं करने का कारण बतावें क्या डी.पी.सी. लम्बे समय से नहीं करने के कारण कई पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये इससे क्या यह परिलक्षित नहीं होता है कि जानकर के उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया? (ग) वर्तमान में अपर संचालक की डी.पी.सी. हेतु कितनी बार 2014-15 में पी.एस.सी. द्वारा तारीख दी गई और कितनी बार अधिकारी उपस्थित नहीं हुये और इस बीच कौन-कौन पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये क्या जान बूझकर उन्हें वंचित किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। लोक शिक्षण संचालनालय में अपर संचालक का 01 पद दिनांक 01 सितम्बर 2014 से रिक्त है। (ख) जी नहीं। दिनांक 01-01-2014 की स्थिति में तथा दिनांक 31-12-2014 तक के रिक्त होने वाले अपर संचालकों के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08 जनवरी 2015 को आयोजित हो चुकी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अपर संचालक की डीपीसी हेतु पीएससी द्वारा वर्ष 2014-15 में एक बार दिनांक 02.12.2014 को तारीख दी गई। उक्त दिनांक को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में पेशी पर विभागीय वरिष्ठतम अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण पीएससी द्वारा डीपीसी की आगामी निर्धारित तारीख 08.01.2015 पर बैठक आयोजित हुई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रेरक पद पर पात्र आवेदक का चयन

17. (क्र. 1381) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल के पत्र क्रं./श.श.के/साक्षर भारत/2012/9274 दि. 27.09.2012 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर प्रति पंचायत प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के अंतर्गत दो पद स्वीकृत किये गये थे? आदेश की प्रति दी जावे? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त स्वीकृत दो पदों में से एक पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा एक पद प्रेरक महिला होना अनिवार्य किया गया था? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो सतना जिले के अंतर्गत जनपद पंचायतों के माध्यम से चयनित व्यक्तियों की प्रौढ़ शिक्षा केंद्रवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या जनपद पंचायत रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरक भर्ती की अंतिम चयन सूची वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत गजास के रामू चर्मकार पिता लालमन चर्मकार के कंप्यूटर अनुभव सहित कुल अंक 58.27 थे, लेकिन सौखीलाल कोल जिसके कुल अंक 55.8 थे, को गलत तरीके से चयनित किया गया, जबकि पात्र आवेदक रामू चर्मकार को समस्त अभिलेखों की पावती (कंप्यूटर

प्रमाण पत्र) दी गई थी? क्या इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आदेश की प्रति की "जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है।" (ख) जी हाँ। (ग) "जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार है।" (घ) जनपद पंचायत रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरक भर्ती की अंतिम चयन सूची वर्ष २०१२ -१३ से संबंधित प्रकरण की जाँच हेतु अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय दल गठित किया गया है, जाँच उपरांत यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

प्रचलित अधिकारों को लेखबद्ध किया जाना

18. (क्र. 1436) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अता. प्रश्न क्रमांक 1870 दिनांक 18 जुलाई 2014 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया कि धारा 4 (1) में अधिसूचित भूमि में से, वन अधिकार अधिनियम 2006 में परिभाषित वन भूमि की श्रेणी में आने वाली भूमि पर निस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने की कार्यवाही प्रचलित है, की जानकारी दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल संभाग के किस जिले में अधिसूचित कितनी भूमि वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली है? इन भूमियों पर कौन-कौन से अधिकार एवं प्रयोजनों की जाँच उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में वर्तमान में कर रहे हैं? (ग) जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक किस उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष ने जाँच हेतु लंबित कितनी जमीनों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों को वन अधिकार कानून के अनुसार लेखबद्ध किए जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं? यदि कार्यवाही नहीं की गई हो, तो कारण बतावें? (घ) वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई भूमियों पर निस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सामुदायिक वन अधिकार पत्र कब तक वितरित कर दिए जावेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वन तथा राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। (ग) राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। (घ) वन अधिकार अधिनियम में परिभाषित सभी वन भूमियों में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

छात्रावासों एवं आश्रमों के कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

19. (क्र. 1437) श्री निशंक कुमार जैन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन श्रमायुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 2752 दिनांक 22.08.2014 को दिए निर्देश के बाद भी विदिशा जिले एवं बैतूल जिले में श्रम विभाग द्वारा छात्रावासों एवं आश्रमों में कार्यरत रसोईयां, चौकीदारों, भृत्य एवं सफाईकर्मियों को किए जा रहे भुगतान की जाँच कर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्रश्नांकित तिथि तक भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका है? (ख) विदिशा एवं बैतूल जिले में किस विभाग के द्वारा कितने आश्रम एवं कितने छात्रावास वर्तमान में संचालित है इनमें कितने चौकीदार कितने रसोईयें कितने सफाईकर्मी एवं कितने भृत्य कार्यरत हैं इन्हें गत एक वर्ष में किस दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) जिलों में शासन द्वारा गत एक वर्ष में न्यूनतम मजदूरी की क्या दर निर्धारित की गई उसके अनुसार कितने चौकीदारों कितने रसोईयें, कितने भृत्य एवं कितने सफाईकर्मियों को किस विभाग ने किन कारणों से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया ऐसे विभाग के विरुद्ध श्रम विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) छात्रावास एवं आश्रमों में कार्यरत चौकीदार, रसोईयां, भृत्य एवं सफाईकर्मी को न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं। श्रमायुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 27522, दिनांक 22.08.2014 द्वारा श्रम पदाधिकारी, बैतूल को म.प्र. के विभिन्न शासकीय विभागों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.04.2014 से प्रभावशील मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन की दरें संसूचित की गई हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) इस प्रकार की जानकारी श्रम विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ग) श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा गत 1 वर्ष की अवधि में अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु दिनांक 01.04.2014 से पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ए" अनुसार व दिनांक 01.10.2014 से पुस्तकालय में रखे अनुसार परिशिष्ट के प्रपत्र- "बी" न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई हैं, किंतु शासकीय विभागों द्वारा संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में नियोजन अधिसूचित नियोजन अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। अतः श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिये संचालित योजनाएं

20. (क्र. 1500) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2015 की स्थिति में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए विभाग की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? पात्रता मापदण्ड शर्तों का विवरण दें? (ख)

रायसेन एवं देवास जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत 01.01.13 से 31.01.15 की अवधि में कितने व्यक्ति लाभांवित हुए, योजनावार संख्या बतायें? किन-किन योजनाओं में एक भी व्यक्ति लाभांवित नहीं हुआ, तथा क्यों? (ग) माननीय मुख्यमंत्री ने उक्त वर्ग की पंचायत में क्या-क्या घोषणायें की थी उनमें से किन-किन घोषणाओं पर अभी तक क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? (घ) उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन तथा विभाग क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है?

दिनांक

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) फरवरी, 2015 की स्थिति में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के लिये विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की सूची एवं पात्रता, मापदण्ड तथा शर्तों के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) रायसेन एवं देवास जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.01.2015 तक की अवधि में योजनावार लाभांवित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एवं नियमानुसार पूर्ण आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण जिन योजनाओं में एक भी व्यक्ति लाभांवित नहीं हुआ, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04.07.2013 को आयोजित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग की पंचायत में 21 घोषणाएँ की गई थी। उक्त घोषणाओं में से 08 घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रचलित है। क्रियान्वयन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। (घ) उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन तथा विभाग नियमानुसार कार्यवाही कर रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है।

सहायक संचालक के पद की योग्यता का निर्धारण

21. (क्र. 1524) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में लागू राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के अंतर्गत सहायक संचालक लोक शिक्षण के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से एवं 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हाँ तो सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की योग्यता का मापदण्ड क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में योग्यता का मापदण्ड पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरे जाने के मापदण्ड अलग-अलग हैं तो इसका आधार क्या है? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में योग्यता का मापदण्ड अलग-अलग होने से क्या शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति ऐसे पात्रताधारी प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद से की जाती है, जिनको की प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।

सीधी भर्ती के सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता एवं अन्य मापदण्ड के निर्धारण हेतु नियमों में प्रावधान किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शिक्षक संवर्ग को अन्य संवर्ग की भांति समयमान वेतनमान का लाभ

22. (क्र. 1525) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. F-11-1/108/नियम/4/भोपाल दिनांक 17-9-2009 के अनुक्रम में राज्य के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत नियुक्त प्राचार्यों/सहायक संचालकों/ प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को भी दिये जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हाँ, तो स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नियुक्त शिक्षक संवर्गों (सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता) को भी अन्य संवर्गों की भांति समयमान वेतनमान दिया जावेगा? यदि नहीं तो राज्य के अन्य कर्मचारियों से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नियुक्त शिक्षक संवर्गों के साथ भेदभाव क्यों? यदि भेदभाव नहीं है तो उक्त लाभ शिक्षक संवर्ग को कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। सीधी भर्ती से नियुक्त प्राचार्य एवं सहायक संचालकों/प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को समयमान वेतन दिये जाने का प्रावधान है। (ख) व्याख्याता/शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाता है, इसलिए इन्हें समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है। जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है, उन्हें समयमान वेतनमान नहीं दिया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बालाघाट जिलांतर्गत आवंटित बजट

23. (क्र. 1561) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट सी.एच.एम.ओ. द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी खरीदी स्थानीय स्तर पर की गई? वर्षवार बतावें? आवंटित बजट भी बताएं? (ख) आवंटित बजट में से सी.एच.एम.ओ. को कितने प्रतिशत स्थानीय खरीदी की पात्रता थी और विगत 3 वर्षों में आवंटित बजट एवं उसके समक्ष खरीदी का प्रतिशत भी बताएं? (ग) इसके लिये जिन अखबारों में विज्ञप्ति निकाली गई, उनकी छायाप्रति, विज्ञप्ति शुल्क के साथ विगत 3 वर्षों की जानकारी दें? जिन फर्मों ने टेंडर डाले उनकी छायाप्रति, स्वीकृत फर्मों के टेंडर की छायाप्रति सहित, कार्यनुसार, वर्षवार दें? (घ) निर्धारित मापदण्डों का पालन न करके खरीदी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा विगत 3 वर्षों में स्थानीय स्तर पर क्रय की गई दवाइयों की व्यय राशि का वर्षवार निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित बजट	व्यय
2012-13	38138300	8771809
2013-14	39371025	7274205
2014-15	33139987	4308198

(ख) आवंटित बजट में से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 20 प्रतिशत राशि स्थानीय क्रय खरीदी में पात्रता थी विगत 03 वर्षों में आवंटित बजट एवं खरीदी का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित बजट	स्थानीय स्तर पर औषधि क्रय का प्रतिशत
2012-13	38138300	23
2013-14	39371025	20
2014-15	33139987	13

(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग की एक सतत प्रक्रिया है।

विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी

24. (क्र. 1562) श्री मधु भगत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकास खण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है, कितने अपूर्ण है एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया? वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है, जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार कि कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई? शिकायतों का विवरण देते हुये बतावें कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जाँच किसके द्वारा कराई गई एवं जाँच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति के हितग्राहियों को विमुक्त जाति आवास योजनांतर्गत वर्ष 2014-15

में विकासखण्ड परसवाड़ा, बैहर, बिरसा एवं कटंगी में कुल 69 हितग्राहियों को राशि रूपये 45000/- के मान से स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृत कार्यों की कार्य एजेन्सी स्वयं संबंधित हितग्राही है। वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी विकासखण्डवार एवं वर्षवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रचलित कार्य में पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य एवं कार्यवार भुगतान की गई राशि का विवरण भुगतान दिनांक सहित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। संबंधित जनपद पंचायत द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में चैक द्वारा राशि जमा कराई गई है। (ग) उत्तरांश (क) में वर्णित कार्यों में आवास योजना के कार्यों में आवास स्वीकृत होने पर प्रथम किश्त दी जाती है। तत्पश्चात् हितग्राही द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है। किसी भी हितग्राही को बिना कार्य के अधिक भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- "दस"

मेडीकल कॉलेज सागर में अर्बन सेन्टर खोला जाना

25. (क्र. 1578) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर नगर में शास. बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज के साथ ही अर्बन सेन्टर खोले जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो सागर नगर में शुरू हुये शास. बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज में अर्बन सेन्टर कब तक प्रारंभ हो पायेगा? इस सेन्टर में किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्टर जिला सागर द्वारा दिनांक 3.06.2010 को सागर नगर के चमेली चौक, बडा बाजार स्थित चमेली पॉली क्लीनिक को चिकित्सा महाविद्यालय, सागर से सम्बद्ध किया गया है। इस केन्द्र पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम टीकाकरण एवं मरीजों को प्राथमिक उपचार की सुविधायें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभाग के चिकित्सको एवं मेडिकल सोशल वर्कर्स के द्वारा मरीजों को परिवार नियोजन, टीकाकरण एवं स्तनपान कराने हेतु परामर्श देने की सुविधायें उपलब्ध है।

सागर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन निर्माण

26. (क्र. 1579) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कितनी लागत से किया गया है? इसकी निर्माण एजेंसी कौन थी? उक्त निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? (ख) सागर जिला आयुर्वेदिक औषधालय का नवीन भवन में कब से संचालन प्रारंभ हुआ है? (ग) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य अत्यंत घटिया किस्म का होने से दीवारों में दरार आ गई है एवं भवन विकृत स्थिति में आ गया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला आयुर्वेद चिकित्सालय भवन का निर्माण 45.00 लाख से करवाया गया है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निर्माण एजेंसी रही है। दिनांक 09/12/2013 को निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। (ख) जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का नवीन भवन में संचालन दिनांक 20/02/2014 से प्रारंभ किया गया है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सैलाना विधानसभा क्षेत्र में नवीन विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण

27. (क्र. 1598) श्रीमती संगीता चारेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1 जनवरी 2010 से दि. 31.10.14 तक कितने शिक्षा गारंटी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय, मा.विद्यालय, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल, छात्रावास कितने कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं कितने अपूर्ण स्थिति में हैं? (ख) (क) के अनुसार सैलाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी सभी मदवार, कार्यवार, वर्षवार स्वीकृत राशि के विरुद्ध कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दें? (ग) (ख) में दर्शाये गए अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा तथा कार्य को अधूरा छोड़ कर या समय अवधि में कार्य पूरा न किये जाने पर शासन द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 जनवरी 2010 से 31.10.2014 तक स्कूल व छात्रावास निर्माण के लिए अग्रिम राशि प्रदान की गयी है तथा ठेकेदारों व फर्म में राशि आहरण कर कार्य न किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी, 2010 से दिनांक 31-10-2014 तक शिक्षा गारंटी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय छात्रावास भवन निर्माण के पूर्णता@अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य	पूर्ण	अपूर्ण	कुल कार्य
-------	-------	--------	-----------

1. शिक्षा गारंटी केन्द्र	0	0	0
2. प्राथमिक विद्यालय	1	3	4
3. माध्यमिक विद्यालय	2	5	7
4. छात्रावास	0	0	0

शासकीय हाई@हायर सेकेण्डरी एवं बालिका छात्रावास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-- "ब" पर है। (ग) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। संबंधित एजेन्सी के विरुद्ध ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत एवं निविदा की शर्तों के तहत कार्यवाही की जाती है। (घ) प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में कार्य अपूर्ण रहने पर संबंधित एजेन्सियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिविल अस्पताल हटा की व्यवस्थाएं

28. (क्र. 1609) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत हटा नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? (ख) हटा सिविल अस्पताल में कितने पद स्वीकृत हैं पदवार सूची उपलब्ध करावें? क्या सम्पूर्ण पद सिविल अस्पताल हटा के भरे हुये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन किस-किस पद पर कब से पदस्थ हैं नाम व पदवार जानकारी प्रदाय करें? (ग) हटा सिविल अस्पताल के नहीं भरे हुये/रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी समय सीमा बतावें? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 6 वर्षों से महिला, शिशुरोग विशेषज्ञ की मांग की जा रही है, यदि हाँ तो पद पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटा को सिविल अस्पताल का दर्जा दिनांक 09.09.2008 को प्राप्त हुआ था। (ख) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। भरे हुये पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है, निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। जी हाँ, निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "ग्यारह"

डा. अम्बेडकर सामुदायिक मंगल भवन का निर्माण

29. (क्र. 1773) कुँवर विक्रम सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा डा. अम्बेडकर सामुदायिक मंगल भवन निर्माण हेतु

वर्ष 13-14 एवं 14-15 में कितनी राशि स्वीकृति की गई तथा राज्य शासन ने किस-किस विभाग को कार्य एजेन्सी गठित किया? स्वीकृति की प्रति दें? (ख) क्या छतरपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्र. 169 दि. 07/05/14 के तहत 05 स्थानों पर भूमि चयन हेतु पत्र जारी किया गया था? (ग) राज्य शासन की स्वीकृति के अनुसार कार्य एजेन्सी द्वारा काम न करने के क्या कारण हैं? स्पष्ट करें? (घ) भूमि चयन में विलंब तथा कार्य प्रारंभ न होने में कौन दोषी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक मंगल भवनों के निर्माण हेतु 18.39 करोड़ रुपये व्यय की तथा वर्ष 2104-15 में 416.36 लाख की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा तथा पी.आई.यू. को निर्माण एजेन्सी के रूप में नियत किया गया। स्वीकृति की प्रति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग छतरपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1692 दिनांक 07/05/2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भूमि चयन हेतु पत्र जारी किया गया था। (ग) डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन न होने से कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। (घ) उपयुक्त भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- "बारह"

ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति को राशि का आवंटन

30. (क्र. 1774) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से दिसम्बर 2011 तक 33559 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के रूप में किया गया है? (ख) वर्ष 01.01.12 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति को वार्षिक कितनी राशि दी गई? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा इस राशि की मॉनीटरिंग हेतु ग्राम के बुद्धिजीवी लोगों से बात कर स्वच्छता रखने, नालियों की सफाई, कचरा पेटी आदि के सम्बंध में जाँच की? (घ) उक्त राशि का सीधा अधिकारियों की मिली भगत से दुरुपयोग होना पाया गया क्या राज्य स्तर पर जाँच कराई जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नावधि में वर्ष 2011-12 में 403,407,000/- रु. वर्ष 2012-13 में 441,670,860/- रु. वर्ष 2013-14 में 434,527,000/- रु. एवं वर्ष 2014-15 में 477,981,133/- रु. की राशि आवंटित की गयी। (ग) वीएचएनडी के दिन ग्रामवासियों से प्रश्न में उल्लिखित मुद्दों पर बात की जाती है। शिकायत होने की स्थिति में जाँच भी की जाती है। (घ) जी नहीं। राशि के दुरुपयोग संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करायी जाएगी।

श्रमायुक्त द्वारा जारी आदेश

31. (क्र. 1829) श्रीमती रेखा यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन श्रमायुक्त इंदौर के द्वारा अक्टूबर 2014 में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कार्यरत चौकीदार एवं अग्नि/वन सुरक्षाकर्मियों के भुगतान की जाँच एवं कार्यवाही हेतु क्या-क्या आदेश निर्देश श्रम विभाग छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना को भी दिया? (ख) छतरपुर वनवृत्त के छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना वनमंडल के अंतर्गत किस वनपरीक्षेत्र में गठित कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में से कितनी समितियों द्वारा वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य के बदले किए गए भुगतान की जाँच श्रम विभाग ने प्रश्नांकित तिथि तक कर ली है? किस परिक्षेत्र की कितनी समितियों की जाँच श्रमायुक्त के आदेश के बाद भी प्रश्नांकित तिथि तक नहीं की जा सकी है? (ग) वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य के बदले वनमंडल स्तर से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का किस दर से भुगतान किया जाना चाहिए? यदि वनमंडल से ही समितियों को कम दर से भुगतान किया जा रहा है, तो कानून के अनुसार संबंधित वन अधिकारी के विरुद्ध किस-किस कार्यवाही के प्रावधान दिए गए हैं? (घ) वनमंडल स्तर से समितियों को न्यूनतम मजदूरी की बजाय कम दर से किए गए भुगतान की जाँच प्रश्नांकित तिथि तक क्यों नहीं की गई? यह जाँच की जाकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण बनाए जाने हेतु श्रम विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेगा समय-सीमा सहित बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) श्रमायुक्त द्वारा अक्टूबर, 2014 के पत्र द्वारा श्रम विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (ख) श्रमायुक्त द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.10.2014 के निर्देशानुसार जिलों में वन विभाग से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जानकारी लेने हेतु स्थानीय श्रम कार्यालयों द्वारा पत्र जारी किए गए, किंतु इन जिलों में निरंतर पत्राचार के बाद भी वन विभाग द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई है। जिसके परिणाम स्वरूप समितियों की जाँच नहीं की जा सकी है। उल्लेखनीय है कि इन जिलों में समितियों द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक श्रमिक की ओर से न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजन वनोपज में नियोजन में कार्यरत पूर्णकालिक श्रमिकों को दिनांक 01.10.2014 से निम्नानुसार न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित है जो कि निम्नानुसार **टेबल 1** में है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दर पर वेतन भुगतान पाये जाने पर संबंधित नियोजक के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन तथा दावा प्रकरण सक्षम न्यायालय में दायर किये जाने के प्रावधान है। यदि प्रकरण में संयुक्त वन प्रबंधन समिति नियोजक है तो यह कार्यवाही उनके विरुद्ध ही की जाना संभव है। (घ) प्रश्नांश ख में उल्लेखानुसार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जानकारी

वन विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा नियोजित किसी भी श्रमिक की ओर से न्यूनतम वेतन भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त न होने के कारण जाँच नहीं की जा सकी है तथा उल्लेखित स्थिति के कारण समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

टेबल-1

क्रमांक	श्रेणी	दैनिक न्यूनतम वेतन	मासिक न्यूनतम वेतन
1.	उच्च कुशल श्रमिक	रु. 374/-	रु. 9735/-
2.	कुशल श्रमिक	रु. 324/-	रु. 8435/-
3.	अर्ध कुशल श्रमिक	रु. 271/-	रु. 7057/-
4.	अकुशल श्रमिक	रु. 228/-	रु. 5939/-

संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि

32. (क्र. 1830) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग छतरपुर एवं बैतूल के अंतर्गत वर्ष 2013-2014 में किस श्रेणी के कितने संविदाकर्मों कार्यरत थे? इनमें से कितने संविदाकर्मियों की सेवा अवधि मार्च 2014 को समाप्त हो गई थी? (ख) कितने संविदाकर्मियों से वर्ष 2014 अप्रैल से दिसम्बर 2014 तक कार्य लिया जाकर किस माह में कितने मानदेय का भुगतान किया गया? इन संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि का आदेश किस दिनांक को जारी किया गया? (ग) मार्च 2014 में जिन संविदाकर्मियों की सेवा अवधि समाप्त हो गई थी उन संविदाकर्मियों को अप्रैल 2014 के बाद बिना सेवावृद्धि का आदेश जारी किए किस-किस माह का मानदेय का भुगतान किस नियम के तहत किया गया? (घ) सेवावृद्धि का आदेश जारी किए बिना ही मानदेय का भुगतान किए जाने का क्या कारण रहा है ऐसा किस नियम के तहत किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं पद व नाम सहित बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला छतरपुर की जानकारी निरंक। विभाग के अंतर्गत बैतूल जिले में वर्ष 2013-14 में संविदा अधीक्षक एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी -1, 2, 3 की कार्यरत संख्या निम्नानुसार है-

क्रं.	पदनाम	कार्यरत संख्या
1	संविदा अधीक्षक	45
2	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1	31

3	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2	197
4	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3	725
	योग	998

उपरोक्त में से 485 संविदा कर्मियों की सेवा अवधि मार्च 2014 में समाप्त हो गई थी। (ख) जिला छतरपुर की जानकारी निरंक। जिला बैतूल में अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक के कुल 998 संविदा कर्मियों से कार्य लिया जाकर निम्नानुसार माहों में भुगतान किया गया है-

माह	कुल मानदेय राशि
अप्रैल 2014	5598000
मई 2014	5598000
जून 2014	5598000
जुलाई 2014	5598000
अगस्त 2014	5598000
सितम्बर 2014	5598000
अक्टूबर 2014	5598000
नवम्बर 2014	5598000
दिसंबर 2014	5598000

संविदा अवधि समाप्त होने पर कार्यरत संविदा अधीक्षकों के सेवावृद्धि आदेश दिनांक 08/08/2014, 04/12/2014 को जारी किये गये हैं। शेष की सेवावृद्धि आदेश/संविलियन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जिला छतरपुर की जानकारी निरंक। जिला बैतूल में वर्ष 2014 में जिन संविदा शाला शिक्षकों की तीन वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण हो चुकी थी उन संविदा शिक्षकों को अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक के मानदेय का भुगतान निरंतर किया गया है। सेवावृद्धि एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये जाने की कार्यवाही जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सेवावृद्धि अथवा अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की प्रत्याशा में संबंधित शिक्षकों को कार्यवधि का मानदेय भुगतान किया गया है। (घ) जिला छतरपुर की जानकारी निरंक। जिला बैतूल में संविदा शाला शिक्षकों से निरंतर शैक्षणिक कार्य लिया जा रहा है। संबंधित संविदा शाला शिक्षकों को उनके कार्य करने की अवधि का मानदेय का भुगतान किया गया है। सेवावृद्धि एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वेतन भुगतान अनियमित नहीं हुआ है। अतः इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारण का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ है।

संविदा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

33. (क्र. 1916) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत कार्यरत संविदा एम.डब्ल्यू. एवं एम.टी.एस. के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संविदा कर्मचारियों को कब से बढ़े हुए वेतन दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संविदा कर्मचारियों को कब से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? कारण बतायें? वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या संविदा कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ तो कब से एरियर्स का भुगतान करना शेष है? एवं एरियर्स का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सीधी जिले में संविदा एम.पी.डब्ल्यू के 41 एवं एम.टी.एस. के 5 तथा सिंगरौली जिले में संविदा एम.पी.डब्ल्यू के 45 एवं 01 एम.टी.एस. कार्यरत हैं। (ख) सीधी जिले में संविदा कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2013 से एवं सिंगरौली जिले में 01 अप्रैल 2014 से बढ़े हुए मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले में संविदा कर्मचारियों के अंतर्गत एम.पी.डब्ल्यू के मानदेय का भुगतान माह सितम्बर के पश्चात नहीं किया गया है। एम.पी.डब्ल्यू का मानदेय माह अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014 तक भारत सरकार द्वारा प्रदाय किया गया था, इसके पश्चात अक्टूबर 2014 से एम.पी.डब्ल्यू के मानदेय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शासन के अधीन विचाराधीन है। स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। (घ) सीधी जिले में मानदेय के एरियर्स का भुगतान लंबित नहीं है। सिंगरौली जिले में अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के एरियर्स का भुगतान लंबित है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षकों की पदोन्नति

34. (क्र. 1931) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग के जिला अनूपपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग/शिक्षाविभाग के अंतर्गत 31 मार्च 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितने सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में व प्रधानाध्यापकों को व्याख्याता के पद पर एवं व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है? (ख) कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं प्राचार्य को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है? क्या कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो सेवानिवृत्ति की कगार में हैं परन्तु उन्हें क्रमोन्नति का लाभ तो मिला लेकिन पदोन्नति के लाभ से वंचित हैं? उक्त कर्मचारियों को कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी? समय सीमा में पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं? कब तक इन कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी जायेगी? (ग) कब तक के कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम में पदोन्नत किया जाना शेष है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 31 मार्च 2011 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षक के पद रिक्त

नहीं होने के कारण सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति नहीं की गई। 120 उच्च श्रेणी शिक्षकों की प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई। उच्च श्रेणी शिक्षक/ प्रधान पाठक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09/07/2014 को आहूत की गई थी। व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु अनूपपुर जिले के 07 शिक्षकों को उपयुक्त पाया गया है। पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अनूपपुर जिले में व्याख्याता से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर 26 व्याख्याताओं की पदोन्नति की गई है। (ख) अनूपपुर जिले में उपलब्ध, रिक्त पदों के अनुसार सभी पात्र सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षकों पदोन्नति दी गई है। उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक से राज्यस्तरीय वरिष्ठता में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। व्याख्याताओं की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठताक्रम एवं पात्रता अनुसार प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है। पदोन्नति की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया होने से समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) पदोन्नति पद रिक्त/उपलब्ध होने पर वरिष्ठता एवं पात्रता अनुसार दी जाती है, कौन पात्र होगा यह बतलाना संभव नहीं है।

शालाओं का उन्नयन

35. (क्र. 1957) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोडाडोंगरी क्षेत्र के खण्ड शाहपुर, घोडाडोंगरी, चिचौली में कितने हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी हेतु उन्नयन माध्यमिक शाला है? (ख) कितने प्राचार्य के पद रिक्त हैं? (ग) चोपना हायर सेकण्डरी में प्राचार्य का पद कब से रिक्त है? कब तक पद भरेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बैतूल जिले के विकासखण्ड शाहपुर, घोडाडोंगरी, चिचौली में निम्नानुसार हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल/ माध्यमिक शाला संचालित है -

विकासखण्ड का नाम	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी स्कूल	माध्यमिक शाला
शाहपुर	10	6	63
घोडाडोंगरी	18	8	92
चिचौली	7	7	57
योग	35	21	212

(ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित हाईस्कूल में 21 एवं हायर सेकेण्डरी में 07 कुल 28 प्राचार्य के पद रिक्त है। (ग) हायर सेकेण्डरी चोपना में प्राचार्य का पद दिनांक 01/11/2012 से रिक्त है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्राथ. स्वा. केन्द्र मझगंवा का उन्नयन

36. (क्र. 1967) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या-95 (क्र. 1240) दिनांक 12.12.2014 में अवगत कराया गया था, कि जबलपुर जिले के मझगंवा पी.एच.सी. को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने का प्रकरण परीक्षाधीन है? (ख) क्या यह सही है कि मझगंवा पी.एच.सी. में कुल 154 गांव आते हैं, और उनकी आबादी 1.30 लाख से अधिक है? यहाँ पर जनता का दबाव बहुत ज्यादा रहता है एवं उन्नयन किया जाना अति आवश्यक है? यदि हाँ तो कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा? निश्चित समय सीमा बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं, 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगंवा में, बाह्य रोगी प्रतिदिन 70-100 एवं आंतरिक रोगी लगभग 1-2 प्रतिदिन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

क्षेत्रीय ग्रंथपाल के वेतनमान में असमानता

37. (क्र. 2000) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय ग्रंथपाल एवं प्राचार्य (10+2) का वेतनमान एक समान 15600-39100+5400 ग्रेड पे है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त पदों पर क्रमशः उच्च वेतनमान ग्रंथपाल (पदोन्नत क्षेत्रीय ग्रंथपाल) एवं प्राचार्य हाई स्कूल/वरिष्ठ व्याख्याता की पदोन्नति होती है? (ग) यदि हाँ, तो उच्च वेतनमान ग्रंथपाल एवं वरिष्ठ व्याख्याता/प्राचार्य हाई स्कूल का वेतनमान समान है? (घ) यदि नहीं, तो क्यों? यदि इस असमानता को दूर किया जाना है तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) उच्च वेतनमान ग्रंथपाल से क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पद पर तथा प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति का नियमों में प्रावधान है। व्याख्याता से प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) भरती तथा पदोन्नति नियमों में ये पद पृथक-पृथक संवर्ग के एवं पृथक-पृथक वेतनमान के हैं। पदों की पारस्परिक तुलना नहीं की जा सकती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र बीना अन्तर्गत भवन विहीन स्कूल

38. (क्र. 2003) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना में कितने हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन विहीन हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) भवनविहीन स्कूलों के भवन कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? शास.उ.मा.वि. मानगढ़ का भवन वर्ष 2008 में स्वीकृत किया गया था, जिसका निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण है, निर्माण कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है, एवं निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र बीना के हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कितने नियमित प्राचार्य कार्यरत हैं, एवं कितने स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं, सूची

उपलब्ध करायी जावे एवं विगत 2 वर्ष का हाईस्कूल/हा.से. के परीक्षा परिणाम क्या रहे हैं, यदि हाँ तो नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना कब हो जायेगी, जिससे परीक्षा परिणामों में सुधार आ सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बीना विधानसभा क्षेत्र में 06 हाईस्कूल एवं 06 हायर सेकेण्डरी स्कूल शासकीय माध्यमिक शाला भवनों में एवं एक हायर सेकेण्डरी स्कूल रेल्वे के बैरक में संचालित है। "जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।" (ख) शाला भवन का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2008 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ का भवन स्वीकृत किया गया है। जिसका 75 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है। निर्माण एजेंसी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) संचालित हाईस्कूल में से 04 शालाओं में नियमित प्राचार्य एवं 12 शालाओं में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं तथा संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल में से 02 शालाओं में नियमित प्राचार्य एवं 10 शालाओं में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं। "जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।" बीना विधानसभा क्षेत्र में संचालित शालाओं में हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षा परिणाम 2012-13 में 39.73, एवं 2013-14 में 44.71 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में हायर सेकेण्डरी परीक्षा का परीक्षा परिणाम 2012-13 में 52.32 एवं 2013-14 में 55.93 प्रतिशत रहा है। नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट- "तेरह"

हाईस्कूलों के भवनों का निर्माण

39. (क्र. 2078) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2003 से वर्तमान तक कितने हाई स्कूल (नवीन) कहाँ-कहाँ स्वीकृत हुये हैं? (ख) कितने नवीन हाई स्कूलों के भवन स्वीकृत हुये हैं? कितने भवन विहीन हैं? कहाँ-कहाँ? (ग) भवन विहीन हाई स्कूलों के भवनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) "जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।" (ग) शाला भवनों की स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "चौदह"

शासकीय चिकित्सालयों में ट्रामा सेंटर की स्थापना

40. (क्र. 2080) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में जनवरी 2013 के पश्चात शासकीय चिकित्सालयों में कहाँ-कहाँ ट्रामा सेन्टर प्रस्तावित हैं कहाँ-कहाँ भवन पूर्ण हो चुका

है, तथा कहाँ-कहाँ उपकरण लगा दिये गये हैं? (ख) स्वीकृत ट्रामा सेन्टर पर कहाँ-कहाँ कितने पद स्वीकृत कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं, इनमें कितने फिजियोथैरेपी डॉक्टर के पद हैं? (ग) मन्दसौर जिला चिकित्सालय में प्रस्तावित एवं निर्मित ट्रामा सेन्टर प्रारंभ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं, कब तक प्रारंभ कर दिये जाएँगे? (घ) मन्दसौर जिला चिकित्सालय में 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने हड्डी रोगी दर्ज हुए हैं, वर्षवार जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन संभाग में जनवरी 2013 के पश्चात जिला चिकित्सालय शाजापुर में ट्रामा सेन्टर की प्रशासकिय स्वीकृती जारी की गई है। जिला चिकित्सा आगर-मालवा में ट्रामा सेन्टर का निर्माण 13 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत है। भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात उपकरण स्थापित किये जावेंगे। (ख) जिला चिकित्सालय शाजापुर में ट्रामा सेन्टर हेतु चिकित्सा विशेषज्ञ 01, निश्चेतना विशेषज्ञ 01, अस्थि रोग विशेषज्ञ 01, चिकित्सा अधिकारी 05 पद स्वीकृत है। भवन निर्माण पूर्ण होने के पर पदस्थापना की जायगी। ट्रामा सेन्टर हेतु फिजियोथैरेपी डॉक्टर के पद स्वीकृत नहीं है। (ग) जिला चिकित्सालय मन्दसौर में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जावेगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) दिनांक 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक 11/02/2015 तक कुल 4402 हड्डी रोगियों का उपचार किया गया। वर्ष वार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	वर्ष	हड्डी रोगियों की दर्ज संख्या
1	2013	1950
2	2014	2188
3	01 जनवरी से दिनांक 11/02/2015 तक	264

राज्य बीमारी सहायता कोष से स्वीकृत राशि

41. (क्र. 2093) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सरकारी एवं निजी चिकित्सालय अंतर्गत ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, जहाँ राज्य बीमारी सहायता के माध्यम से अलग-अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है? (ख) अस्पताल एवं बीमारी का नाम जिस संस्था में इलाज कराने का राज्य सरकार ने अधिकृत किया है? (ग) विगत दो वित्तीय वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक म.प्र. शासन द्वारा कितने व्यक्तियों का राज्य बीमारी सहायता से इलाज हेतु कितनी राशि दी गई? (घ) प्राक्कलन अनुसार स्वीकृति राशि का पूरा उपयोग किया जाता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) राज्य बीमारी सहायता के अन्तर्गत चिन्हित बीमारियों का ईलाज प्रदेश के अन्दर 07 शासकीय अस्पतालों एवं 34 निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विगत दो वित्तीय वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक राज्य बीमारी सहायता निधि से ईलाज हेतु हितग्राहियों को दी गई सहायता की संख्या एवं राशि निम्नानुसार है:

क्रमांक	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	राशि
1	2012-13	6908	612566501
2	2013-14	6925	651812037
3	2014-15 प्रश्न दिनांक तक	3991	381240930

(घ) चिकित्सालयों द्वारा प्राक्कलन प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न बीमारी के पैकेज अनुसार स्वीकृति दी जाती है, यदि कोई राशि शेष बचती है तो संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख करते हुये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वापस की जाती है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

42. (क्र. 2094) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल में स्वीकृत पद के मान से कितने शिक्षकों/अध्यापकों के पद रिक्त है? (ख) शिक्षकों/अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिले व शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या जिले में ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ एक शिक्षकीय विद्यालय होने के बावजूद अन्य कार्य/स्थान में ड्यूटी लगा देने के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन हो गये हैं? (घ) विद्यालय को शिक्षक विहीन करने के लिये दोषी कौन है, तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभागान्तर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रश्नांकित जिले की "जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।" (ख) रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति एवं संविदा शाला शिक्षक भर्ती से की जाती है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

जिला चिकित्सालय शहडोल में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

43. (क्र. 2096) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय शहडोल में चिकित्सकों के कितने पद

स्वीकृत हैं, तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय शहडोल में चिकित्सकों के कुल 58 पद स्वीकृत एवं 27 पद रिक्त हैं। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरुद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

मॉडल स्कूल जावरा में निर्माण कार्य

44. (क्र. 2103) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर मॉडल स्कूल के विगत वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां दी जाकर कार्य किये गये? (ख) क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जाकर उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए? तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण होकर बंद पड़े हैं? (ग) वर्ष 2005-06 से लेकर प्रश्न दिनांक तक विभाग/शासन द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर उसमें से कितनी राशि व्यय हुई? (घ) उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्यों के बजट, कार्यों की पूर्णता, कार्यों की अपूर्णता के भौतिक सत्यापन सहित वस्तु स्थिति से अवगत कराए?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) "जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।"

इप्का लेबोरेट्री में कार्यरत स्थाई एवं अस्थायी मजदूरों की संख्या

45. (क्र. 2104) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत ग्राम सेजावता तहसील रतलाम में इप्का लेबोरेट्री के नाम से उद्योग स्थापित होकर उसमें सैकड़ों स्थाई एवं अस्थायी मजदूर कार्यरत होकर कार्य करते हैं? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त उद्योग में कितने स्थाई एवं कितने अस्थायी रूप से कार्य करने वाले मजदूर विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं? वे कार्य किस-किस प्रकार के होते हैं? (ग) साथ ही क्या स्थाई एवं अस्थायी मजदूरों की जीवन रक्षा हेतु कोई उपाय निश्चित किये जाकर उनका दुर्घटना बीमा, आकस्मिक मृत्यु सहायता, बीमा, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है? (घ) साथ ही क्या ठेका पद्धति के माध्यम से भी कार्य करवाये जाते

हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त समस्त तथ्यों से अवगत करायें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) इप्का लेबोरेट्रीज में 2, 023 स्थाई श्रमिक एवं 43 अस्थाई श्रमिक कार्यरत हैं। स्थाई श्रमिकों द्वारा उत्पादन से संबंधित कार्य- जैसे बेच चार्जिंग, प्रोसेस मॉनिटरिंग, उत्पादन से संबंधित दस्तावेज बनाना, माल का पैकिंग, इत्यादि कार्य किया जाता है। अस्थाई श्रमिकों द्वारा माल की लोडिंग/अनलोडिंग, शिफ्टिंग इत्यादि कार्य किया जाता है। (ग) जी हाँ। श्रमिकों के लिये कार्यस्थल पर कंपनी द्वारा जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। सभी श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराया गया है श्रमिकों को पात्रतानुसार केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सा सहायता एवं दुर्घटना बीमा सहायता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तथा कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं द्वारा चिकित्सा की सुविधा दी जाती है। (घ) जी हाँ। वर्ष 2010 से वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

रिक्त पदों की पूर्ति

46. (क्र. 2117) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एच.सी. त्योंथर एवं चाकघाट जिला रीवा में स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी दें? (ख) यदि स्वीकृत पद के अनुरूप पद भरे नहीं तो रिक्त पदों की कब तक पूर्ति की जायेगी? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति की समय सीमा बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग के अधीन विशेषज्ञों एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी हैं। चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, तथा पैरामेडिकल के 900 पदों पर सीधी भर्ती हेतु मांग पत्रव्यापम को प्रेषित किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही की जायेगी। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

ग्रन्थपालों को समयमान - वेतनमान का लाभ

47. (क्र. 2124) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के समस्त कर्मचारियों को 30 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर लेने पर तीन पदोन्नति या तीन समयमान/वेतनमान दिये जाने का नियम है? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रन्थपालों को इससे वंचित रखा गया है? (ग) जबकि अन्य विभागों के ग्रन्थपालों को इसका लाभ शासन द्वारा प्रदान कर दिया जाता है? (घ) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रन्थपालों को भी इसका लाभ दिया जाना

विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उपरोक्त लाभ ग्रन्थपालों को कब तक प्रदान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्रंथपालों हेतु अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेतर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 है। ग्रंथपालों को शिक्षक संवर्ग में घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रंथपालों द्वारा शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। (घ) जी नहीं। इन्हें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है, जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है, उन्हें समयमान वेतनमान नहीं दिया जाता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षकीय पद की पूर्ति

48. (क्र. 2126) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अनेक आयुर्वेद महाविद्यालयों में अनेक शिक्षकीय पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो महाविद्यालयवार रिक्त पदों की सूची दें, तथा इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) क्या विगत 05 वर्षों के अंतराल में प्रदेश के अनेक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों को मान्यता न मिल पाने के कारण उन वर्षों में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था? वर्षवार शासकीय महाविद्यालयों की सूची एवं उनमें स्वीकृत छात्र संख्या बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मान्यता न मिलने एवं उन वर्षों में छात्रों के प्रवेश शून्यवत रहने के लिए क्या मूल कारण उन महाविद्यालयों में शिक्षकीय पदों का रिक्त होना था? यदि हाँ, तो क्या रिक्त पदों को शीघ्र भरा जावेगा? यदि हाँ, तो कब?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार।** रिक्त पद पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) विगत 05 वर्षों में जिन महाविद्यालयों में मान्यता न मिलने से प्रवेश नहीं दिया गया उनकी वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) जी हाँ। पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "सत्रह"

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति

49. (क्र. 2128) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक के 19 पद एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी (प्रशासन) के 15 पद पदोन्नति हेतु परि.अतां. प्रश्न क्र. 3072 दिनांक : 25.07.2014 में बताये गये थे? यह पद किस वर्ष से रिक्त है? (ख) क्या विभाग द्वारा रिक्त पदों पर प्रतिवर्ष शासन प्रावधान अनुसार पदोन्नति नहीं की जाती? यदि हाँ तो कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों के अलावा किस-किस पदों के पदोन्नति

के प्रस्ताव वर्षवार, पदवार, संख्यावार एम.पी. पी.एस.सी. को भेजे गये हैं? जिनकी प्रश्न दिनांक तक पदोन्नति नहीं हुई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं सागर में नहीं। अपितु आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक के 19 पद तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रशासन) के 15 पद रिक्त बताये गये थे। (ख) विभाग द्वारा रिक्त पदों पर प्रतिवर्ष शासन प्रावधान अनुसार पदोन्नति की जाती है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट- "अठारह"

आदिम जाति कल्याण विभाग सागर में सामग्री का वितरण

50. (क्र. 2131) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में प्रश्न क्र. 3071 दिनांक 25.07.2014 में मांग एवं छात्र-छात्राओं की आवश्यकता अनुरूप सामग्री का वितरण बताया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्ष 2012-13 में 50 सीट के छात्रावास रहली, देवरी, गौरझामर, राहतगढ़, जैसीनगर प्रत्येक को 200 चादर एवं जैसीनगर को 150 प्रसाधन किट क्यों दिये गये हैं? औचित्य बताये? अन्य सामग्री भी मांग/आवश्यकता अनुसार वितरण नहीं की गई? परिशिष्ट (अ) (ब) से स्पष्ट है? (ग) क्या विभाग में सामग्री का समय पर वितरण नहीं किया जाता? प्रश्न दिनांक को आदिवासियों के विद्युत पंप एवं पलंग स्टोर के स्थान पर अन्य विभागीय भवनों में रखे हैं? रजाई फिनायल एवं सामग्री समय पर नहीं भेजने की जाँच की गई है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) (ग) के लिये कौन जिम्मेदार है विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) छात्रावासों को चादर का प्रदाय छात्रावास अधीक्षकों की मांगानुसार किया गया है। अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जैसीनगर तथा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जैसीनगर को दिनांक 21.1.2012 एवं एक अन्य अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जैसीनगर को दिनांक 6.11.2013 को 50-50 नग प्रसाधन किट प्रदाय की गई है। प्रश्न क्रमांक-3071 दिनांक 25.7.2014 की जानकारी भेजते समय टंकण त्रुटि के कारण 6.11. 2013 के स्थान पर 6.11.2012 लिखा गया है। अतः एक ही छात्रावास में 150 प्रसाधन किट वितरित नहीं की गई है। (ग) आदिवासी विकास विभाग द्वारा क्रय सामग्री के भौतिक सत्यापन उपरांत सामग्री का वितरण संस्थाओं में किया जाता है। जिला सागर में वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत 300 नग रजाई एवं वर्ष, 2010-11 में 200 नग रजाई क्रय की गई जिसका वितरण समय पर न होने के कारण संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर द्वारा जाँच की गई है। विद्युत पंप, पलंग एवं फिनाईल आदिवासी मद से क्रय नहीं किये गये हैं। जी नहीं।

विभागीय स्टोर किराये के निजी भवन में संचालित है जिनमें स्थान अनुपलब्ध होने के कारण कपिलधारा योजना के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले पंपों को अस्थाई रूप से अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सागर के एक कक्ष में रखा गया है। इसी प्रकार कुछ पलंग टी सी पी सी सागर के एक कक्ष में अस्थाई रूप से वितरण हेतु रखे गये हैं। जी हाँ। रजाई, फिनाईल एवं अन्य सामग्री समय पर नहीं भेजने की जाँच संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग द्वारा की गई है। (घ) जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनुपयोगी सामग्री का क्रय

51. (क्र. 2132) श्री हर्ष यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग सागर द्वारा वर्ष 2010 में छात्रावासी बच्चों के उपयोगार्थ रजाईयां, बेडशीट आदि सामग्री क्रय की थी? यदि हाँ, तो क्रय सामग्री को वितरित न कर एक वर्ष से अधिक समय तक स्टोर में रखे जाने के क्या कारण रहे? क्या इस मामले में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया? (ख) टी.सी.पी.सी. सागर के एक कक्ष में एवं उत्कृष्ट बालक छात्रावास सागर के एक कक्ष में छात्रों के उपयोगार्थ क्रय की गई क्या-क्या सामग्री कब से भंडारित की गई है? इसका उपयोग न किये जाने के क्या कारण है इस सामग्री को कब क्रय किया गया था? (ग) अनुपयोगी सामग्री क्रय कर के उसको लंबे समय तक स्टोर में खराब करने, शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने, समय पर सामग्री का समुचित छात्रहित में उपयोग न कराने हेतु कौन उत्तरदायी है? इनके विरुद्ध कब तक नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ, यह सही है कि सागर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में आदिवासी मद अन्तर्गत वर्ष 2010 में 300 रजाईयां क्रय की गई थीं। उक्त वर्ष में बेडशीट क्रय नहीं की गई है। यह भी सही है कि वर्ष 2009-10 में क्रय की गयी रजाईयां भंडारण में रखी गई थीं। जिसकी जाँच सम्भागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग सागर द्वारा की गई है। (ख) प्रश्नांश (ख) में भंडारित सामग्री आदिवासी विकास विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अतः आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल एवं संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्य प्रदेश, भोपाल से जानकारी प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। (ग) यह सही नहीं है, कि विभाग द्वारा अनुपयोगी सामग्री क्रय की जाती है। म.प्र. भंडार क्रय नियम अनुसार विभागीय जिला क्रय समिति के अनुमोदन उपरांत तथा भौतिक सत्यापन उपरान्त क्रय तथा वितरण की कार्यवाही की जाती है। सामग्री स्टोर में खराब होने के सम्बन्ध में श्री के.के. जैन, मण्डल संयोजक, आदिवासी विकास, सागर द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में, कार्यालय सम्भागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागरसंभाग सागर द्वारा जाँच

की गई है। जाँच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 138/शिकायत/2015 दिनांक 12/2/2015 द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सागर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन

52. (क्र. 2141) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में सतना जिले के किन-किन अशासकीय स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बी.पी.एल./निम्न आय वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया? क्या उक्त अवधि में विद्यालयों द्वारा छात्र संख्या के मान से समुचित प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दिया गया? किन-किन संस्थाओं द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया? (ख) केन्द्रीय शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने का उत्तरदायित्व किसका है? क्या उक्त अवधि में इन विद्यालयों से प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन कराया गया? (ग) सतना जिले में किस संस्था को कितनी-कितनी राशि वर्षवार फीस प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा दी गई? (घ) उक्त अवधि में बच्चों के प्रवेश को लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधी क्या-क्या शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? शिकायतवार की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार है। जी हाँ। अधिनियम के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का। जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" अनुसार है। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिवपुरी जिले में अपात्र गुरुजियों को एरियर का भुगतान

53. (क्र. 2154) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले की शिक्षा गारण्टी शालाओं में गुरुजी के पद पर निर्धारित मानदेय पर कार्यरत लगभग 150 गुरुजियों को बिना अध्यापक बने शासन के नियमों की अनदेखी कर करीब डेढ़ करोड़ रूपयों की राशि एरियर के रूप में भुगतान कर दी गई है? (ख) यदि हाँ तो किन-किन गुरुजियों को कितनी-कितनी एरियर राशि किन-किन के द्वारा किसकी स्वीकृति से कब-कब भुगतान की गई? (ग) उक्त अनियमितता पर जिला प्रशासन एवं शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासकीय राशि का अनियमित भुगतान करने वाले दोषियों से राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) उत्तरांश क के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्देशों की अवहेलना

54. (क्र. 2155) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा संलग्नीकरण समाप्त कर जानकारी भेजने के संबंध में सी.एम.एच.ओ. शिवपुरी को उनके पत्र क्रमांक/स्था.अवि./2014/5442-58 ग्वालियर दिनांक 03/06/2014 से निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा उक्त निर्देश के पालन में किन-किन का संलग्नीकरण कहाँ-कहाँ से कब-कब किस आदेश से समाप्त किया गया एवं उन्हें किस पद एवं स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया? भेजी गई जानकारी एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दें? (ग) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के अंतर्गत कई कर्मचारी/डॉक्टर मूल पदस्थापना के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में दिसंबर 2014 की स्थिति में संलग्नीकरण के तहत कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम, मूल पद, कार्यालय एवं संलग्नीकरण के तहत कर रहे कार्य की जानकारी दें? (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय शिवपुरी में विगत 5 वर्षों में संलग्नीकरण के तहत कौन-कौन संलग्न किए गए और उन्हें किन-किन शाखाओं का कब से कब तक प्रभार दिया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर के पत्र क्रमांक/स्था.अवि./2014/5442-58 ग्वालियर दिनांक 03/06/2014 (ई-मेल) के निर्देशों के पालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई किन्तु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक/58/248/2015/सत्रह/मेडि-1/दिनांक 12.01.2015 के पालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा दिनांक 30.01.2015 को संलग्नीकरण समाप्त करने संबंधी आदेश जारी किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ग) मूल पदस्थापना के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में दिसंबर 2014 की स्थिति में संलग्नीकरण के तहत कार्यरत कर्मचारी/डॉक्टर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

टंट्या भील स्वरोजगार योजना में लाभान्वित हितग्राही

55. (क्र. 2183) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में टंट्या भील स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी थी? यदि हाँ, तो जिले में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? (ख) क्या टंट्या भील स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2013-14 में लाभान्वित हितग्राहियों की अनुदान राशि संबंधित बैंकों को भेजी गयी है? यदि नहीं तो

क्यों और कब तक भेजी जायेगी? (ग) क्या टंट्या भील स्वरोजगार योजना बंद कर दी गयी है? यदि हाँ, तो उक्त योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करने की क्या योजना है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। शहडोल जिले में वर्ष 2013-14 में टंट्या भील स्वरोजगार योजना के तहत 128 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। (ख) टंट्या भील स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2013-14 में लाभान्वित 128 हितग्राहियों में से 98 हितग्राहियों की अनुदान राशि बैंकों को प्राप्त हो चुकी है। 30 हितग्राहियों को अनुदान राशि भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। टंट्या भील स्वरोजगार योजना के स्थान पर राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (आदिवासियों हेतु) प्रारंभ की गई है।

बैहर विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सकों की पद पूर्ति

56. (क्र. 2207) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की, बैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सालयों में चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मचारियों एवं अन्य समस्त संवर्गों के चिकित्सालयवार स्वीकृत पद बतावें? (ख) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, कब से पदस्थ हैं? संवर्गवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरुद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार चिकित्सक की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। पैरामेडिकल स्टॉफ पद पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को 900 पदों हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

दवाईयों के क्रय हेतु निविदाओं की स्वीकृति

57. (क्र. 2208) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में जिला स्तर पर वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कब-कब दवाईयां क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं, तथा उक्त अवधि में किन-किन फर्मों द्वारा निविदाएं डाली गईं? इनमें से किन-किन की निविदायें स्वीकृत की गईं? (ख) स्वीकृत निविदाओं में दर्शायी गई दवाओं के मूल्य एवं बाजार में उक्त दवाओं के मूल्य का मिलान/सत्यापन किनके द्वारा किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-1, अ-2, अ-3 एवं प्रपत्र अ-4 अनुसार है। (ख) स्वीकृत निविदाओं में दर्शाई गई दरों का मूल्यांकन जिला स्तर पर क्रय समिति/तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है।

ग्रन्थालय/सहायक ग्रन्थपाल के पदों की पूर्ति जानकारी

58. (क्र. 2228) सुश्री उषा ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के हायर सेकण्डरी विद्यालयों (शासकीय) के लिये ग्रन्थपाल/सहा.ग्रन्थपाल के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने रिक्त हैं? कब तक भरे जावेंगे? (ख) गत 5 वर्षों में प्रदेश के शासकीय हायर सेकण्डरी विद्यालयों के ग्रन्थालयों में पुस्तकें/फर्निचर क्रय करने हेतु कितनी राशि स्वीकृत/आवंटित की गई? (ग) प्रदेश के शासकीय हायर सेकण्डरी विद्यालयों के ग्रन्थालयों हेतु स्वीकृत राशि, पुस्तकें/फर्निचर क्रय किये जाने बाबत उपयोगिता प्रमाणिकरण हेतु पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) ग्रन्थपाल (उच्च वेतनमान) के 94 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 64 पर रिक्त हैं तथा ग्रन्थपाल (निम्न वेतनमान) के 107 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 99 पद रिक्त हैं। निश्चित समयावधि बताया संभव नहीं है। (ख) हायर सेकण्डरी विद्यालयों के ग्रन्थपालों हेतु पृथक से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है। समस्त शासकीय हाई स्कूलों एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में जहाँ कक्षा 9 एवं कक्षा 10 संचालित है। वहाँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत रुपये- 50, 000 की राशि अनुदान के रूप में शालाओं को दी जाती है, जिसमें शाला के आकस्मिक व्यय, साफ सफाई समाचार पत्र पत्रिकाएँ इत्यादि हेतु राशि का उपयोग शाला द्वारा किया जा सकता है। (ग) उत्तरांश (ख) में वर्णित अनुदान की राशि की उपयोगिता का पर्यवेक्षण प्रमाणिकरण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सामुदायिक/सिविल हॉस्पिटल, डबरा में रोगी कल्याण समिति की आयोजित बैठक

59. (क्र. 2249) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी आयोजित की जाती है, नियम की प्रति उपलब्ध करायें तथा जिला ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल डबरा में रोगी कल्याण समिति की बैठक गत वर्ष (अंतिम बार) किस दिनांक को आयोजित की गई थी, इसके बाद इस बैठक का आयोजन किस कारण नहीं किया जा रहा है, इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, नाम सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार

क्या यह सही है कि रोगी कल्याण समिति की बैठक के अनुमोदन बिना ही जन भागीदारी की राशि खर्च की जा रही है, इसकी गत वर्ष अंतिम बैठक के बाद प्रश्न दिनांक तक किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार सिविल हॉस्पिटल डबरा में रोगी कल्याण समिति को वर्ष 2011-12 से 2014-15 (जनवरी, 2015 तक) वर्षवार कितनी आय हुई, तथा कितनी राशि अभी तक व्यय की गई, वर्षवार बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार एवं कार्यकारी सभा की बैठक दो माह में एक बार किये जाने का प्रावधान है। नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। वर्ष 2014 में लोकसभा निर्वाचन, नगर पालिका निर्वाचन एवं पंचायत निर्वाचन के कारण लगी आचार संहिता के कारण रोगी कल्याण समिति की बैठक आहूत नहीं हो सकी। माह जुलाई से अक्टूबर 2014 तक वर्षा ऋतु में होने वाली मौसमी बीमारियों के चिकित्सकीय प्रबन्धन में व्यस्तता होने के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। उपरोक्त कारणों के परीप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) अति आवश्यक एवं मूलभूत कार्यों हेतु राशि व्यय की गयी। गत वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न गतिविधियों पर किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।

जाँच उपरांत संबंधितों पर कार्यवाही

60. (क्र. 2273) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 12/12/2014 में मुद्रित प्रश्न क्रमांक 307 के प्रश्नांश (क) का उत्तर जी हाँ, (ख) का उत्तर जाँच प्रचलित है, जी हाँ, पुनः अर्धशासकीय पत्र क्रं. 13773 दिनांक 02/12/2014 को भी प्रमुख सचिव कृषि को कार्यवाही हेतु लिखा गया है (ग) का उत्तर जाँच प्रचलित है, जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी (घ) का उत्तर म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-1/96/आ.प्रा.-1 दिनांक 08/09/1997 के निर्देशानुसार छान-बीन समिति को सतर्कता अधिकारी से जाँच कराकर निर्णय लेने के निर्देश हैं? यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें आवश्यक जाँच उपरांत निर्णय संभव होता है? प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जाँच निरंतर प्रचलित है, का उत्तर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 02/12/2014 को प्रमुख सचिव कृषि को लिखे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? संबंधित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएँ, तथा विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में जाँच की कार्यवाही प्रचलित होना बताया गया था? उक्त जाँच की गंभीरता को देखते हुये जाँच किस से कराई जा रही है और जाँच अधिकारी द्वारा कब-कब क्या जाँच की गई? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 08/09/1997 के निर्देशानुसार छान-बीन समिति की सतर्कता अधिकारी से जाँच कराने के

प्रावधान मात्र का उल्लेख किया गया? क्या वास्तव में उक्त छान-बीन समिति द्वारा कब-कब जाँच हेतु छान-बीन समिति की बैठक हुयी? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग), (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत देखते हुये समय सीमा में कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कब तक की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र क्रमांक 23773 दिनांक 02/12/2014 की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं कृषि विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 307 में उल्लेखित अनावेदक के प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 29/01/2015 एवं विवरण की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 5854/1994 कु. माधुरी पाटिल विरुद्ध एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेवलपमेंट महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 02/09/2014 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं है। (घ) म.प्र.शासन. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 7-1-96 आ.प्र.-एक दिनांक 08 सितम्बर 1997 के अनुसार छानबीन समिति को पुलिस अधिकारी/सतर्कता अधिकारी से जाँच कराने के निर्देश हैं। पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर छानबीन समिति की बैठक आयोजित कर प्रकरण आवश्यक जाँच निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का प्रावधान है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 29/01/2015 समिति को दिनांक 12/02/2015 को प्राप्त हुआ है, जो सिविल अपील क्रमांक 5854/1994 कु. माधुरी पाटिल विरुद्ध एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेवलपमेंट महाराष्ट्र राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02/09/2014 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं है। प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष, जाँच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत निर्णय हेतु रखा जायेगा। (ड.) जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस जाँच उपरांत छानबीन समिति द्वारा निर्धारित जाँच प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही में समय लगना संभावित है। समय सीमा बतलाई जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र बमोरी एवं गुना में इंटर स्कूल खोला जाना

61. (क्र. 2287) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले की विधानसभा बमोरी एवं गुना के प्राथमिक, माध्यमिक एवं इन्टर स्कूलों में पर्याप्त स्टाँफ (प्राचार्य, अध्यापक, चपरासी) कार्यरत है? यदि नहीं तो कितने स्कूलों में कमी है? (ख) क्या गुना जिले के संकुल केन्द्रों के प्रभारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से जूनियर सेवा के है? यदि हाँ तो उन्हें कब तक बदलेगें एवं क्या जिला शिक्षा एवं ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक अटैच होकर कार्यरत हैं, उन्हें कब तक पदस्थापना वाले स्कूलों में वापिस भेजेंगे? (ग) क्या गुना एवं बमोरी विधानसभा में नवीन

इन्टर (10वीं एवं 12वीं) स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ तो बतायें कि कितनी संख्या एवं कितनी दूरी पर नवीन स्कूल खोलने का प्रावधान है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 22 संकुल केन्द्रों में से 04 संकुल केन्द्रों के प्रभारी जूनियर है। इनमें से 03 संकुल केन्द्रों में सीनियर शिक्षकों द्वारा संकुल का प्रभार लेने में असमर्थता व्यक्त करने में तथा एक संकुल केन्द्र में वरिष्ठ अध्यापक की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जूनियर वरिष्ठ अध्यापकों को प्रभार सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कोई अध्यापक अटैच नहीं हैं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कराये गये कार्य

62. (क्र. 2304) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 में कराये गये कार्यों जैसे सी.सी. निर्माण कार्य, विद्युतीकरण कूप निर्माण, सामुदायिक भवन एवं विभाग द्वारा संचालित समस्त प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या बतावें? (ख) क्या सिवनी जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा की गई है? अतः उनकी समीक्षा एवं जाँच जिला स्तर के अधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा करायी जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो जाँच द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं ठेकेदारों पर कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक तथा प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम वासियों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।

अमानक दवाईयों का क्रय

63. (क्र. 2313) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला स्तर पर खुले बाजार से क्रय की जाने वाली दवाईयों की गुणवत्ता के मापदण्ड क्या है? एवं उनको सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जाते हैं? (ख) क्या क्रय की गई दवाईयां पहले किसी अधिकृत लैब में प्रमाणित होने के पश्चात ही रोगियों में वितरित की जाती हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या नियम हैं एवं दवाईयां कौन-कौन सी लैब में टेस्ट करवाई जाती हैं? उनके नाम एवं पते सहित जानकारी दें? (ग) यदि हाँ, तो कोष एवं लेखा की आडिट रिपोर्ट एवं शासकीय लैब की रिपोर्ट के अनुसार दवाईयों को बिना लैब में

टेस्ट करवाये रोगियों एवं बच्चों में क्यों वितरित किया गया है? (घ) क्या सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर परिजनों को मुआवजा प्रदान करेगी? क्या अमानक दवाईयां क्रय करने वाले अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सागर अंतर्गत विद्यालयों में खेल मैदानों का उन्नयन

64. (क्र. 2346) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर के विद्यालयों में जहाँ-जहाँ खेल मैदान हैं, उनके उन्नयन के लिये शासन की क्या योजना है? क्या रख-रखाव के अभाव में वह अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं? क्या शासन इनके उन्नयन के लिये आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगा? (ख) सागर नगर के खेल परिसर में स्थित जिननिशियम संचालित हैं क्या शासन स्तर पर इसके उन्नयन हेतु कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) खेल मैदान के उन्नयन हेतु मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में खेल मैदान के निर्माण एवं सुदृढीकरण तथा खेल उपकरण, खेल सामग्री क्रय करने के संबंध में नीति 2015 लागू है। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) सागर जिले के खेल परिसर में स्थित जिमनिशियम शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित नहीं है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शामगढ़ के अपूर्ण छात्रावास के कार्य को पूर्ण किया जाना

65. (क्र. 2368) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के शामगढ़ नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन निर्माण हेतु किस वर्ष कितनी राशि स्वीकृत की गई, तथा छात्रावास भवन का कितना निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है? स्वीकृत राशि में से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? (ख) शासन के लाखों रुपये खर्च करने के पश्चात भी भवन आज तक अनुपयोगी है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? (ग) निर्माण कार्य कितने वर्षों से बंद पड़ा है, तथा क्यों बंद पड़ा है? निर्माण कार्य विलंब हेतु संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) अपूर्ण भवन कब तक पूरा कर लिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, शामगढ़, जिला मंदसौर के भवन निर्माण हेतु राशि रु. 27.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। छात्रावास भवन के 04 कक्षाओं का

निर्माण कार्य छत स्तर तक तथा शेष भवन का कार्य कुर्सी स्तर तक पूर्ण है। राशि रु. 21.60 लाख व्यय हो चुकी है। (ख) भवन निर्माणाधीन है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रकरण होने से विलंब हुआ है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (ग) निर्माण कार्य 04 वर्षों से बंद है। भवन के मूल स्वीकृत मानचित्र/डिजाइन से हटकर अतिरिक्त निर्माण कार्य किये जाने से निर्माण में विलंब हुआ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) निश्चित समय सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

स्कूलों में खेल सामग्री का प्रदाय

66. (क्र. 2369) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में खेलों एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये स्कूलों को जिम एवं खेलों की सामग्री कब प्रदाय की गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या सामग्री सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में किस-किस विद्यालय को जिम एवं खेल सामग्री प्रदाय की गई है? उनके नाम तथा सामग्री का विवरण दें? (ग) जिम की मशीनों को किस-किस स्थान पर फिट किया गया है एवं इनका उपयोग विद्यार्थियों के हित में किस-किस विद्यालय में हो रहा है? जिम का संचालन कौन कर रहे हैं? उनके नाम एवं पदनाम बतावें? (घ) जिन स्थानों पर जिम एवं खेल की सामग्री अनुपयोगी पड़ी है? सामग्री का उपयोग नहीं करने वाले संबंधितों के विरुद्ध शासन द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2014-15 में प्रदेश के 5 जिलों (नरसिंहपुर, बैतूल, मुरैना, छिंदवाड़ा, देवास) की 500 माध्यमिक शालाओं में यूनिसेफ के सहयोग से स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई गई। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में खेलों एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा कोई सामग्री प्रदाय नहीं की गई। (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय की गई सामग्री का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार प्रदायित किट का उपयोग किया जा रहा है।

क्षतिग्रस्त स्कूलों का निर्माण

67. (क्र. 2389) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल जनकगंज ग्वालियर के भवन का एक बड़ा हिस्सा माह सितम्बर 2014 में छात्रों के एक बड़े आयोजन के पूर्व गिर गया था? पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) क्या उक्त स्कूल के सम्पूर्ण भवन को डिसमेन्टल कर नया भवन बनाने हेतु शासन द्वारा राशि स्वीकृत की जा चुकी है? यदि हाँ तो कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हो सका? विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) उक्त विद्यालय के छात्रों के अध्यापन की व्यवस्था कहाँ की गई है? क्या उस स्थान पर सभी सुविधायें छात्रों को मुहैया कराई गई है?

पूर्ण जानकारी दी जावे? (घ) भवन का निर्माण कब तक, किस एजेन्सी से करवाया जावेगा? समय-सीमा निर्धारित की जावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मूल भवन लगभग 150 वर्ष से अधिक पुराना है। दिनांक 05.09.2014 को भवन का एक हिस्सा गिर गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन परिसर में नव निर्मित कक्षों को छोड़कर शेष भाग को अनुपयोगी घोषित करने की अनुशंसा की गई है। (ख) जी हाँ। शाला भवन डिस्मेंटल एवं निविदा जारी करने हेतु शासकीय प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अतः कोई जिम्मेदार नहीं है। (ग) कलेक्टर द्वारा विद्यालय छात्रों के अध्ययन की वैकल्पिक व्यवस्था पी.जी.व्ही. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लश्कर में की जाकर अध्ययनरत सभी छात्रों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। (घ) भवन निर्माण हेतु संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर को अधिकृत किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उज्जैन संभाग में संचालित छात्रावास

68. (क्र. 2413) डॉ. मोहन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उज्जैन संभाग में किन-किन स्थानों पर छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? उक्त छात्रावास में विभाग द्वारा कितनी-कितनी संख्या में छात्र-छात्राओं की संख्या अपेक्षित है, एवं वर्तमान में उनमें कितनी-कितनी संख्या में छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं? छात्रावास अनुसार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) में संचालित होने वाले छात्रावासों में कौन-कौन छात्रावास अधीक्षक किस दिनांक से पदस्थ है? विभाग में कार्यरत अधिकारियों के एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रहने के क्या नियम हैं? नियमों एवं निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराते हुये जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (क) में संचालित होने वाले छात्रावासों के संबंध में शासन द्वारा किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन जनवरी 2012 के पश्चात प्रदत्त किया गया? प्राप्त आवंटनों का किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया? छात्रावास अनुसार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम एवं आगर मालवा के आदिवासी मद से संचालित छात्रावासों में स्वीकृत सीट एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है। (ख) उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम एवं आगर मालवा के आदिवासी मद से संचालित छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षक/अधीक्षिका की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है। (ग) उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम एवं आगर मालवा के आदिवासी मद से संचालित छात्रावासों में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष

2014-15 का आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार है।

आदिवासी हितग्राहियों को अनुदान

69. (क्र. 2436) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में कितने आदिवासियों को कितनी अनुदान स्वरूप स्वीकृति की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने हितग्राहियों को सामान व पशु प्रदाय किये गए हैं? प्रदत्त पशुओं का चयन किसके द्वारा किया गया व सामग्री तथा पशुओं का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया? (ग) उक्त योजनान्तर्गत डीजल पंप कितने हितग्राहियों को दिया गया? पंप किस कंपनी का व कितने हार्स पावर का था? क्या पंप की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गयी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सिवनी जिले में 02 परियोजनाओं एवं 01 माडा पाकेट अन्तर्गत पिछले 05 वर्षों में (वर्ष 2009-2010 से 2013-14 तक) 10614 आदिवासियों को राशि रुपये 2123.22 लाख अनुदान स्वरूप स्वीकृत की गई। (ख) 3421 हितग्राहियों को पशु एवं 7193 हितग्राहियों को अन्य सामान प्रदाय किया गया। पशुओं का चयन हितग्राही द्वारा किया गया एवं पशुओं का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनादौन, छपारा, धन्सौर, धनोरा, कुरई, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि लखनादौन, सहायक भू-संरक्षण अधिकारी लखनादौन, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सिवनी, उप संचालक पशु चिकित्सा सिवनी, द्वारा किया गया। (ग) 2185 आदिवासी हितग्राहियों को डीजल पंप वितरित किये गये। उषा, किलोस्कर, इन्द्रामार्शल, वरुणा, टेक्समो, ग्रीव्स कंपनी के 2, 3, 4 एवं 5 हार्सपावर के डीजल पंप दिये गए। जी हाँ, पंप की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु कलेक्टर को लिखा गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित

70. (क्र. 2439) डॉ. मोहन यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कौन-कौन सी जातियों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, जानकारी प्रस्तुत करें? (ख) उपरोक्त जातियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु म.प्र. शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? (ग) अल्पसंख्यकों के लिये चलाई जा रही योजनाओं का वर्ष जनवरी 2010 से दिसम्बर 2015 तक उज्जैन जिले में किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजना का लाभ दिया गया, विवरण तहसीलवार प्रस्तुत करें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मध्यप्रदेश राज्य में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्ख, बुद्धिष्ट, पारसी एवं जैन समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। (ख) मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक

स्वरोजगार योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण योजना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सहयोग से अल्पसंख्यक पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति, मैरिट कम मीन्स, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास योजना (एमएसडीपी) आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। (ग) अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना वर्ष 2011-12 से लागू की है, जो कि वर्ष 2014-15 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (इसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों) लागू है, अल्पसंख्यक हितग्राहियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **परिशिष्ट - "उन्नीस"**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध खरीदी

71. (क्र. 2479) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2015 तक आर.सी.एच. सहित विभिन्न मर्दों में क्या-क्या बजट दिया गया? उसमें से किस-किस तिमाही में क्या-क्या खरीदी किन-किन संस्थाओं/एजेन्सी से किन-किन नियमों के तहत की गई? स्टेशनरी खरीदी सहित? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या सामग्री खरीदी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा बिना सामग्री खरीदी के भी बिलों का भुगतान किया गया? जो सामग्री खरीदी की गई वह भी घटिया किस्म की खरीदी गई? क्या एस.सी./एस.टी. फर्मों से भी खरीदी की गई या कोटेशन से खरीदी गई? (ग) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा नियम विरुद्ध खरीदी के संबंध में कलेक्टर उज्जैन द्वारा जाँच के आदेश दिये गये हैं? किस अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है? जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच में क्या पाया गया? (घ) क्या वर्तमान में उज्जैन जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ कितनी विभागीय जाँच प्रचलित है? कितनी बार इनका पदावनती की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला उज्जैन द्वारा 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2015 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मर्दों में बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'एक' अनुसार है। खरीदी गई औषधि एवं सामग्रीयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'दो' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'स' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। जी हाँ। (ग) जी हाँ। डॉ. कैलश बुन्देला, अपर कलेक्टर द्वारा जाँच सम्पादिक की जा चुकी है। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को म.प्र. वित्तीय संहिता एवं म.प्र. भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करना पाया गया है। (घ) वर्तमान में उज्जैन जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध राज्य स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रचलित नहीं है। एक बार भी पदावनती नहीं की गई।

स्कूल भवन, बाऊण्डीवाल, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था

72. (क्र. 2481) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितने स्कूलों की बिल्डिंग किचन शेड, अतिरिक्त कक्ष तथा बाऊण्डीवाल एवं शौचालय निर्माण किए गए एवं कितने स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की गई? सूची उपलब्ध करावें? (ख) इन निर्माण कार्यों पर कितनी -कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं किन-किन एजेंसी द्वारा कितनी -कितनी राशि खर्च की गई? सूची उपलब्ध करावें? कितने कार्य पूर्ण है? कितने कार्य अपूर्ण है? स्थानवार कार्य की स्थिति एवं अपूर्ण होने का कारण सहित बतायें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है।

अध्यापक संवर्ग को पेंशन एवं समूह बीमा योजना का लाभ

73. (क्र. 2503) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवकों के लिए लागू अंशदायी पेंशन योजना में अब तक कुल कितनी राशि कटौती के रूप में जमा की गई है? (ख) अंशदायी पेंशन योजना के तहत शासकीय सेवक की मृत्यु/त्यागपत्र देने उपरांत उसके स्वत्व के भुगतान हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है? अध्यापक संवर्ग योजना लागू होने के बाद से आज तक कितने अध्यापकों को स्वत्व की प्राप्ति हुई है? (ग) राज्य शासन के कर्मचारियों को प्राप्त पेंशन के समान वर्ष 2005 तक नियुक्त शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षकों को पेंशन योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस ओर विचार करेगा? (घ) क्या अध्यापक संवर्ग हेतु समूह बीमा योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) लगभग रूपये 949 करोड़। (ख) संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी की माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय को प्राप्त होता है। आवेदन पत्रों को परीक्षण NSDL eGIL (नेशनल सिक्यूरिटीय डिपॉजिटरी लिमिटेड ई गर्वनेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई) को अंतिम भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है। एन.एस.डी.एल. द्वारा परीक्षण उपरांत सीधे संबंधित के खाते में राशि जमा कराई जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय से एन.एस.डी.एल. मुंबई को कुल 70 प्रकरण अंतिम भुगतान हेतु भेजे गये हैं, जिनमें से 03 प्रकरण के स्वत्वों को

भुगतान किया जा चुका है, शेष 67 प्रकरण विचाराधीन है। (ग) नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत शाला भवनों का निर्माण

74. (क्र. 2504) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने शासकीय हाई स्कूल एवं उ.मा.वि. संचालित हैं? इनमें से कितने विद्यालय भवन युक्त एवं कितने भवन विहीन हैं? कृपया पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें? (ख) सुसनेर विधान सभा में कुल कितने शासकीय विद्यालय भवन विहीन एवं जर्जर स्थिति वाले भवन युक्त हैं? इन विद्यालयों को नवीन भवन स्वीकृति हेतु शासन के क्या मापदण्ड हैं? (ग) सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत शासकीय उ.मा.वि. सुसनेर, शा.उ.मा.वि. सोयतकलां एवं शा.क.उ.मा.वि. सोयतकलां के भवनों एवं उनमें शाला संचालन की क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शालाओं को नवीन भवन स्वीकृति संबंधी कोई मांग या प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है एवं कब तक भवन स्वीकृत होंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सुसनेर विधानसभा अंतर्गत 01 प्राथमिक 04 माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है। उक्त विद्यालयों का उन्नयन किया जाकर नये भवन स्वीकृत कर दिये गये हैं। 07 प्राथमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं। जीर्णशीर्ण एवं जर्जर शाला भवनों को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग से जीर्णशीर्ण एवं जर्जर तथा अनुपयोगी का प्रमाण पत्र देने के उपरांत भारत शासन से नवीन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। भवन निर्माण का प्रस्ताव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार की स्वीकृति तथा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुसनेर बालक प्राथमिक विद्यालय के भवन में संचालित है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोयतकला स्वयं के पुराने भवन में संचालित है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोयतकला, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या माध्यमिक विद्यालय सोयतकला के भवन में प्रातः पारी में संचालित है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शालाओं के निर्माण के संबंध में मांग प्राप्त हुई थी। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इनके भवनों की स्वीकृति अभी संभव नहीं है। इन शालाओं के भवन स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा का बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "बीस"

प्रदेश में एम्स की स्थापना

75. (क्र. 2529) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एम्स स्थापना के लिये अब तक क्या-क्या स्वीकृतियां, कार्यवाही बजट आवंटन हुआ? ब्यौरा क्या है? (ख) केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के स्थापना दिशा में अब तक क्या सहयोग किया? (ग) प्रदेश की जनता को एम्स की सुविधाओं का लाभ कब तक प्राप्त हो सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला संयोजक द्वारा अवैध नियुक्तियां

76. (क्र. 2560) श्री अजय सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री एल.आर. मीना तत्कालीन जिला संयोजक गुना, शिवपुरी, छतरपुर तथा प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी द्वारा विभिन्न पदों पर अवैधानिक रूप से दैनिक वेतन भोगी, दैनिक लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, भृत्य रसोइया, चौकीदार के पद पर नियुक्ति की गई है? (ख) यदि हाँ तो इन जिलों में नियुक्तियों की जाँच कर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच की गई है? आरोप पत्र विभागीय जाँच की प्रतियां दी जावें तथा क्या इन नियुक्तियों में इन कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के रिश्तेदार नियुक्त किये गये हैं? उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बतायें? यदि नियुक्ति अवैध है तो उन अधिकारियों/कर्मचारियों एवं श्री एल.आर. मीना तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त के विरुद्ध पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है यदि नहीं तो कब तक किया जायेगा? (ग) क्या श्री मीना द्वारा उक्त जिलों में कर्मचारियों का अवैधानिक स्थानान्तरण एवं अवैध नियमितीकरण किया गया है? यदि हाँ तो पदवार, नामवार विवरण दिया जावें तथा नियमित किये गये कर्मचारियों को पूर्व दिनांक से नियमितीकरण मान्य कर एरियर्स राशि का भुगतान किया गया है? यदि हाँ तो क्या श्री मीना एवं लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से इसकी वसूली की जाकर इन अवैध कृत्यों में शामिल विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं प्रपत्र 'स' अनुसार है। श्री मीना को निलंबित कर आरोपपत्र किये गये हैं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शिवपुरी व सीधी जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' एवं 'ई' अनुसार है, शेष जिलों में जानकारी निरंक है।

फर्जी प्रमाण पत्रों की जाँच

77. (क्र. 2561) श्री अजय सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा श्री एल.आर.मीना आत्मज श्री वंशीलाल मीना तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी के अनुसूचित जनजाति के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जाँच हेतु गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति के पारित निर्णय दिनांक 11.10.2014 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र राजसात करने तथा विधि अनुरूप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है? (ख) यदि हाँ तो श्री मीना तत्कालीन सहायता आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी को सेवा से पृथक कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है या नहीं? (ग) यदि सेवा से पृथक नहीं किया गया तथा पुलिस से आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किये गये तो कब तक सेवा से पृथक किया जावेगा तथा पुलिस में कब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जावेगी? (घ) जब 11.10.2014 को समिति द्वारा पारित निर्णय में श्री एल.आर. मीना का जाति प्रमाण पत्र राजसात करने का निर्णय लिया गया था तब श्री मीना की पदोन्नति का आदेश दिनांक 17.10.14 का कैसे जारी किया गया? इस अवैधानिक कार्यवाही के लिए दोषी कौन है? दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। अपितु दिनांक 13/02/2014 को उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। (ख) सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जाकर सहमति हेतु प्रकरण म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। थाना सिरोंज जिला विदिशा में अपराध क्रमांक 50/2015 दर्ज किया गया है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) छानबीन समिति की बैठक दिनांक 13/10/2014 में लिये गये निर्णय को आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र क्रमांक/जा.प्र.समिति/720/2011/23829 दिनांक 02/12/2014 के द्वारा जारी किया गया। उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होने से पूर्व श्री एल.एन. मीना की पदोन्नति से संबंधित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17/07/2014 को सम्पन्न हुई तथा विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश दिनांक 17/10/2014 को जारी किये गये। इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

सीहोर जिले की घटित जाति को आरक्षण का लाभ

78. (क्र. 2568) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में घटिया (घट्टे/घट्टी) जाति निवास करती है? क्या इन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है? अगर नहीं तो क्यों? सूची में शामिल करने हेतु क्या प्रयास किये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इस जाति को सरकार की किन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों? (ग) सीहोर जिले में इनकी जनसंख्या कितनी है? कहाँ-कहाँ निवासरत हैं? (घ) सीहोर जिले में यह क्या कार्य कर रही है? इस जाति में साक्षरता का कितना प्रतिशत है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) अधिसूचना क्रमांक: 6209-25 (सा) -आई.के.-63, दिनांक 21 सितंबर, 1963 द्वारा जारी अधिसूचना में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की सूची में घटिया (घट्टे/घट्टी) जाति नहीं है। **सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उक्त जाति को शामिल करने हेतु जिला स्तर से कोई प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की सूची में उक्त जाति सम्मिलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- "इक्कीस"

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालापीपल के भवन की मरम्मत

79. (क्र. 2578) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कालापीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या नवीन भवन बनने तक वर्तमान भवन का मरम्मत का कार्य किया जा सकता है? (ख) सी.एच.सी. भवन कालापीपल के मरम्मत कार्य के किस-किस के प्रस्ताव संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु क्या प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (ग) प्रश्नांश (क) में प्राप्त मरम्मत कार्य के प्रस्तावों को प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं दी गई? क्या विभाग द्वारा भवन का मरम्मत कार्य आवश्यक नहीं समझा जा रहा है? (घ) क्या सी.एच.सी. भवन का कालापीपल के मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन दिया जावेगा कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, भवन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। वर्तमान भवन का मरम्मत कार्य प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ, सी.एच.सी भवन कालापीपल के मरम्मत हेतु (1) पुरुष जनरल वार्ड नर्स इयुटी रूम का रिनोवेशन कार्य (2) मेटरनिटी वार्ड लेबर रूम का रिनोवेशन कार्य (3) पेवर ब्लॉक का कार्य एवं (4) वाटर प्रूफिंग के कार्यों के प्रस्ताव दिनांक 02.09.2014 को प्राप्त हुये हैं। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन कालापीपल के मरम्मत कार्य हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक 5/भवन/2014-15/329 दिनांक 13.2.2015 द्वारा तथा वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु पत्र क्रमांक 5 /भवन/2014-15/2415 दिनांक 29.09.2014 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कालापीपल एवं पोलाय कलां में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति

80. (क्र. 2579) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल एवं पोलाय कलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

हेतु कितने-कितने पद चिकित्सकों के लिये स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कौन-कौन कार्यरत हैं? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालापीपल एवं पोलाय कलां में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है? अगर रिक्त है, तो उक्त केन्द्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ का कार्य किससे लिया जा रहा है? (ग) क्या ग्रामीण महिलाओं को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इस हेतु कालापीपल एवं पोलाय कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जावेगी? तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। पदस्थ चिकित्सकों द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य किया जाता है। (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरुद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में शतप्रतिशत विशेषज्ञों के पदों पर पदस्थापना नहीं की जा सकी है, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "बाईस"

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में अनियमितताएं

81. (क्र. 2593) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डही में निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन में आ रही बाधाओं से शासन को अवगत करवाया गया था? (ख) शासन द्वारा कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डही में निर्माण कार्य कितनी लागत से, किस एजेंसी एवं ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है? तकनीकी स्वीकृति सहित विस्तृत जानकारी प्रदान करें? (ग) शासन द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र में निर्माण कार्य पूर्ण करने की क्या समय सीमा तय की गयी थी? (घ) शासन द्वारा उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा (समय सीमा बतायें) एवं कार्य विलंब में दोषी कौन-कौन है और दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। (ख) लागत राशि रुपये 144.56 लाख, लोक निर्माण विभाग, संभाग धार एवं ठेकेदार श्री मगन सिंह भाटिया सिंघाना द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, परंतु कार्य की संतोषजनक प्रगति न होने के कारण दिनांक 12.02.2015 को अनुबंध निरस्त कर दिया

गया। शेष कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 157.51 लाख है। (ग) 16 माह की अवधि। (घ) यथा शीघ्र, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विलंब के लिये ठेकेदार श्री मगनसिंह भाटिया सिंघांना दोषी है, उनका ठेका निरस्त कर दिया है एवं अनुबंधानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।

कुक्षी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्य

82. (क्र. 2595) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-2015 में परियोजना मद से कुक्षी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से विकास कार्य किये जाने थे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से विकास कार्य अप्रारंभ, अपूर्ण और पूर्ण है? कार्यों को पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा क्या समयसीमा तय की गयी थी? (ग) क्या क्रियान्वयन एजेंसीयों के कार्य अप्रारंभ है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा दोषियों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्या कारण स्पष्ट करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी कार्य अप्रारंभ हैं। कार्य पूर्ण होने की समय सीमा आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त एक वर्ष नियत है। (ग) जी हाँ। निर्वाचन आदर्श आचारण संहिता प्रभावशील होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- "तेईस"

शालाओं का उन्नयन

83. (क्र. 2615) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक दिमनी द्वारा विधानसभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक कितने आवेदन प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से हाईस्कूल व हाईस्कूल व हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी के उन्नयन हेतु एवं दूरस्थ अंचलों में शाला विहीन ग्रामों में प्राथमिक नवीन विद्यालय खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो आवेदन पत्रों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राथमिक से माध्यमिक उन्नयन हेतु 03 एवं दूरस्थ अंचलो में शाला विहीन ग्रामो में प्राथमिक नवीन विद्यालय खोलने हेतु 01 आवेदन पत्र। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जिला स्तर पर छात्रावास की स्थापना

84. (क्र. 2616) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 50 में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये जिला स्तर पर 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास तथा 50 सीटर कन्या छात्रावास की स्थापना की जानी है? (ख) यदि हाँ, तो जिला मुरैना में अभी तक उपरोक्त वर्णित प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या-क्या गतिविधियां हुईं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) मुरैना जिले में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं 50 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की स्थापना की जा चुकी है।

कर्मचारियों का नियमितकरण

85. (क्र. 2627) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग में सन् 01.01.1990 से कार्यरत आकस्मिक निधि भृत्य कब तक नियमित स्थापना पद पर नियुक्त किये जायेंगे? (ख) इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी के नियमित पद पर स्थापना की शासन की क्या योजना है? (ग) उपरोक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी भविष्य में किस प्रकार नियमित होंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आकस्मिक निधि से वेतन पान वाले भृत्यों की नियुक्ति उनके निर्धारित सेवा भर्ती नियमों के तहत की जाती है, इन्हें नियमित सेवा में समायोजित/नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः नियमित पदस्थापना में नियुक्ति करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) शासन की कोई योजना नहीं है। (ग) आकस्मिक निधि अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-3/2006/1-3, दिनांक 16.05.07 एवं 08.02.08 द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अकिस्मिकता निधि सेवा के स्वीकृत पदों पर रोस्टर का पालन करते हुये आकस्मिक निधि सेवा का सदस्य घोषित करते हुये नियमित किये जाने का प्रावधान है।

विभागीय पत्र व्यवहार व विकास प्रस्तावों पर कार्यवाही

86. (क्र. 2650) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जिला खरगोन को प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2014-15 में कितने पत्र दिए गये विषयवार सूची दें? इन पत्रों के जबाब कब दिए गये उनकी पूर्ति उपलब्ध करावें? (ख) आदिवासी बस्ती विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सूची 2014-15 की दें? प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु भेजे गये पत्रों की प्रति दें? प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) छात्रावास अधीक्षक का कार्यकाल एवं स्थानांतरण

संबंधी कोई समयावधि तय है? क्या संविदा शिक्षक छात्रावास अधीक्षक बन सकता है? नियम की प्रति देवें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ख) पत्र की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है तथा कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। शासन नीति दिनांक 22.08.2013 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है।

वन ग्राम धार एवं बरेठा में वन अधिकार पत्र धारकों की अर्जित भूमि का मुआवजा

87. (क्र. 2718) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के वनग्राम धार एवं बरेठा में वन अधिकार पत्र धारकों की फोर लेन हेतु अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा वन अधिकार पत्र धारकों को दिए जाने का प्रकरण बनाए बिना ही वन भूमि व्यपवर्तन का प्रकरण अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है? (ख) वनग्राम बरेठा एवं धार की ग्रामसभाओं ने फोरलेन हेतु अर्जित की जा रही भूमि एवं मकान के संबंध में किस दिनांक को क्या-क्या निर्णय लिया है? वन विभाग द्वारा मुआवजा एवं पुनर्वास बाबत किस दिनांक को लिखे गए पत्र कलेक्टर बैतूल को प्राप्त हुए हैं? (ग) किस वन अधिकार पत्र धारक की कितनी भूमि उस पर निर्मित मकान/दुकान अर्जित किया जा रहा है? इनका एन.एच.ए.आई. ने क्या मूल्यांकन प्रस्तुत किया है? मकान एवं दुकान के नवनिर्माण की लागत प्रस्तावित न किए जाने पर जिला स्तरीय समिति ने किस दिनांक को क्या कार्यवाही की? (घ) वन अधिकार पत्र धारकों को मुआवजा भुगतान या वैकल्पिक भूमि दिलवाए बिना वनभूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही किए जाने का क्या कारण है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) ग्रामसभा बरेठा द्वारा दिनांक 19.9.2014 को पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित सम्पतियों का उचित मुआवजा प्रदाय किये जाने का उल्लेख है। ग्रामसभा धार का प्रस्ताव अप्राप्त है। वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल उत्तर (सा.) बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक 7626 दिनांक 7.9.2014 द्वारा वनग्राम धार एवं बरेठा के किसानों की कृषि भूमि, मकान, दुकान प्रभावित हो रहे हैं, इनका मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान तथा व्यवस्थापन से संबंधित कार्यवाही हेतु कलेक्टर बैतूल को दिनांक 10.9.2014 को प्राप्त हुआ है। (ग) फोरलेन निर्माण हेतु व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि में वनग्राम धार के 20 पट्टाधारियों की कुल 2.105 हेक्टेयर भूमि, उस पर निर्मित मकान/दुकान तथा वनग्राम बरेठा के 2 पट्टाधारियों की 0.130 हेक्टेयर भूमि उस पर निर्मित मकान/दुकान प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिये एन.एच.आई.ए. ने उनके पत्र क्रमांक/5715, दिनांक 10.9.2014 द्वारा राशि रुपये 1,06,00, 581/- का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

एन.एच.आई.ए. के द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन से वन ग्राम बरेठा एवं धार के ग्रामीणों के द्वारा उठाई गई आपत्ति से एवं वन मण्डल उत्तर (सा.) बैतूल की असहमति से महाप्रबंधक (तक.) सह परियोजना निदेशक एन.एच.आई.ए. भोपाल को पत्र क्रमांक 8339 दिनांक 20.10.2014 से अवगत कराते हुए वस्तुस्थिति आधारित मुआवजा निर्धारित कराने एवं ग्रामसभा से अनुमोदन कराने हेतु लेख किया गया है तथा यूजर एजेन्सी को नव निर्माण की लागत का पत्रक प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर बैतूल के पत्र क्रमांक 557 दिनांक 6.2.2015 द्वारा लिखा गया है। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है।

कौशल विकास योजना अंतर्गत आवंटन

88. (क्र. 2763) श्री शान्तिनाथ बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति के युवकों के कौशल विकास अंतर्गत विभाग द्वारा कितना आवंटन जिले में प्रदाय किया गया था? (ख) झाबुआ जिले में आदिवासी विकास विभाग में किस कंपनी से इसके लिए एमओयू हुआ था? एमओयू अनुरूप कौन-कौन से ट्रेडों में जिले के युवकों को कहाँ-कहाँ, कितनी संख्या में प्रशिक्षण दिया गया एवं इस पर कितना व्यय एमओयू अनुसार हुआ वर्षवार विवरण दें? (ग) प्रशिक्षण प्राप्त युवकों में से एमओयू अनुसार कितने युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ और कहाँ-कहाँ विवरण दें? (घ) यदि एमओयू अनुसार अनुसूचित जनजाति युवकों को रोजगार नहीं दिया गया तो उस कंपनी के विरुद्ध एमओयू अनुसार क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांकित अवधि में कौशल विकास मद अंतर्गत 21.98 लाख का आवंटन झाबुआ जिले को प्रदाय किया गया था। जिला झाबुआ में उक्त राशि का आहरण नहीं किया गया था। शासकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र झाबुआ जिले के लिये निम्नानुसार आवंटन दिया गया -

वर्ष	आवंटन (राशि लाखों में)	विवरण
2013-14	30.00	व्हीटीसी झाबुआ हेतु
2014-15	20.00	व्हीटीसी झाबुआ एवं पेटलावद जिला झाबुआ हेतु

(ख) प्रश्नांकित 'क' में उल्लेखित अवधि में झाबुआ जिले में इसके लिए एमओयू नहीं किया गया था। (ग) एवं (घ) उक्त अवधि में उपरोक्त 'ख' के संदर्भ में निरंक।

विभागीय कर्मचारियों का संविलियन

89. (क्र. 2787) श्री कमलेश शाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला एवं विकलांग कर्मचारियों के अंतर्जिला संविलियन के प्रावधान संविदा शिक्षकों के लिये भी समान है या भिन्न हैं? स्पष्ट करें? (ख)

विगत 05 वर्षों में ऐसे कितने संविदा शिक्षकों का संविलियन किया गया? वर्षवार बतावें? (ग) यदि (क) अनुसार संविलियन नहीं होता है, तो कब से होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला, निःशक्तजन तथा पारस्परिक अन्तर्जिला एवं जिलान्तर्गत केवल जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अन्तर्गत एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रावधान है। संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा छानबीन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को अन्तर्जिला संविलियन की पात्रता नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरवाड़ा में स्वीकृत निर्माण कार्य

90. (क्र. 2796) श्री कमलेश शाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र अमरवाड़ा में स्वीकृत निर्माण कार्य जो बी.आर.सी. के अधीन हो, की सूची दें? विगत 01 वर्ष के कार्यों की स्वीकृति दिनांक, लागत, कार्य पूर्णता दिनांक, स्थान नाम सहित दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में कितनी राशि का आहरण किया जा चुका है और कितने प्रतिशत कार्य इसके समक्ष हुए हैं? कार्यानुसार पृथक-पृथक बतावें? (ग) क्या शासन से राशि (बजट) आवंटन के अभाव में ये कार्य रुके हुए या अप्रारंभ हैं? यदि हाँ, तो फिर इनकी स्वीकृति क्यों दी गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में विगत 1 वर्ष (2013-2014) में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट में कटौती

91. (क्र. 2814) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय संकट के चलते राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट में कटौती कर इसका पैसा सिंहस्थ मेले के निर्माण कर्यों, राज्य मार्गों की मरम्मत एवं सुधार तथा पुलों के निर्माण के लिए आवंटित कर दिया? (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और बजट में कमी से उपयोजना के विभिन्न मदों में खर्च पर क्या असर पड़ेगा? (ग) वित्त वर्ष 2014-2015 में अनुसूचित जाति उपयोजना के मद में कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में

प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति उपयोजना मद अंतर्गत बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- "चौबीस"

मध्यप्रदेश में रोजगार की स्थिति

92. (क्र. 2816) श्री मुकेश नायक :क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के सरकारी और गैरसरकारी संगठित क्षेत्र में वर्ष 2010 से दिसम्बर 2014 तक वर्षवार रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या क्या थी? (ख) मध्यप्रदेश में सरकारी क्षेत्र में तथा गैरसरकारी संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की क्या नीति है और पिछले पाँच वर्षों में राज्य में रोजगार अवसर बढ़ने या घटने के मुख्य कारण क्या थे? (ग) पिछले पाँच वर्षों में राज्य के रोजगार कार्यालयों में रोजगार पाने के इच्छुकों की दर्ज संख्या तथा इन वर्षों में रोजगार कार्यालयों द्वारा दिलाये गये रोजगार की संख्या वर्षवार प्रदान करें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मध्यप्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजन क्षमतानुसार श्रमिकों की संख्या वर्षवार निम्नवत है :- 1. वर्ष 2010 - 759846, 2. वर्ष 2011 - 777512, 3. वर्ष 2012 - 793439, 4. वर्ष 2013 - 822433, 5. वर्ष 2014 - 832841, (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों की वेतनवृद्धि

93. (क्र. 2839) डॉ. गोविन्द सिंह :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शिक्षाकर्मियों योजना कब प्रारम्भ हुई? योजना प्रारम्भ के समय तथा वर्तमान स्थिति में अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्यों को कितना-कितना वेतन भत्ता दिया जा रहा है? (ख) सम्पूर्ण म.प्र. में अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्यों की वर्तमान में जिलेवार कितनी-कितनी संख्या है? बतायें? (ग) तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता को पत्र क्रमांक 307 दिनांक 3.2.2011 द्वारा अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्यों के वेतन बढ़ाने की कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव वित्त को निर्देश दिये थे? यदि हाँ तो अभी तक वेतन वृद्धि न करने का कारण बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) दिनांक 30.07.1994 से योजना प्रारंभ के समय अंशकालीन लिपिक को रूपये 400/- प्रतिमाह एवं अंशकालीन भृत्य को रूपये 300/- प्रतिमाह तथा वर्तमान स्थिति में अंशकालीन लिपिक को रूपये 2000/- प्रतिमाह एवं अंशकालीन भृत्य को रूपये 1600/- प्रतिमाह वेतन भत्ता दिया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट- "पच्चीस"

औपचारिकेत्तर केन्द्र में अनुदेशकों के लिए परीक्षा

94. (क्र. 2870) श्री नथनशाह कवरेती :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औपचारिकेत्तर केन्द्र में वर्ष 2008 में अनुदेशकों के लिए परीक्षा ली गई थी? यदि हाँ, तो इसमें छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत जुन्नारदेव विधान सभा क्षेत्र के कितने व्यक्तियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की? (ख) क्या इन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कर दी जायेगी? समय सीमा बतायें? (ग) क्या यह भी सही है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी अनुदेशक के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है? इसके लिए कौन दोषी हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। 14 अनुदेशकों द्वारा। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 04-01-2010 एवं विभागीय आदेश दिनांक 14-05-2010 के अनुक्रम में अर्हता पाये जाने पर 05 अनुदेशकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। शेष 09 अभ्यर्थियों को अर्हता पूर्ण न करने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सहायक शिक्षक/लिपिक वर्ग की वेतन वृद्धि

95. (क्र. 2872) श्री नथनशाह कवरेती :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अंतर्गत वर्ष 1994 से सहायक शिक्षक/निम्न श्रेणी लिपिकों की अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है, वेतन वृद्धि हेतु दोनों संवर्गों को बी.एड.बी.टी.आई./हिंदी मुद्रलेखक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वेतन वृद्धि की पात्रता की शर्तें लगाई गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1999 के अनुसार शासन आदेश अनुसार नियुक्ति दिनांक से वेतन वृद्धि की पात्रता हेतु कोई आदेश निकाला गया था? आदेश की प्रति संलग्न करें? (ग) यदि हाँ, तो अब नियुक्ति दिनांक से शासन आदेश अनुसार प्रशिक्षण बी.एड.बी.टी.आई./हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा से छूट प्रदान कर कर सहायक शिक्षक/लिपिक संवर्ग को वेतनवृद्धि प्रदान कर दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक सी/3-4/94/03/एक भोपाल, दिनांक 10 जून 94 के अनुसार सहायक शिक्षकों की अनुकम्पा नियुक्ति में बी.एड.बी.टी.आई. प्रशिक्षित होने की कोई शर्त नहीं रखी गई है। निम्न श्रेणी लिपिकों के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त स्व.शासकीय सेवक की विधवा को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का कोई बंधन नहीं रखा गया है शेष आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने में टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त लगाने के निर्देश है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्रावासों में क्रय सामग्री की जाँच

96. (क्र. 2889) श्री महेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रों एवं छात्राओं के कितने रहवासी कितने छात्रावास स्वीकृत व चालू हैं स्थानवार जानकारी दें? (ख) छात्र व छात्राओं को कौन-कौन सी सुविधाएँ शासन द्वारा दी जाती है, छात्रावासों में कौन-कौन सी सामग्री शासन द्वारा खरीद कर उपलब्ध कराई जाती है, सामग्रीवार बतावें व उसमें कितनी राशि वर्ष 2012, 13, 14 में व्यय की गई है? (ग) उक्त सामग्री किसके द्वारा क्रय की जाती है क्या सामग्री क्रय करते समय समिति का गठन किया जाता है यदि हाँ तो समिति सदस्य कौन-कौन को बनाया जाता है? (घ) क्या वर्ष 2012, 13, 14 में जो सामग्री छात्रावासों के उपयोग के लिए क्रय की गई है वह घटिया एवं निम्न स्तर की है जिसका समिति से मूल्यांकन न कराकर अपने स्तर से सामग्री का उपयोग कर लिया गया है ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जाँच मौके पर संयुक्त दल से निरीक्षण कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला पन्ना गुनौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन 01 आदिवासी बालक आश्रम धनगढ़ में स्वीकृत एवं संचालित है। (ख) छात्रावास/आश्रम में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाती है। छात्रावास/आश्रमों में दी जाने वाली सामग्री की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार खरीदकर उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में रूपए 03,54,220/-, वित्तीय वर्ष 2012-13 में रूपए 18,89,990/-, वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपए 42,37,255/-, (ग) विभागीय छात्रावास/आश्रमों के लिये सामग्री का क्रय पालक समिति के माध्यम से किये जाने के निर्देश है, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-11/2013/25-2/1472 दिनांक 27/06/2013 एवं म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के संशोधन आदेश क्रमांक एफ-12-11/2013/25-2/699 दिनांक 13/06/2014 द्वारा स्थानीय स्तर पर छात्रावास/आश्रम पालक समिति के गठन के निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 में क्रय की गई सामग्री घटिया एवं निम्न स्तर की नहीं है। सामग्री की गुणवत्ता का मूल्यांकन/परीक्षण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किये जाने एवं गुणवत्ता युक्त पाये जाने पर सामग्री मान्य कर उपयोग की गई है, फलस्वरूप कोई

अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। उक्त अवधि में कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट- "छब्बीस"

विधानसभा क्षेत्र गुनौर में विद्यालयों की संख्या

97. (क्र. 2895) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गुनौर के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च. माध्यमिक विद्यालयों की कितनी संख्या है, स्वीकृत स्थानवार बतावें? (ख) विद्यालयों में छात्र अनुपात के अनुसार बैठने की व्यवस्था है? यदि नहीं है तो किन-किन विद्यालयों में ऐसी स्थिति निर्मित है, स्थानवार बतावें तथा विद्यालयों में खेल परिसर है यदि हाँ तो कितने विद्यालयों में है और कितने विद्यालयों में नहीं है? (ग) उक्त ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें विद्युतीकरण कनेक्शन है? जिनमें नहीं है उनकी जानकारी दें? (घ) प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कितनी संख्या है? इनमें से स्वयं की कितनी शासकीय जमीन पर भवन निर्मित व संचालित है ऐसे कितनी स्कूली भूमि है जिनमें अन्य किसी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? क्या शासन उक्तानुसार भवनों परिसरों या विद्युतीकरण का कार्य करेगा तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब तक करावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विधानसभा गुन्नौर के अंतर्गत 199 माध्यमिक शालाएँ संचालित है तथा 18 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, स्थलवार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 3 अनुसार है। (ख) विधानसभा गुन्नौर में संचालित 199 माध्यमिक शाला में से 142 शालाओं बैठक व्यवस्था छात्रानुपात में है। 57 शालाओं में बैठक व्यवस्था छात्रानुपात में नहीं है। 199 माध्यमिक शालाओं में से 91 शालाओं में खेल परिसर उपलब्ध है एवं 108 में नहीं है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 3 अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में संचालित 199 माध्यमिक शालाओं में से 39 में विद्युत कनेक्शन है एवं शेष 160 शालाओं में विद्युत कनेक्शन नहीं है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 3 अनुसार है। (घ) विधानसभा गुन्नौर में 506 प्राथमिक शालाएँ तथा 199 माध्यमिक शालाएँ संचालित है। इनमें से 705 शासकिय भूमि पर एवं निरंक निजी भूमि पर संचालित है। कुल संचालित विद्यालयों में से 67 शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण है एवं विद्युतिकरण का कार्य बजट की उपलब्धता पर किया जावेगा। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है विद्युतिकरण का कार्य बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व रिकार्ड खुरद-बुर्द करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

98. (क्र. 2907) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बुरहानपुर जिले में अनेक वक्फ संपत्तियों जैसे ग्राम एमगिर्द स्थित खसरा 149/2, 337/1, 527, 297/1 इसी तरह से ग्राम हमीरपुर खसरा नंबर 30, 22, 10 नियमातपुरा खसरा नंबर 527, आदि वक्फ संपत्तियों को तहसीलदार द्वारा निजी व्यक्तियों के नाम, नामान्तरण बटांकन के आदेश कर भू-अभिलेखों में वक्फ संपत्ति प्रविष्टि विलोपित कर निजी व्यक्तियों को वक्फ भूमियों का स्वामित्व दे दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त समस्त वक्फ संपत्तियों म.प्र.शासन के राजपत्र अनुसार वक्फ बोर्ड में पंजीयत है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा नामान्तरण बटांकन के आदेश निरस्त कर वक्फ सम्पत्ति के रूप में प्रविष्टि करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन अधिकारिताविहीन एवं पद का दुरुपयोग करने वाले तत्कालीन तहसीलदार बुरहानपुर के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा किये गये आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा की जा रही है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) तत्कालीन तहसीलदार, बुरहानपुर (वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर, जिला बड़वानी) के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

गंभीर रोगियों के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा की घोषणा का क्रियान्वयन

99. (क्र. 2908) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना, सिविल सर्जन एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का वादा किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि 100 दिन की अपेक्षा लगभग 400 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वादा पूरा करने में नाकाम रहे? (ग) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन-कौन दोषी है और यदि नहीं तो यह अवगत करावें कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना तथा सिविल सर्जन एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी तिथि सहित यह भी अवगत करावें कि घोषणा के बाद अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की और वर्तमान में किस स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 100 दिवसीय कार्ययोजना में डायलिसिस सेन्टर की स्थापना प्रस्तावित नहीं थी। सिविल सर्जन व अन्य रिक्त पदों को भरने हेतु 100 दिवसीय कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया था। (ख) जी नहीं। (ग) नियमित सिविल सर्जन की पदस्थापना हेतु विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-12-10/2014/17 /मेडि-3 दिनांक 10/11/2014 के द्वारा प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के 51 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त पदों को विभागीय राजपत्रित सेवाभर्ती नियमों में समाहित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, उक्त कार्यवाही उपरांत पदोन्नती के माध्यम से पद पूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में जिलों में प्रभारी सिविल सर्जन पदस्थ किए गए हैं। कोई दोषी नहीं है। डायलिसिस सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रचलन में है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के 1271 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किए जाने के उपरांत चयन सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। वर्ष 2014 में बंधपत्र के अनुक्रम में 167 स्नातक बंधपत्र चिकित्सक एवं 125 स्नातकोत्तर चिकित्सकों की पदस्थापना प्रदेश अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में किए जाने के आदेश जारी किए गए। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नती की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों हेतु विज्ञापन जून 2014 में जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के बाद चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

जीरापुर मेला स्थल पर निर्मित सी.सी. खरंजा निर्माण की लागत

100. (क्र. 2923) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जीरापुर में विगत दिनों मेला स्थल पर सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण करवाया गया है? (ख) उक्त कार्य की लागत राशि बतावें एवं किस निर्माण एजेंसी से कार्य करवाया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ (ख) स्वीकृत लागत रुपये 20.00 लाख एवं 4.00 लाख का कार्य निर्माण एजेन्सी आदिवासी विकास, धार एवं जनपद पंचायत नालछा है।

रेडियोलॉजिस्ट के पद की स्वीकृति

101. (क्र. 2996) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) इंदौर जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट स्वीकृत पदों से कितने अधिक रेडियोलॉजिस्ट कार्य कर रहे हैं? (ग) जो रेडियोलॉजिस्ट स्वीकृत पदों से अधिक कार्य कर रहे हैं उनकी मूल पदस्थापना कहाँ है? (घ) इंदौर जिले में रेडियोलॉजिस्ट के कितने पद रिक्त हैं, तथा कितने अन्य स्थान पर आसंजित हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 01 पद स्वीकृत है। (ख) 01 अतिशेष में डॉ. कीर्ती चतुर्वेदी, रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत है। (ग) डॉ. कीर्ती चतुर्वेदी, रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, इंदौर है एवं वे जिला चिकित्सालय इंदौर में सेवायें प्रदान कर रही हैं। (घ) इंदौर जिले में रेडियोलॉजिस्ट का एक पद स्वीकृत है एवं 01 विशेषज्ञ कार्यरत है, शेष जानकारी उत्तरांश "ग" अनुसार।

प्रधानाध्यापक के पदों की पूर्ति

102. (क्र. 2997) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में प्रधानाध्यापक प्रा.वि. के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों की पूर्ति के लिये पदोन्नति कब तक की जावेगी? (ख) इंदौर जिले में प्रधानाध्यापक मा.वि. के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों की पूर्ति के लिए पदोन्नति कब तक की जावेगी? (ग) ए.ई.ओ. के पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी? (घ) इंदौर जिले में उ.श्रे.शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं? विषयवार संख्या देवें रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत के अन्तर्गत छात्र संख्या के मान से प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का कोई पद रिक्त नहीं है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मान. न्यायालय के निर्णयों के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलित है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पदपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "सत्ताईस"

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) का संचालन

103. (क्र. 3003) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कहाँ-कहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट भवन) की स्थापना की गई है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) में स्थापित किए गए संस्थानों में कहाँ-कहाँ भवन बनकर तैयार हो गए हैं? अवधि बताएं? (ग) क्या स्थापित

डाइट भवनों में डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? शासन कब तक स्थापित डाइट भवनों में डी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ कराएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) डाइट उज्जैन, शाजापुर, देवास, पिपलौदा, मंदसौर में डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित है। एन.सी.टी.ई.- डब्ल्यू.आर.सी. की मीटिंग क्रमांक 216, दिनांक 12-13 फरवरी, 2015 के मिनिट्स अनुसार सत्र 2015-16 में, डाइट नीमच को डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता की अनुमति एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन 2014 के तहत दी गई है।

परिशिष्ट- "अट्ठाईस"

रतलाम में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण

104. (क्र. 3004) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 के बजट में रतलाम में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है? (ख) निर्माण कार्य किस एजेंसी को दिया गया है, तथा उसकी परियोजना क्या है एवं समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? (ग) निर्माण कार्य पूर्ण कर किस शैक्षणिक वर्ष से मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एम.पी.आर.डी.सी.) को निर्माण एजेन्सी बनाया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) फिलहाल बताया जाना संभव नहीं है।

चिकित्सकों के पदों की पूर्ति

105. (क्र. 3008) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई व विछुआ जिला छिन्दवाड़ा और उनके अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं? विशेषकर विकासखण्ड चौरई के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी भी चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में स्वीकृत 7 पदों के विरुद्ध केवल एक चिकित्सक पदस्थ होने से नागरिकों को चिकित्सा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई व विछुआ जिला छिन्दवाड़ा और उनके अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के अनुसार उनकी पदस्थापना कर चिकित्सा सेवाएं क्षेत्र के नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु विभाग एवं माननीय मंत्री जी को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ तो चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु किस स्तर से क्या सार्थक पहल की गयी हैं? अभी तक पदस्थापना न होने के क्या कारण है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक 1254) दिनांक 12.12.2014 के पूरक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने फरवरी 2015 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई व विछुआ जिला छिन्दवाड़ा और उनके अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने हेतु आश्वस्त किया था? तो चिकित्सकों की अभी तक पदस्थापना नहीं किये जाने के क्या कारण है? कब तक चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के अनुसार उनकी पदस्थापना कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं तथा 01 नियमित व 01 संविदा चिकित्सक कार्यरत हैं, उक्त अधिकारी चौरई में स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। शेष संस्थाओं में पदस्थ स्टाँफ द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। (ख) जी हाँ। विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की रिक्त पद की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है अतः पदस्थापना संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों की चयन सूची माह फरवरी 2015 तक प्राप्त होने की आशा थी, परंतु चयनित चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त न होने के कारण पदस्थापना संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना के संबंध में कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

छात्रवृत्ति एवं रोजगार मूलक योजनाएं

106. (क्र. 3012) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत बैतूल जिले में कितने स्कूलों में छात्रों/छात्राओं की कितनी छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में वितरित की, वर्षवार जानकारी दें? (ख) क्या विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना प्रारंभ की गई है? यदि हाँ तो इसके क्रियान्वयन हेतु क्या नियम हैं? (ग) योजना के प्रारंभ से लेकर माह दिस. 2014 तक बैतूल जिले में कितनी धनराशि आवंटित की गई एवं कितना व्यय किया गया?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना माह अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई है, योजना के प्रारंभ से लेकर माह दिसम्बर 2014 तक बैतूल जिले को 32.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई एवं रु. 7.53 लाख व्यय किया गया।

नागदा जं. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा कर्मचारियों की समय पूर्व दी गई सेवा निवृत्ति

107. (क्र. 3017) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु क्या निर्धारित है? इसके गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति दें? (ख) नागदा जंक्शन जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के श्रमिकों की जबरिया सेवानिवृत्ति पर शासन ने क्या कदम उठाये हैं? दि. 01-01-13 से 31-12-14 तक कितने श्रमिकों को निर्धारित आयु से पूर्व सेवानिवृत्ति किया गया? (ग) (ख) प्रश्न अनुसार ऐसे प्रकरणों में संबंधित जिला व राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा अनदेखी करने पर शासन ने इन पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो कब तक करेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अधिसूचना दिनांक 28.06.2014 द्वारा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। गजट नोटिफिकेशन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" पर है। (ख) ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज नागदा द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेश में सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.10.2014 द्वारा लागू मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अध्यादेश, 2014 के पश्चात अधिसूचना दिनांक 28.06.2014 द्वारा की गयी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष संबंधी प्रावधान प्रमाणित

स्थायी आदेशों में लागू हुआ है। उक्तानुसार अध्यादेश दिनांक 25.10.2014 के पश्चात दिनांक 31.12.2014 तक ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. (स्टेपल फायबर डिवीजन) में 9 तथा इंजीनियरिंग डिवीजन में 1 श्रमिक को निर्धारित आयु से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया है। विभाग द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित आयु के पूर्व सेवानिवृत्त करने की वैधता तथा इस संबंध में उन्हें देय सहायता संबंधी प्रकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद के रूप में श्रम न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 20.02.2014 को अधिनिर्णयार्थ संदर्भ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.06.2014 द्वारा मानक स्थायी आदेशों में सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से संशोधित कर 60 वर्ष की गयी थी किंतु ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा इसका पालन नहीं किये जाने के कारण सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, उज्जैन द्वारा पूर्व में ही दिनांक 07.08.2014 को प्रबंधन के विरुद्ध मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु 2 आपराधिक अभियोजन प्रकरण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायालय उज्जैन में दायर किये जा चुके हैं। तत्पश्चात मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अध्यादेश, 2014 के दिनांक 25.10.2014 से लागू होने के पश्चात निर्धारित आयु के पूर्व सेवानिवृत्त किये गये कर्मचारियों के संबंध में श्रम कार्यालय, उज्जैन द्वारा दिनांक 23.01.2015 एवं दिनांक 20.02.2015 को निरीक्षण किये गये हैं। जिनमें पाये गये उल्लंघनों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। (ग) प्रश्नांश ख के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के सामु. स्व. केन्द्र में निर्माण कार्य की जांच

108. (क्र. 3018) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के कस्बा झारड़ा के सामुदायिक स्वा. केन्द्र भवन की स्वीकृति दिनांक, लागत, कार्यपूर्णता दिनांक एवं निर्माण एजेंसी बतावें? (ख) (क) अनुसार कितनी राशि का आहरण किया जा चुका है? तिथिवार बतावें? (ग) क्या उपरोक्त कार्य की जांच विभागीय मंत्री जी के आदेश से की जा रही है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन का विवरण देवें? (घ) उपरोक्त (ग) अनुसार जाँच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के कस्बा झारड़ा के सामुदायिक स्वा. केन्द्र भवन की स्वीकृति दिनांक 15.09.2008 को एवं भवन निर्माण के कार्यादेश दिनांक 20.10.2011 को जारी हुये थे, लागत रुपये 211.97 लाख, कार्य पूर्णता दिनांक 18.02.2015 है एवं निर्माण एजेंसी स्वास्थ्य विभाग है। (ख) भवन निर्माण हेतु आहरित देयकों की कुल राशि रुपये 18075852/- का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र	तिथि	राशि (लाख में)
1	15.02.2012	2565574.00
2	26.03.2012	1235128.00
3	31.10.2012	645294.00
4	22.03.2013	2167996.00
5	02.08.2013	942668.00
6	13.02.2014	1988463.00
7	12.09.2014	1679666.00
8	16.10.2014	1901237.00
9	12.02.2015	4949826.00

(ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भर्तियों में अनियमितता की जाँच

109. (क्र. 3023) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग के अन्तर्गत दि. 01-01-2012 से 31-01-15 तक कितनी योजनाओं में कितने पदों पर कितनी नियुक्तियां विभाग ने की है? योजना नाम, पदनाम सहित माहवार, वर्षवार बतावें? (ख) सितं. 2014 में आर.एन.टी.पी.सी. कार्यक्रम के तहत संविदा पदों पर चयनित उम्मीदवारों के नाम, जिस पद पर चयन हुआ उसका नाम, शैक्षणिक योग्यता देवें? इस परीक्षा के चयनकर्ताओं के नाम, पदनाम सहित बतावें? (ग) चयन प्रक्रिया में अपात्र लोगों का चयन करने वाले चयनकर्ताओं पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) अनुसार बतावें? कितने उम्मीदवारों ने चयन उपरांत ज्वाइनिंग 31-01-15 तक नहीं दी है? उनकी नाम सहित सूची देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) सितम्बर 2014 में आरएनटीसीपी कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरने के कारण अपात्र लोगो का ऑनलाईन चयन हुआ है, अतः चयनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर संलग्न है।

कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाएं

110. (क्र. 3034) श्री उमंग सिंघार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योगों में कार्यरत कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं आवास जैसी सुविधायें दी जाती है? यदि हाँ, तो धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई है? (ख) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कितनी कंपनियों में 100 या 100 से अधिक कुशल/अर्धकुशल श्रमिक कार्यरत है? साथ ही बतायें कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कितने स्थानीय वेण्डरों को औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य दिये गये है? (ग) क्या यह सही है कि कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों से संबंधित जानकारी (नाम/पते) कंपनियों द्वारा संधारित की जाती है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल द्वारा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनाओं का लाभ श्रमिकों की कुशलता के आधार

पर प्रदान नहीं किया जाता है। धार जिले में वर्ष 2013-14 में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल द्वारा निम्नानुसार तालिका अनुसार-

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या	प्रदाय की राशि रु.
1.	शैक्षणिक छात्रवृत्ति	194	1, 56, 750/-
2.	शिक्षा प्रोत्साहन	256	3, 76, 250/-

योजनाओं में लाभ प्रदान किये गये है, चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं आवास संबंधी योजना नहीं होने से कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया। (ख) पीथमपुर आद्योगिक क्षेत्र में 42 कंपनियों में 100 या 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत है। स्थानीय वेण्डरों को कार्य दिये जाने संबंधी पंजीयन का प्रावधान किसी श्रम कानून में नहीं है। अतः जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) जी हाँ।

विद्युतीकरण राशि वितरण में अनियमितता

111. (क्र. 3035) श्री उमंग सिंघार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति क्षेत्रिय विकास योजनाओं द्वारा वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में कितनी राशि विद्युतीकरण योजना अंतर्गत जिलों को आवंटित की गई? जिलेवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) में आवंटित राशि किस आधार/मापदण्डों के आधार पर जिलों को आवंटित की गई? क्या यह सही है कि जिन जिलों में आदिवासी जनसंख्या कम है उन्हें ज्यादा राशि एवं जिन जिलों में आदिवासी जनसंख्या अधिक है उन जिलों को कम राशि क्यों दी गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में क्या आवंटित राशि में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी? प्राप्त शिकायतों की जाँच की गई या नहीं यदि हाँ, तो दोषी किसे पाया गया? यदि जाँच नहीं की गई तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी है? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जिलों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार राशि का आवंटन जारी किया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि राशि ऐसे जिलों को आवंटित की गई, जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, बल्कि राशि अनुसूचित जनजाति के लिए ही उन जिलों को जारी की गई है, जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए वास्तविक आवश्यकता तथा मांग थी। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। अंतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रजिस्ट्रार पद की अर्हता

112. (क्र. 3143) श्री चैतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाकौशल नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार पद की अर्हता क्या है, एवं इस पद की पूर्ति की क्या प्रक्रिया है? (ख) वर्तमान में पदस्थ रजिस्ट्रार क्या निर्धारित अर्हताधारी है? यदि नहीं, तो रजिस्ट्रार के पद के अर्हताधारी का चयन कर नियुक्ति कब तक की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार पद की अर्हता आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुसार एम.एस.सी. नर्सिंग 8 से 10 वर्ष का नर्सिंग शिक्षण एवं प्रशासनिक अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष शैक्षणिक कार्य का अनुभव आवश्यक है। इस पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा 35 से 50 वर्ष निर्धारित है। रजिस्ट्रार के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है। (ख) म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार के पद पर रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महाविद्यालयों में नर्सिंग पाठ्यक्रम का संचालन

113. (क्र. 3144) श्री चैतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किन-किन नर्सिंग पाठ्यक्रम से संबंधित शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय किस-किस शहर में संचालित हो रहे हैं? (ख) उक्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में कौन-कौन से अकादमिक पद सीधी भर्ती/पदोन्नति के स्वीकृत हैं, तथा इन पदों के विरुद्ध विद्यालय/महाविद्यालय वार कौन-कौन कार्यरत है, और कौन से पद रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक हो जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मझवार जनजाति का अध्ययन प्रतिवेदन और सामाजिक स्थिति

1. (क्र. 145) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जनजाति की वर्तमान व पूर्ववर्ती अनुसूची में मझवार को माझी से पृथक प्रविष्टियों में किन्हीं भिन्न क्षेत्रों के लिये मान्य किया गया है, जिससे दोनों जनजातियां पृथक अस्तित्व की बन गई है? (ख) क्या आदिमजाति अनुसंधान संस्था ने मझवार जनजाति का कभी किन्हीं जिलों के स्थानों में सीमित मानवशास्त्रीय अध्ययन और वैयक्तिक सर्वेक्षण (केसस्टडी) तैयार कर प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया है? (ग) क्या प्रश्नांश-"ख" में मझवार जनजाति की उत्पत्ति, गोत्र, टोटेम, धर्म (जीववादी/हिन्दी), देवी-देवता, जीवनचक्र (जन्म, विवाह, मृत्यु) के संस्कार (ब्राम्हण, नाई, धोबी, चमारिन, बसोरिन की सेवाओं और हिन्दू रीति-रिवाज-परम्पराओं सहित), वधुमूल्य, दहेजप्रथा, वैवाहिक संबंध, सामाजिक स्तर, बोली तथा परम्परागत प्रमुख व गौण पेशे आदि दर्शायी गयी है? (घ) क्या यह सत्य है कि राज्य में मझवार जनजाति के न पाये जाने के कारण उसका कोई अध्ययन नहीं किया गया है और फलस्वरूप क्या प्रश्नांश (ख) संस्था, विभाग और भारत सरकार को अनुसूची से विलोपित किये जाने हेतु कभी कोई अभिमत देगी? (ङ.) क्या यह सत्य है कि आ.जा.अ. संस्था द्वारा धीमर, कहार, भोई, केवट, कीर, मल्लाह आदि और मझवार जनजाति में साम्यता न पायी जाने के अभिमत दिये हैं? तब क्या वह प्रश्नांश-"क", "ख", "ग" के परिपेक्ष्य में अपने समस्त प्रतिवेदनों में से मझवार जनजाति के उल्लेखों को विलोपित करेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) पूर्ववर्ती अनुसूचित जनजाति अनुसूची में मझवार व माझी पृथक-पृथक क्रमांकों पर पृथक-पृथक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय बंधन के साथ अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 29 पर माझी एवं क्रमांक 30 पर मझवार अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्नउपस्थित नहीं होता। (घ) शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ङ) जी नहीं, अपितु धीमर, कहार, भोई, कीर, मल्लाह, आदि और माझी, मझवार जनजाति में साम्यता न पाये जाने संबंधी अभिमत दिये गये हैं।

स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, पदपूर्तियाँ और अनियमितताओं की जाँच

2. (क्र. 174) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के किन विकासखण्डों के 1000 से अधिक की जनसंख्या के किन ग्रामों में कब सामुदायिक/प्राथमिक/उप एवं मिनी स्वास्थ्य केंद्र खोले गये हैं एवं कब किनका उन्नयन किया गया और अब कब किनका उन्नयन किया जावेगा? विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) स्वास्थ्य केंद्रों में कौन और कितने विभागीय एवं

आर.सी.एच. के चिकित्सक/अधिकारी व पैरामेडिकल कर्मचारी पदस्थ हैं तथा कहाँ किनके स्वीकृत पदों के विरुद्ध पद रिक्त हैं? विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) में कौन चिकित्सक एवं कर्मचारी कितने वर्षों से पदस्थ है और किनके विरुद्ध क्या शिकायतें पायी गयी हैं और किनका स्थानांतरण कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में से कौन चिकित्सक एवं कर्मचारी कहाँ पदस्थ है और अपने केंद्र एवं स्थायी निवास में कहाँ निवास करते हैं और उनमें से किनकी जनवरी 2014 से नियमित एवं निर्धारित समय पर सेवा में उपस्थित कितने दिवस उपस्थिति रही है? (ड.) क्या प्रश्नांश (ख), (ग), (घ) के अनुसार पदों की पूर्ति एवं अनियमितताओं पर कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र की शा.मा. शाला खमरिया (बाकल) के संबंध में

3. (क्र. 435) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शा.मा. शाला खमरिया (बाकल) - वि.स. बहोरीबंद में प्रधानाध्यापक कौन है? क्या ये सन् 2010 में शाला में अनुपस्थित रहे हैं? यदि हाँ तो कब से कब तक? क्या अनुपस्थित तिथियों का वेतन भी विभाग द्वारा इन्हें प्रदत्त किया गया है? यदि हाँ तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित प्रधान अध्यापक अत्यधिक विवादास्पद है और इनके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की गई है और जाँच में दोषी पाये जाने के बाद भी कार्यवाही न होने से माननीय उच्च न्यायालय की परिधि में जाने से माननीय न्यायालय द्वारा कलेक्टर कटनी को कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, किंतु आज दिनांक तक इनके विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई यदि हाँ तो क्यों? क्या शीघ्र कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संबंधित प्रधान अध्यापक द्वारा अपने अधीन कार्यरत एक सहायक शिक्षक को माह मार्च 2014 में शाला में नियमित उपस्थिति के बाद भी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं करने दिये गये। यदि हाँ तो क्या इसे स्वेच्छा चारिता मानकर सेवा संहिता अधिनियम के तहत संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) श्री लटटीलाल रैदास प्रधानाध्यापक। जी हाँ। दिनांक 06-02-2010 से 19-02-2010 तक अनुपस्थित रहे। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री को बहोरीबंद प्रवास पर 18-02-2011 को आयोजित अंत्योदय मेला में शिकायत की गई। शिकायत की जाँच तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद द्वारा की गई। माननीय न्यायालय के निर्देश पर कलेक्टर कटनी द्वारा पुनः जाँच के आदेश इस आधार पर दिए गए कि जाँच अधिकारी द्वारा श्री रैदास का पक्ष नहीं सुना गया। अंतिम जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश में वर्णित शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फीस

4. (क्र. 604) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा इंदौर/भोपाल/उज्जैन जिलों में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान किस-किस निजी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति/फीस, प्रति छात्र दी गई? (ख) अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/मेडिकल/नर्सिंग/बी.एड/एम.बी.ए./बी.ए/ एम. ए/ अन्य प्रकार के) करने वाले अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है? कोर्सवार/राशिवार जानकारी दें? (ग) क्या अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कमी की गई है? अगर हाँ तो किस कारण से? जारी हुये आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग की क्रमशः इन्दौर /भोपाल/उज्जैन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ए, बी एवं सी अनुसार है एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की इन्दौर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक, दो एवं तीन एवं भोपाल जिले की जानकारी प्रपत्र-चार, पाँच एवं छः तथा उज्जैन जिले की जानकारी प्रपत्र-7, 8 एवं 9 अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन, छः एवं नौ अनुसार है। निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अशासकीय संस्थाओं में सेन्ट्रल काउंसिलिंग से प्रवेश लेने पर फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है:-

पाठ्यक्रम	निर्धारित फीस
एमबीबीएस	375000
बीडीएस	135000
बीई	37000
बी. फार्मा.	37000
एम. फार्मा.	140000
पोलिटेक्निक	22000
नर्सिंग	45000
बी.एड.	25000

आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित इन्दौर जिले की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-डी, भोपाल जिले की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई एवं उज्जैन जिले

की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एफ अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फीस

5. (क्र. 605) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा ग्वालियर/जबलपुर एवं सतना जिलों में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान किस-किस निजी महाविद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति/फीस, प्रति छात्र दी गई? (ख) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/ मेडीकल/नर्सिंग/बी एड/एम बी ए/बी ए/एम ए/अन्य प्रकार के) करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है? कोर्सवार/राशिवार जानकारी दें? (ग) क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के पिछड़ावर्ग में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कमी की गई है? अगर हाँ तो किस कारण से? जारी हुये आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 12 वीं कक्षा के बाद के कोर्स हेतु (इंजीनियरिंग/ मेडिकल/ नर्सिंग/ बीएड/एमबीए/बीए/एमए/अन्य प्रकार के) पाठ्यक्रमों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति संशोधित नियम 2013 अनुसार फीस उसी सीमा तक दी जाती है जो किसी शासकीय संस्था में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर दी जाती है। विषयवार स्वीकृत छात्रवृत्ति की दरों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्कूल बसों में महिला कंडक्टर/हेल्पर की व्यवस्था

6. (क्र. 678) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में बच्चों को घर से लाने ले जाने हेतु चल रही बसों में महिला कंडक्टर या हेल्पर रखने संबंधी निर्देश जारी किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो इंदौर जिले के कितने विद्यालयों द्वारा इस आदेशानुसार अपनी स्कूल बसों में महिला कण्डक्टर या हेल्पर की नियुक्ति कर पालन किया है, संख्या स्पष्ट करें व जिन्होंने नहीं किया है उनके लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) इस संबंध में कलेक्टर इंदौर से जारी आदेश की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग स्तर पर इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। (ख) इंदौर जिले के कुल 27 विद्यालयों ने उक्त आदेश का पालन किया है एवं शेष ने यथा शीघ्र जिला प्रशासन इंदौर की बैठक में आदेश पालन करने की मौखिक स्वीकृति दी है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

चिमनबाग स्थित छात्रावास को नवीन भवन में स्थानांतरण

7. (क्र. 679) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इंदौर के खण्डवा रोड स्थित नवीन बालक छात्रावास हेतु नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो इंदौर के चिमनबाग स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक छात्रावास को आज दिनांक तक उक्त नवीन भवन में स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया व कब तक स्थानांतरित किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा

इन्दौर के खण्डवा रोड स्थित नवीन बालक छात्रावास का भवन स्वीकृत नहीं होने से पूर्ण होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सबलगढ़ तहसील में सामु.स्वा. केंद्र हेतु स्वीकृत भवन निर्माण

8. (क्र. 752) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील मुख्यालय पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु नवीन भवन निर्माण हेतु 2.60 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है? यदि हाँ, तो स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? क्या यह सही है कि उक्त भवन के निर्माण का शिलान्यास मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05.09.14 को सबलगढ़ प्रवास के दौरान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उक्त भवन का निर्माण अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं हुआ है? (ख) उक्त भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी भूमि कहाँ पर आरक्षित की गई है? भूमि का सर्वे क्रमांक एवं रकबा सहित बतावें? क्या यह सही है कि प्रशासन द्वारा तहसील सबलगढ़ में अलखिया खोह के पास शासकीय भूमि का आवंटन अस्पताल भवन के निर्माण हेतु किया है जो कि सबलगढ़ नगर से बाहर एवं शमशानघाट के पास से रास्ता होने के कारण नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अस्पताल हेतु उचित जगह न होने के कारण अन्य स्थान पर भूमि आवंटन की मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या प्रशासन पूर्व में ही स्थित सामुदायिक भवन एवं उसके पास स्थित शासकीय भूमि जो वर्तमान में किराए पर है, को भवन निर्माण हेतु आवंटन कर उपलब्ध कराएगा? (घ) अस्पताल भवन निर्माण प्रारंभ किए जाने के संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है एवं कब तक भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। स्वीकृति आदेश की प्रति की जानकारी परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं होने के कारण। (ख) नवीन भूमि ग्राम रामपुरकलां रोड से अलखिया कच्चा रोड पर आरक्षित की गई है। भूमिका सर्वे क्रमांक 984 एवं रकबा 1.810 हेक्टेयर। जी हाँ। (ग) प्रकरण विचाराधीन है। (घ) भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.02.2013 को जारी हुई। शहर से बाहर आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य कराने हेतु अंतिम निर्णय नहीं हुआ। अस्पताल भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन होने एवं भूमि आवंटित होने पर निर्माण कार्य की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तीस"

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति की समस्याएँ

9. (क्र. 753) श्री रामनिवास रावत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति की समस्याओं को जानने एवं उनके निराकरण हेतु मुख्यमंत्री निवास पर दिनांक 04 जुलाई 2013 को इन वर्गों के प्रतिनिधियों की पंचायत का आयोजन किया गया? यदि हाँ, तो इस पंचायत में क्या प्रमुख समस्याएँ इस वर्ग की सामने आईं एवं इस वर्ग के कल्याण के लिये मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या-क्या घोषणाएँ की? इन घोषणाओं में से कितनी पूर्ण हो चुकी है एवं कितनी अपूर्ण है एवं क्यों? (ख) वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्नांकित दिनांक तक श्योपुर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के कल्याण हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई बतावें तथा आवंटित राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई व वर्तमान में कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु शेष है? (ग) क्या मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रावधानों के अनुरूप विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के आवासहीनों के लिए आवास निर्माण हेतु अनुदान देने की योजना विभाग में संचालित है? यदि हाँ, तो अनुदान स्वीकृत किए जाने के क्या नियम एवं निर्देश हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) की अवधि में श्योपुर जिले में प्रश्नांश (ग) की योजना के तहत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित कर कितना अनुदान स्वीकृत किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। इस पंचायत में इस वर्ग की कोई प्रमुख समस्या सामने नहीं आई। मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिये 21 घोषणाएँ की गई थी, जिनमें से 12 घोषणाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। 01-घोषणा अन्य विभाग को अंतरित की गई है एवं 08-घोषणाओं पर कार्यवाही प्रचलित है। अपूर्ण/लंबित रहने का कारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) आवंटित राशि एवं व्यय राशि की जानकारी तथा किए गए कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ। विमुक्त जाति आवास योजनांतर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाने के नियम एवं निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) की अवधि में श्योपुर जिले में उत्तरांश (ग) की योजना विमुक्त जाति आवास योजना के तहत किसी भी हितग्राही को लाभान्वित कर अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। उक्त योजनांतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु जिला स्तर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। प्रस्ताव प्राप्त न होने से अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

उज्जैन इन्दौर सम्भाग में छोटे बच्चों में विटामिन की कमी

10. (क्र. 834) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उज्जैन, इन्दौर सम्भाग के अनेक शहरों में छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण मोटापे एवं स्वास्थ्य संबंधी

बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि विटामिन डी की कमी और मोटापे के संयुक्त प्रभाव के चलते डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है? यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोकथाम हो, क्या कारगर योजना बनाने पर विचार कर रही है? (ग) क्या सरकार बच्चों एवं अभिभावकों में शारीरिक पोषक के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हुए कोई ठोस कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले की विभिन्न माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल की शालाओं में कब-कब किस-किस दिनांक को स्वास्थ्य परीक्षण हुआ? शाला का नाम, चिकित्सक का नाम, दिनांक एवं परीक्षण के दौरान यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई बच्चा हो, तो उसका नाम बतायें, तथा इलाज के लिये क्या प्रयास किये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन, इंदौर संभाग के अनेक शहरों में छोटे बच्चों में विटामिन-डी की कमी के कारण मोटापे एवं स्वास्थ्य संबंधी बिमारियों के निरंतर बढ़ने संबंधी कोई राष्ट्र/राज्य स्तरीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। अतः बच्चों में विटामिन-डी की कमी से मोटापे एवं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं या घट रही हैं, यह बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। सरकार द्वारा बच्चों एवं अभिभावकों में शारीरिक पोषक तत्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। (घ) प्रश्नभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि संकाय बढ़ाये जाने बावत्

11. (क्र. 1116) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्तमान में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जा रहे हैं, स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें? क्या उक्त स्कूलों में वर्तमान में संचालित संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय बढ़ाये जाने के लिये प्रस्ताव मांगे गये थे? (ख) यदि हाँ तो पोहरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में किस-किस विद्यालय में कौन-कौन से संकाय को बढ़ाये जाने के प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजे गये हैं? उक्त विद्यालयों में अन्य संकाय कब तक प्रारंभ कर दिये जावेंगे? विद्यालयवार संकाय की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) व (ख) के संदर्भ में किस-किस विद्यालय में कृषि संकाय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव विभाग को दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत 09 संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्तमान में पढ़ाए जा रहे विषय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शासन स्वीकृति एवं बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट - "इकतीस"

शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाईयों का वितरण

12. (क्र. 1236) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में शासन निर्देशानुसार कितने-कितने प्रकार की कौन-कौन सी दवाईयां मरीजों को निःशुल्क दी जा रही है? (ख) उक्त निर्देशानुसार श्योपुर जिले में जिला चिकित्सालय सहित समस्त सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अप्रैल, 2014 से वर्तमान तक की अवधि में कितने प्रकार की कौन-कौन सी दवाईयां निःशुल्क दी जा रही है? (ग) क्या उक्त अवधि में उक्त दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता निरंतर बनी रही? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी दवाईयों का कब-कब अभाव रहा, इसके क्या कारण हैं? इनकी उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में चिकित्सकों द्वारा लिखे गये पर्चे के अनुसार उक्त चिकित्सालय/सभी केन्द्रों में मरीजों को कई प्रकार की दवाईयां बाजार से क्रय करना पड़ी, अथवा कर रहे हैं? इस कारण निःशुल्क दवाई वितरण योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है? (ड.) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में श्योपुर जिले को सभी प्रकार की कुल प्राप्त दवाईयों का कोटा व खपत तथा स्टोर में शेष बची दवाईयों से संबंधित अभिलेखों का भौतिक सत्यापन शासन करवायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में शासन निर्देशानुसार मरीजों को निःशुल्क प्रदाय की जाने वाली दवाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) श्योपुर जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अप्रैल 2014 से वर्तमान तक की अवधि में दी जाने वाले निःशुल्क दवाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जिले में उक्त अवधि में उपरोक्त दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। (घ) जी नहीं। निःशुल्क दवा वितरण योजना का लाभ मरीजों को मिल रहा है। (ड.) (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निशुल्क जाँचों के संबंध में

13. (क्र. 1237) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जाँच योजना के तहत थायरॉइड प्रोफाईल टार्चटेस्ट, पीटीटी, पीएपी, स्मीअर, फारसाईटोलॉजी की जाँच सुविधाएं उपलब्ध न होने की जानकारी प्रश्नकर्ता के परि. अतारांकित प्रश्न संख्या-19 (क्र.-175), दिनांक 4 मार्च, 2014 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो इन जाँच सुविधाओं की उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त जाँचों की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जावेगी? (ग) क्या यह सच है कि उक्त जाँचों के लिये जिले के मरीजों को वर्तमान में भी अन्यत्र जाना पड़ता है? तथा शासन की निःशुल्क जाँच सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित अनुपलब्ध जाँच सुविधाएं जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था शासन शीघ्र करेगा व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जिला चिकित्सालय श्योपुर में निःशुल्क जाँच योजना के तहत पी. पी. टी. की जाँच सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। टार्च किट एवं थायरॉइड जाँच के लिये उपकरण के क्रय की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है एवं पेप-स्मीयर फॉरसाईटोलॉजी जाँच से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री/रीजेन्स उपलब्ध हैं परन्तु उक्त जाँच मेडिकल कालेज स्तर पर साईटोलोजी विभाग में की जाती है। उक्त जाँच करने के लिये मेडिकल कालेज ग्वालियर के साईटोलोजी विभाग से स्वीकृती हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 46 श्योपुर दिनांक 03.01.2015 भेजा गया है। जी हाँ, निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। पी. टी. टी. की जाँच जिला चिकित्सालय श्योपुर में उपलब्ध होकर मरीजों को सुविधा प्रदान कराई जा रही है। शेष थायरॉइड प्रोफाईल टार्चटेस्ट, की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी तथा वर्तमान में थायरॉइड प्रोफाईल टार्चटेस्ट, पीएपी, स्मीअर, फारसाईटोलॉजी के सैंपल लेकर आवश्यकता पड़ने पर हायर सेंटर पर निःशुल्क भेजे जाते हैं। (घ) उत्तरांश 'ख' अनुसार।

छतरपुर जिले में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

14. (क्र. 1294) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला कार्यालय द्वारा विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत अनु.जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के वितरण में कोई अनियमितता हुई है? (ख) यदि हाँ, तो कितने छात्रों की कितनी राशि का गबन किया गया है? (ग) इस घोटाले में लिप्त श्रम अधिकारी के साथ-साथ सभी अधिकारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? (घ) यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) से (घ) निरंक।

छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही

15. (क्र. 1295) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक जिला छतरपुर में छात्रवृत्ति संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं शिकायतें व जाँच रिपोर्ट दोषी अधिकारी पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें? (ख) जिला छतरपुर में छात्रवृत्ति से संबंधित उक्त शिकायतों पर जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर ने जांचों को किस स्तर पर लंबित रखा हुआ है और इनमें से कौन-सी जांचें समय सीमा पर निपटाने के निर्देश दिये गये थे यदि समय सीमा पर नहीं निपटायी गयी तो जिम्मेदार अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बतावे? (ग) ग्राम करी के विद्यालय में छात्रवृत्ति में की गयी घोर अनियमितता की शिकायतें हुई थी, उन शिकायतों पर समय सीमा पर कार्यवाही की गयी या नहीं यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? (घ) उक्त शिकायतों पर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करने के लिये जिम्मेवार वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की यदि की गयी है तो जानकारी प्रदाय की जावे, यदि नहीं की गयी है तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कुल 03 शिकायतें, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) उत्तरांश- क अनुसार, छात्रवृत्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न नहीं उठता है। (ग) जी हाँ, शिकायतकर्ता श्री नीलू साहू एवं अधिमान्य पत्रकार विजय द्विवेदी द्वारा जन शिकायत निवारण के माध्यम से ग्राम करी के शास.उ.मा.वि. करी में छात्रवृत्ति में की जा रही अनियमितताओं एवं घोटाला संबंधी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर को दिनांक 09/08/14 प्राप्त हुई थी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4520 दिनांक 28/08/14 द्वारा उक्त शिकायत मूलतः कलेक्टर, छतरपुर की ओर प्रेषित करते हुये जाँच आदिम जाति कल्याण विभाग, छतरपुर से कराये जाने का अनुरोध किया गया, वर्तमान में उक्त शिकायत की जाँच सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छतरपुर द्वारा की जा रही है। (घ) उत्तरांश- क के अनुसार, प्राप्त 03 शिकायतें निराध एवं असत्य पाये जाने के कारण किसी भी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा शास. उ.मा.वि. करी में छात्रवृत्ति घोटाला संबंधी 01 शिकायत की जाँच सहायक संचालक, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, छतरपुर द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

शासकीय विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

16. (क्र. 1325) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से

प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायरसेकण्डरी स्कूल है जिनकी बाउण्ड्रीवाल नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? (ग) क्या शासन उपरोक्त स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु इस वित्तीय सत्र में स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की 264 शालाओं में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार** है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार** है। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में प्रावधान रखा गया था। भारत शासन में योजना स्वीकृत न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी बाउण्ड्रीवाल बजट उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रश्न दिनांक तक बाउण्ड्रीवाल की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति संबंधी उक्त योजना की स्वीकृति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा होती है। वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास की स्वीकृति

17. (क्र. 1326) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 2058/सीएमएस/एमएलए/161/2014 भोपाल दिनांक 7 अगस्त 2014 द्वारा ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास स्वीकृत किये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग को आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास की स्वीकृति इसी बजट सत्र में प्रदान करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) इस विषय पर निर्णय अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा लिये जाने के कारण इस विभाग के पत्र दिनांक 27/08/2014 द्वारा प्रेषित किया गया। (ग) अनुसूचित जाति विकास विभाग से संबंधित।

बाल श्रमिकों को उत्थान के लिए किये गये प्रयास

18. (क्र. 1384) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक कितने बाल श्रमिकों, विभिन्न उद्योगों/कंपनियों एवं

प्रतिष्ठानों में कार्यरत पाये गये हैं, जिलेवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि सतना जिले में प्रतिष्ठानों/संस्थानों में बाल श्रमिक के काम करते हुए पकड़े जाने के बावजूद भी श्रम विभाग द्वारा काम कराने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई? (ग) क्या जो बाल श्रमिक काम करते हुए पाये गये, उनके उत्थान के लिये शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक विभिन्न उद्योगों/कंपनीयों एवं प्रतिष्ठानों में पाये गये बाल श्रमिकों का विवरण निम्नानुसार **टेबल** में दिया गया है, (ख) जी, नहीं। सतना जिले में बाल श्रमिक नियोजित नहीं पाये जाने से कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं रही। (ग) बाल श्रमिकों के संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:- (1) बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। (2) प्रदेश में 17 जिलों मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, राजगढ़, रीवा, सीधी जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह तथा सतना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों को शाला में प्रवेश दिलाया जाता है तथा परियोजना अंतर्गत उन्हें 150 रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा मध्यान्ह भोजन, पठन पाठन सामग्री आदि दी जाती है। **टेबल**

क्रमांक	जिले का नाम	पाये गये बाल श्रमिक
1.	सागर	02
2.	बेतूल	01
3.	देवास	01
4.	उज्जैन	02
5.	ग्वालियर	08
6.	मंदसौर	01
7.	टीकमगढ़	01
8.	भोपाल	01
9.	इंदौर	31
10.	नरसिंहपुर	01

प्रायवेट उद्योग में श्रमिकों को मजदूरी भुगतान

19. (क्र. 1387) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के विधान सभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत सतना से पन्ना मार्ग पर गोयल प्लाईवुड फैक्ट्री सितपुरा में स्थापित है? (ख) उक्त फैक्ट्री में कितने श्रमिक कार्यरत हैं? उन्हें कितनी मजदूरी प्रतिदिन दी जा रही है? क्या कार्यरत श्रमिकों की पंजी संधारित की जाती है?

(ग) यदि इनके द्वारा श्रम नियमों का पालन न कर श्रमिकों को कम मजदूरी भुगतान की जाती है तो क्या जाँच कराकर दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

RMSA अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति

20. (क्र. 1415) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत दिनांक 1.4.2013 से 31.12.2014 तक किस-किस शाला में अधोसंरचना एवं लघु निर्माण अंतर्गत कितने-कितने और कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुये थे, तथा कौन-कौन सी शालाओं के लिये नवीन शाला भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हुये थे? शाला की नामवार एवं कार्य का नामवार जानकारी देवें? (ख) इनमें से 31 जनवरी 2015 तक कितने और कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये हैं? कितने और कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं, तथा कितने और कौन-कौन से कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुये हैं? शाला के नामवार एवं कार्य के नामवार जानकारी देवें? (ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में शासकीय कन्या हाई स्कूल राहतगढ़ एवं बालक हायर सेकण्डरी स्कूल, बिलहरा सहित अन्य विद्यालयों के लिये स्वीकृत निर्माण कार्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हो सके हैं? (घ) यदि हाँ, तो अब तक उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ न करने के लिये कौन - कौन अधिकारी दोषी है और उस पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी, तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त अवधि में नवीन भवन स्वीकृत नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त अवधि में संलग्न परिशिष्ट अनुसार ही कार्य स्वीकृत हुए हैं उक्त अवधि में अन्य कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। शासकीय कन्या हाईस्कूल राहतगढ़ हेतु भवन स्वीकृत नहीं है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलहरा में सत्र 2011-12 में 27.75 लाख के 05 अतिरिक्त कक्ष, 01 कला कक्ष स्वीकृत किए गए। उक्त निर्माण, आवंटित आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होने से, प्रारम्भ नहीं हो सका कालान्तर में अतिक्रमण हटने के बाद, ठेकेदार ने पुराने एस.ओ.आर. पर कार्य करने से इनकार कर दिया। परिणामतः निर्माण एजेंसी द्वारा ठेकेदार की अमानत राशि राजसात कर ली गई। (घ) प्रश्नांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेतीस"**अधिकार एवं प्रयोजनों के सामुदायिक अधिकार पत्रों का वितरण**

21. (क्र. 1448) श्री निशंक कुमार जैन :क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनवरी, 2008 से लागू वन अधिकार कानून, 2006 में परिभाषित वन भूमियों पर राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों के सामुदायिक अधिकार पत्र विदिशा जिले में एवं बैतूल जिले में प्रश्नांकित तिथि तक भी वितरित नहीं किए जा सके हैं? (ख) यदि हाँ, तो कानून में वन भूमि की क्या परिभाषा दी गई है? इस परिभाषा के दायरे में आने वाली भूमि विदिशा एवं बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए वर्तमान में दर्ज हैं? इन भूमियों पर वन अधिकार कानून की किस धारा, उपधारा के तहत कौन-कौन से अधिकारों के सामुदायिक अधिकार पत्र दिए जाने हैं? (ग) विदिशा एवं बैतूल जिले में कितनी वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है? इन समितियों को या ग्रामसभा को या ग्राम पंचायत को कितने पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी की प्रति प्रश्नांकित तिथि तक उपलब्ध करवा दी है? कितनों को उपलब्ध करावाया जाना शेष है? (घ) कानून द्वारा परिभाषित वन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार एवं प्रयोजनों के कब तक सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित कर दिए जावेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ) से- "वनभूमि से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है"। राजस्व अभिलेखों में उल्लिखित मदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं सामुदायिक अधिकारों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) बैतूल जिले में 1045 एवं विदिशा जिले में 530 समितियों का गठन किया है। इन समितियों को ग्रामसभा/ग्राम पंचायतों को पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक, खसरा पंजी, की प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है। मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख की प्रति पूर्व से ही उपलब्ध कराई गई जा चुकी है। (घ) वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौतीस"**मॉडल स्कूल में विद्युत व्यवस्था**

22. (क्र. 1449) श्री निशंक कुमार जैन :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले के गंजबासौदा में सरकारी मॉडल स्कूल के नवनिर्मित भवन में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण जनरेटर का उपयोग किया जाकर विद्युत व्यवस्था की

जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो नवनिर्मित भवन में स्कूल का संचालन किस दिनांक से किया जा रहा है स्कूल में प्रश्नांकित तिथि तक भी विद्युत कनेक्शन न करवाए जाने का क्या-क्या कारण रहा? (ग) स्कूल संचालन में प्रश्नांकित तिथि तक जनरेटर से की गई विद्युत व्यवस्था पर कितनी राशि खर्च कर दी गई है? जनरेटर में उपयोग किए जा रहे ईंधन एवं जनरेटर ऑपरेटर को भुगतान की गई राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा दें? (घ) मॉडल स्कूल गंजबासौदा में कब तक विद्युत कनेक्शन लगवा लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) नव निर्मित भवन में शाला का संचालन दिनांक 22.11.2014 से किया जा रहा है। विद्युत कनेक्शन के लिये बिजली कंपनी द्वारा चाही गई राशि की स्वीकृति संचालनालय के आदेश क्रमांक 550-51 दिनांक 19 जून 2014 के द्वारा लोक निर्माण विभाग, विदिशा को प्रदान की गई है। (ग) "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (द) कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षकों के स्वीकृत पद

23. (क्र. 1564) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में अध्यापक संवर्ग - 1, 2, 3 के तथा शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने पद भरे हुए हैं? (ख) कितने पद अध्यापक संवर्ग से पदोन्नति से भरे जाने हैं एवं कितने शिक्षक संवर्ग से? (ग) क्या बालाघाट जिले में पदोन्नति से भरे जाने वाले अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो इनकी पूर्ति पदोन्नति द्वारा कब तक कर दी जावेगी? लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने हेतु जिम्मेदार कौन है? (घ) क्या संविदा शाला शिक्षकों की परिविक्षा अवधि 1 वर्ष की जानी चाहिये? चूंकि वह प्रशिक्षित होकर ही नियुक्त किया जा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अध्यापक संवर्ग के 305 एवं शिक्षक संवर्ग के 680 पद। पदोन्नति से भरे जाना है। (ग) जी नहीं। बालाघाट जिले में वरिष्ठ अध्यापक के 26 पद एवं अध्यापक के 96 पद पदोन्नति के रिक्त है। उक्त पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से रिक्त है। उच्च श्रेणी शिक्षक के 10 पद रिक्त है जिन पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रशिक्षित होना आवश्यक आर्हता है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

कर्मचारी/अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति

24. (क्र. 1565) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के अन्तर्गत

समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं कितने पद किन-किन कारणों से कब से रिक्त हैं? (ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर लंबे समय से पदों की पूर्ति नहीं होने से सामान्य स्वास्थ्य सुविधायें आमजन को नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन शीघ्र रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? (ग) 2012-13, 2013-14, 2014-15 में किन-किन मदों में विभाग को कितनी-कितनी राशि का आबंटन जिला बालाघाट को दिया गया? (घ) जिला अस्पताल में आडिट केश बुक के अनुसार वितरित राशि फर्म के नाम सहित प्रदाय करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) उपलब्ध स्वास्थ्य अमले से स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरुद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विभाग में विशेषज्ञों एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सा अधिकारियों हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा पैरामेडिकल के 900 पदों पर सीधी भर्ती हेतु मांग पत्र व्यापम को प्रेषित किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

विद्यालयों में पदों की जानकारी

25. (क्र. 1696) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल संचालित हैं? शैक्षणिक संवर्ग के पदवार स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों पर समय रहते कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना नहीं करने के क्या कारण है? इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने के कारण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अध्ययन पर किस प्रकार का प्रभाव हुआ और हो रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) में दर्शित शिक्षकों की कमी के कारण उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र किस प्रकार हुए और हो रहे हैं? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इस विसंगतियों को कब तक दूर किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। (ख) रिक्त पदों पर पदस्थापना की कार्यवाही पदोन्नति अथवा संविदा शिक्षक की नवीन नियुक्ति

द्वारा की जाती है। प्राचार्य उ.मा.वि. एवं हाईस्कूल के पदों पर पदोन्नति प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जी नहीं रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

श्रमिकों के लिए संचालित कल्याण योजनाएं

26. (क्र. 1697) श्री सचिन यादव :क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने श्रमकार्डधारी श्रमिक हैं? पंचायतवार संख्या बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार विगत एक वर्ष में कितने श्रमकार्डधारियों को विभाग की किन-किन योजना से लाभान्वित किया गया? पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत कुल 16, 657 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। पंचायतवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ख के अनुसार विगत एक वर्ष में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निम्न योजनांतर्गत लाभान्वित किया गया है, जिसकी जानकारी टेबल 1 अनुसार है। योजनावार दिये गये हितलाभ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 3 एवं 4 अनुसार है। टेबल 1

क्रमांक	योजना	लाभान्वित श्रमिक
1.	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	83
2.	प्रसूति सहायता	23

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन

27. (क्र. 1709) श्री प्रताप सिंह :क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जेबरा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किस अवधि से किन-किन स्थानों पर संचालित है? क्या इन संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ तो उन्हें संचालित करने के लिए अनुभवी स्टाफ है अथवा नहीं यदि नहीं तो क्या कारण है? उपकरण क्या गैर तकनीशियन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ तो उनके नाम, पदनाम सहित बतलावें? (ख) विधान सभा क्षेत्र जेबरा में संचालित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

स्वीकृत स्टाफ एवं कार्यरत स्टाफ तथा रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति बतलावें? रिक्त पद यदि है, तो उनकी पूर्ति के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी? समय-सीमा बतलावें? (ग) वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये? वर्तमान स्थिति केन्द्रवार बतलावें? (घ) जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा विगत एक वर्ष में क्षेत्र अंतर्गत केन्द्रों का निरीक्षण किया है? यदि हाँ तो कब-कब? अधिकारीवार एवं दिनांकवार विवरण दें? निरीक्षण में केन्द्रवार क्या-क्या अनियमितताएं परिलक्षित हुईं तथा उनके सुधार के लिए जिला एवं शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दमोह जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जबेरा में संचालित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकास खण्ड का नाम	सामु.स्वा.केन्द्र का नाम एवं वर्ष	प्राथ.स्वा.केन्द्र का नाम एवं वर्ष
1	तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा-2005	सर्गा-2001
2	जबेरा	जबेरा-2005	रौंड-2001
3			नोहटा-2008

शासन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्टाफ स्वीकृत है एवं उपकरण उपलब्ध है। जी हाँ । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नावधि में विधान सभा क्षेत्र जबेरा के विकास खण्ड तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र तेजगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया गया है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

रोगी कल्याण समिति की बैठक एवं उपस्थित

28. (क्र. 1710) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में विगत 2 वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार कब-कब रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई हैं? तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में आयोजित बैठकों में कितने सदस्य आमंत्रित किये गये, सदस्यों के नाम एवं पते बतलावें एवं कुल कितने सदस्य हैं? बैठकवार उपस्थित सदस्यों की जानकारी दें? (ख) क्या यह सत्य है कि जबेरा एवं तेंदूखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया, हाँ या नहीं? (ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण रहा है, यदि हाँ, तो रोगी कल्याण समिति की अंतिम बैठक का दिनांक एवं बैठक में लिये गये निर्णय तथा

निर्णय के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दें? (घ) विगत 2 वर्षों से तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन न होने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका नाम पदनाम सहित बतलावें? क्या संबंधित दोषी अधिकारी पर अनियमितता के फलस्वरूप कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दमोह जिले में विगत दो वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार रोगी कल्याण समिति की आयोजित बैठकोंकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। तेन्दूखेडा एवं जबेरा में आयोजित बैठकों में आमंत्रित सदस्यों के नाम एवं पतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) जी नहीं। रोगी कल्याण समिति की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जबेरा में विगत बैठक दिनांक 02/09/2013 को एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेन्दूखेडा में विगत बैठक दिनांक 01/02/2013 को आयोजित की गई। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जबेरा का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेन्दूखेडा के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) इसके लिए संबंधित विकास खण्ड के विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार है। इस हेतु उनके विरुद्ध कारणबताओं नोटिस जारी किया गया है।

छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन

29. (क्र. 1711) श्री प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2012-13 से राज्य शासन ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला कार्यालय की स्थापना की है? (ख) दमोह जिले में वर्ष 12-13 एवं 13-14 में पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत जबेरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित पाठशालाओं के कितने बालक एवं बालिकाओं को लाभांशित किया गया, वर्षवार बतलावें? कक्षा ग्यारहवीं, बारहवीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी व्यवसायी पाठक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति किस दर पर प्रदान की गई? (ग) दमोह जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक तक कितना ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया है? (घ) दमोह जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि चरणवार स्वीकृत की गई है? ऐसे छात्र/छात्राओं के नाम एवं पते सहित बतलावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी, हाँ। (ख) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में 18402 एवं 2013-14 में 19306 बालक एवं बालिकाओं को पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभांशित किया गया है। पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक संशोधित छात्रवृत्ति नियम, 2013 की कंडिका 5.3 के अनुसार कक्षा ग्यारहवीं, बारहवीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी व्यवसायी पाठक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शासकीय संस्थाओं में लगने वाली फीस के समतुल्य दी जाती है। दरों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) दमोह जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक तक बैंकों के माध्यम से रुपये 48, 93, 000 का ऋण उपलब्ध कराया है एवं इस ऋण पर

विभाग के द्वारा रूपये 12, 23, 250 का अनुदान दिया गया है। (घ) दमोह जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर रूपये 1, 95, 000 की राशि चरणबद्ध स्वीकृत की गई है। छात्र/छात्राओं की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

वन संस्कार कार्यक्रम संचालित पौधे प्रदान बावत

30. (क्र. 1712) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से विगत वर्ष वन संस्कार कार्यक्रम संचालित किया गया था? यदि हाँ, तो दमोह जिले में उल्लेखित कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूल की कक्षा छटवी से आठवी तक के छात्र छात्राओं कुल कितने पौधे प्रदान किये गए, इस पर कितनी राशि व्यय हुई बतलावें? (ख) जिले के स्कूल के छात्र छात्राओं को जो पौधे प्रदाय किये गये थे, उनमें से कितने छात्र छात्राओं ने, प्रोजेक्ट जमा किए? (ग) क्या यह भी सत्य है कि शासकीय कार्यक्रम के अनुसार जिन छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट तैयार किये एवं पौधे स्कूल वापिस लाए तो ऐसे छात्रों को मूल्यांकन उपरांत कितने अंक प्रदान किये गये हैं? कितने छात्र/छात्राएं लाभांवित हुए?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। सत्र 2012-13 में पर्यावरण संरक्षण एवं चेतना जागृति की दृष्टि से वन संस्कार कार्यक्रम अंतर्गत दमोह जिले में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को उद्यान विभाग के माध्यम से कुल 71156 पौधे उपलब्ध कराए गए। इस पर रु. 5, 31, 307/- की राशि व्यय हुई। (ख) प्रदाय किए गए पौधों में से जिले के कुल 52029 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रोजेक्ट जमा किए गए। (ग) जिन छात्र-छात्राओं द्वारा प्रोजेक्ट जमा किए गए उन पर शालेय शिक्षकों द्वारा 5 से 10 तक अंक दिए गए। कुल 52029 छात्र-छात्राएं लाभांवित हुए।

किराये पर लिये गये वाहन

31. (क्र. 1731) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन के द्वारा मितव्ययता एवं दायित्वों के सही निर्वहन एवं समय पर कार्य संपादित करने, विभाग पर नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिकोण से शासकीय कार्यालयों/विभागों में, किराये पर वाहन लिये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो सागर के स्वास्थ्य विभाग में विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर एवं संभाग स्तर पर कितने-कितने और कौन-कौन से मॉडल के, किस-किस वाहन मालिक के, चार पहिया वाहन किस-किस कार्य हेतु प्रतिमाह कितनी-कितनी दर पर, किन् शर्तों के तहत किराये पर लिये गये हैं? (ग) इन वाहनों पर विकासखंड स्तर पर,

जिला स्तर पर एवं संभाग स्तर पर प्रतिमाह किराये के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? दिनांक 01.04.2013 से 31.12.2014 तक प्रतिमाह वाहनवार कितनी-कितनी राशि का भुगतान वाहन मालिक को किया गया? (घ) क्या विभाग वाहनों के मासिक किराये के भुगतान के अलावा किराये के वाहनों के रखरखाव का व्यय भी शासकीय मद से करता है? यदि हाँ, तो 01.04.2013 से 31 दिसम्बर, 2014 तक किराये पर लिये गये वाहनों के रख-रखाव पर कुल कितना व्यय किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक कार्य एवं अटेचमेन्ट

32. (क्र. 1742) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/प्रधानाध्यापक/उच्च श्रेणी शिक्षक/सहायक शिक्षक/ वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को क्या दूसरे विभाग में शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने अथवा संलग्नीकरण के शासन के कोई निर्देश हैं? यदि हाँ, तो कितने समय के लिये? शासन के निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) राजगढ़ जिले में वर्तमान में कितने प्राचार्य/व्याख्याता/प्रधानाध्यापक/उच्च श्रेणी शिक्षक/सहायक शिक्षक/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/ सहायक अध्यापक को शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति अथवा अटेचमेन्ट पर भेजा गया है? नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल, पदस्थापना अवधि, सहित विकास खण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो गई है, फिर भी वे दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति अथवा अटेचमेन्ट पर कार्यरत हैं? शासन उनको उनके मूल पदस्थापना स्थल पर कब तक भेजेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) इसके लिये कौन दोषी है? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बतावें, तथा उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी, तथा कब तक और क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) कोई नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मृतक परिवार को अनुकंपा नियुक्ति

33. (क्र. 1743) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने कर्मचारियों/नियमित शिक्षकों/ अध्यापकों/सहायक अध्यापकों/भृत्य के मृतक परिवार को उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई? उनके नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल सहित विकासखण्ड एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) वर्तमान में राजगढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में दी गई अनुकंपा नियुक्ति में शासन द्वारा कौन-कौन से नियम के तहत उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को दी गई है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) वर्तमान में राजगढ़ जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण उनके आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने हेतु लंबित है? कब तक उन्हें नियुक्ति दी जावेगी? (घ) क्या मानवीय आधार पर मृतक कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में शासन द्वारा

डी.एड/बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना अनुकम्पा नियुक्ति छूट प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) राजगढ़ जिले में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक 40 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल एवं विकास खण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब, स एवं द अनुसार है। (ग) अनुकम्पा नियुक्ति के 08 प्रकरण लंबित है। पात्रता एवं पद की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। समय सीमा बताना संभव नहीं। (घ) भारत सरकार के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद (एन.सी.टी.ई) द्वारा तत्संबंधी अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र अनुसार दिनांक 23 अगस्त 2010 को जारी की गई है। अब संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 व वर्ग-3 के पद पर, अधिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता की पूर्ति के बिना नियुक्ति/अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

जननी सुरक्षा वाहन के संबंध में

34. (क्र. 1749) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला चिकित्सालय राजगढ़ अंतर्गत समस्त विकासखण्ड अंतर्गत प्रसूति महिलाओं को प्रसूति हेतु लाने एवं छोड़े जाने हेतु लगाई जाने वाली जननी वाहनों के क्या नियम -निर्देश है? इसमें राजगढ़ जिला चिकित्सालय अंतर्गत विगत एक वर्ष से कितने वाहन कब से, किस अवधि तक, किस दर पर किस फर्म के लगाये गये है? उक्त फर्म की अवधि कब समाप्त हो रही है? उक्त अवधि में उक्त फर्म को किये गये भुगतान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) राजगढ़ जिला चिकित्सालय अंतर्गत समस्त विकासखण्ड में कुल कितने वाहन चालू हालत में है तथा कितने वाहन खराब स्थिति में है तथा किस कार्य में किसके द्वारा उपयोग में लिये जा रहे है? उनके नाम, नंबर एवं वाहन चालक सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? विगत 3 वर्षों में सभी वाहनों की मरम्मत एवं डीजल पर किये गये व्यय की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या वर्तमान में किसी विकासखण्ड में शासकीय कार्य हेतु प्रायवेट वाहन भी अनुबंधित किये गये है? यदि हाँ, तो उक्त प्रायवेट वाहनों को लगाये जाने हेतु कब निविदा आमंत्रित की गई थी? आदेश की पूर्ण जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट

के प्रपत्र 'तीन' एवं 'चार' अनुसार है। (ग) जी हाँ दिनांक 16/07/2014 को निविदा आमंत्रित की गई थी।

हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूलों का उन्नयन

35. (क्र. 1781) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में प्राप्त हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों के उन्नयन के छतरपुर जिलों के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कितने प्रस्ताव लंबित हैं? उनकी जानकारी दें? (ख) राजनगर एवं लवकुशनगर विकास खण्ड अंतर्गत मा. शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन तथा हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन न किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) शासन प्रावधानों के मुताबिक प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, जहाँ उन्नयन किये जाना है? उनकी सूची दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2014-15 में बजट प्रावधानुसार सभी 50 हाईस्कूलों एवं 100 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन आदेश जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में राजनगर वि.स. क्षेत्र के कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रतिवर्ष सीमित संख्या में ही उन्नयन संभव हो पाता है। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

36. (क्र. 1785) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खाद्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं नियम 1955 के अंतर्गत विभाग द्वारा घी, मावा, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों के 2012 से 31/12/14 तक कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? (ख) क्या यह सच है कि त्यौहारों के समय पर राजधानी, संभागस्तर तथा जिलास्तर पर एक दो दिन अभियान चलता है, फिर बंद हो जाता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 निरसित हो चुका है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के 5 अगस्त, 2011 से प्रभावी होने के कारण प्रश्नांकित अवधि में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। प्रदेश में राजधानी सहित संभाग तथा जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से नमूना/निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

श्रमायुक्त द्वारा अगस्त 2014 में जारी आदेश

37. (क्र. 1839) श्रीमती रेखा यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा माह अगस्त 2014 में जारी पत्र के बाद भी छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न छात्रावास एवं आश्रमों में कार्यरत चौकीदार, रसोईये, भृत्य एवं सफाईकर्मियों को किए गए कम भुगतान की प्रश्नांकित तिथि तक भी जाँच कर कार्यवाही नहीं की है? (ख) श्रमायुक्त इंदौर के द्वारा अगस्त 2014 में जारी पत्र के अनुसार छात्रावास एवं आश्रम में कार्यरत रसोईये, चौकीदार, भृत्य एवं सफाईकर्मियों को दिए जा रहे मजदूरी भुगतान की जाँच हेतु क्या-क्या आदेश निर्देश दिए गए थे? इसके अनुसार छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में श्रम विभाग ने किस-किस दिनांक को क्या कार्यवाही की है? (ग) छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में किस विभाग के कितने आश्रम एवं छात्रावास वर्तमान में कार्यरत हैं? इनमें कितने चौकीदार, रसोईये, भृत्य एवं सफाईकर्मी कार्य कर रहे हैं? इन्हें गत 6 माह में किस दर से प्रतिमाह कितनी राशि का

भुगतान किया गया? (घ) आश्रम एवं छात्रावास में कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किए जाने पर श्रम विभाग ने किस-किस के विरुद्ध कितने प्रकरण बनाए? यदि नहीं बनाए तो कारण बतावें? कब तक बनाए जाएंगे?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं। श्रमायुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 27522 दिनांक 22.08.2014 द्वारा श्रम पदाधिकारी, बैतूल को म.प्र. के विभिन्न शासकीय विभागों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2014 से प्रभावशील मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन की दरें संसूचित की गई थी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) इस प्रकार की जानकारी श्रम विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (घ) शासकीय विभागों द्वारा संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में नियोजन न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 में अधिसूचित नियोजन अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अतः श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रावधान

38. (क्र. 1840) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गैर वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि व्यपवर्तन के संबंध में वन अधिकार कानून 2006 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों में क्या प्रावधान किए जाकर क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं? (ख) जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में किस-किस गैरवानिकी कार्य के लिए कितनी-कितनी वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण जिला स्तर पर प्राप्त हुए हैं उनमें से किस प्रकरण में किस ग्राम सभा के कितने सदस्यों की उपस्थिति में किस दिनांक को प्रस्ताव लिया गया? (ग) किस प्रकरण में कितनी वनभूमि के गैरवानिकी कार्यों में व्यपवर्तन की अनुमति या सहमति या अनुशंसा या अनापत्ति जारी की गई प्रति सहित बतावें? (घ) किस प्रकरण में 50 प्रतिशत से कम सदस्यों की उपस्थित वाली ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अनुमति/सहमति/अनुशंसा या अनापत्ति दी गई इस बाबत कितने सदस्यों की उपस्थिति में ग्रामसभा के प्रस्ताव पर कार्यवाही के प्रावधान रहे हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। प्रस्ताव में ग्रामसभा सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति का उल्लेख है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) प्रस्ताव में 50 प्रतिशत संस्तुति का उल्लेख है।

बैतूल जिले में शाला भवन का निर्माण

39. (क्र. 1888) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में किस-किस विकासखण्ड में विगत पाँच वर्षों में कितने प्राथमिक शाला भवन एवं कितने माध्यमिक शाला भवन के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं? वर्षवार एवं शाला भवन के नामवार एवं स्वीकृत राशि की जानकारी दें? (ख) उपरोक्त स्वीकृत शाला भवनों में से कौन-कौन से भवन अपूर्ण हैं एवं कब से? इन भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) क्या यह सही है कि इन शाला भवनों की निर्माण एजेन्सी पंचायत को बनाया गया है यदि हाँ, तो इसके क्या नियम हैं? लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से बच्चों के बैठने हेतु शाला भवनों का निर्माण नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं? (घ) भवन निर्माण हेतु एजेन्सी को राशि भवन निर्माण की किस-किस स्टेज पर उपलब्ध कराई जाती है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बैतूल जिले में विगत पांच वर्षों में प्राथमिक शाला भवन एवं माध्यमिक शाला भवन के स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण निम्न है:-

निर्माण कार्य	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
प्राथमिक शाला भवन	0	04	0	21	0
माध्यमिक शाला भवन	0	13	0	37	0
योग	0	17	0	58	0

वर्षवार एवं शाला भवन के नामवार एवं स्वीकृत राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 01 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 02 अनुसार। 10 कार्य स्वीकृत वर्ष से अपूर्ण है। कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है। (ग) जी हाँ। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत/शाला प्रबंधन समिति एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भवन निर्माण हेतु एजेंसी को अग्रिम राशि भवन स्वीकृति के समय 50 प्रतिशत प्रथम किश्त जारी की जाती है, प्रथम किश्त का उपयोग होने पर द्वितीय किश्त 35 प्रतिशत जारी की जाती है। शेष निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरांत जारी की जाती है।

परिशिष्ट "उनतालीस"

विभाग की संचालित योजनाएं

40. (क्र. 1981) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं, विवरण उपलब्ध करावें? (ख) विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में प्रश्नांश (क) योजनांतर्गत 1 जनवरी 2010 से दिसंबर 2014 तक कौन-कौन से कार्य करायें गये? योजनावार, ग्रामवार, वर्षवार कार्य की लागत, कार्य स्थिति, एजेन्सी का नाम, सत्यापनकर्ता एवं मूल्यांकनकर्ता अधिकारी के नाम सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

लिपिकों की पदोन्नति

41. (क्र. 1998) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता.प्रश्न संख्या-97 (क्रमांक 1242) दिनांक 12.12.2014 में अवगत

कराया गया था, कि जबलपुर जिले में लेखापाल, सहायक ग्रेड-2 के पद वर्ष 2010 से रिक्त हैं? (ख) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रत्येक 6 माह में कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं एवं लंबे समय से पद रिक्त होने से कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है? (ग) यदि हाँ तो कब तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी? निश्चित समय सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सभी संभागों एवं जिलों में केन्द्रीय पुस्तकालय/जिला पुस्तकालय की स्थापना

42. (क्र. 2001) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के गठन (1956) में प्रदेश में 5 संभाग और 24 जिले थे? उन में सभी संभागीय एवं जिला कार्यालय स्थापित किए गये थे? (ख) यदि हाँ, तो आज जब प्रदेश में 10 संभाग एवं 51 जिले हो गये हैं, तो क्या सभी में सभी विभागों के जिला एवं संभागीय कार्यालय खोले गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो आज दिनांक तक संभाग स्तर पर केन्द्रीय पुस्तकालय एवं जिला स्तर पर जिला पुस्तकालय 1956 की स्थिति में ही क्यों रखे गये? (घ) नवीन 5 संभागों में केन्द्रीय पुस्तकालय एवं 27 जिले में अभी तक जिला पुस्तकालय क्यों नहीं खोले गये? (ङ.) खोले जाने हैं तो कब तक, और यदि नहीं, खोले जाने हैं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिक्षा विभाग के 5 संभाग (जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा) एवं 16 जिले थे। जी हाँ। (ख) प्रदेश में शिक्षा विभाग अंतर्गत 9 संभागीय एवं 51 जिला कार्यालय स्थापित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) 5 संभागों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में केन्द्रीय पुस्तकालय तथा 35 जिलों में जिला पुस्तकालय संचालित है। (घ) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी संभव नहीं हुआ है। (ङ.) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चालीस"

अतिथि शिक्षकों को सुविधायें

43. (क्र. 2061) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में कुल कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत है? फरवरी 2014 से 1 फरवरी 2015 की अवधि में इनके विभिन्न संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्री जी तथा शासन प्रशासन को सौंपे जापन में इनकी मुख्य मांगे क्या-क्या हैं? (ख) अतिथि शिक्षकों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं, तथा उनकी विभिन्न मांगों पर अब तक शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती में इनको क्या-क्या सुविधायें प्राथमिकता का प्रावधान है, मानदेय का भुगतान किस

दर से किया जाता है? (घ) क्या उक्त जिलों के अतिथि शिक्षकों को प्रति माह मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों कारण बतायें, तथा प्रतिमाह मानदेय दिलावाया जाये? इस हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) रायसेन जिले में 1251 एवं देवास जिले में 1751 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। मांग पत्रों में वेतन बढ़ाये जाने, संविदा शिक्षक पद पर नियुक्ति करने, नियमित करने, संविदा शिक्षक पद पर भर्ती में 25 अंक बोनस देने, आयुसीमा में छूट, वेतनवृद्धि, मार्च-अप्रैल माह का वेतन एवं स्थायी करने से संबंधित प्रमुख मांगे प्रस्तुत की गयी। (ख) अतिथि शिक्षकों को मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा देने का प्रावधान नहीं है। अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक की भर्ती में अतिरिक्त अधिभार दिये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष मांगों के संबंध में नियमों में प्रावधान नहीं होने से मान्य किया जाना संभव नहीं है। (ग) संविदा शाला शिक्षकों को भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को जो सरकारी स्कूलों में कम से तीन शैक्षणिक सत्रों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं, नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रावधान है। अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को रुपये 180/- प्रतिदिवस (न्यूनतम तीन कालखण्ड प्रतिदिन लेने पर) तथा माह में अधिकतम सीमा रुपये 4500/-, अतिथि शिक्षक वर्ग-2 को रुपये 150/- प्रति दिवस (न्यूनतम तीन कालखण्ड प्रतिदिन लेने पर) तथा माह में अधिकतम सीमा रुपये 3500/-, प्राथमिक शाला में प्रति उपस्थिति दिवस रुपये 100/- व माध्यमिक शाला में प्रति उपस्थिति दिवस रुपये 150/- की दर से मानदेय भुगतान किये जाने का प्रावधान है। (घ) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

छात्रावास/आश्रम खोलने की योजना

44. (क्र. 2062) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में नायक (बंजारा) समाज के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास आश्रम खोले जाने की विभाग की क्या-क्या योजना है? पूर्ण विवरण दें? (ख) देवास एवं रायसेन जिले में अ.जा./अ.ज.जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए कहाँ-कहाँ आश्रम-छात्रावास संचालित है? सीट की संख्या, उपलब्ध सुविधायें बतायें? (ग) उक्त वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक तथा प्री-मैट्रिक छात्रावास/आश्रम कहाँ-कहाँ प्रारंभ करने हेतु किन-किन माध्यमों से प्रस्ताव /पत्र प्राप्त हुए? (घ) उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं। आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा देवास एवं रायसेन जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों की सूची एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ग) आदिम जाति कल्याण विभाग की

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की जानकारी निरंक है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

प्राचार्य परीक्षा निरस्त होने पर अनियमितता

45. (क्र. 2086) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य के 240 पदों हेतु एम.पी.पी.एस.सी. के द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 12 जुलाई 2010 को जारी की गई थी? (ख) इस विज्ञप्ति में कितने आवेदकों ने आवेदन किया, तथा उनसे परीक्षा शुल्क कुल कितनी राशि वसूली गई? (ग) क्या उक्त प्राचार्य परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद 28 नवम्बर 2014 को निरस्त कर दी गई? यदि हाँ तो निरस्त का कारण बताएं? क्या इस संबंध में कोई न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है? यदि हाँ तो उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार आवेदकों से वसूली गई राशि अभी किस खाते में कहाँ है? क्या परीक्षा निरस्त उपरांत यह राशि पुनः आवेदकों को लौटा दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त विज्ञापन के संदर्भ में कुल 16744 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क के रूप में कुल 2, 3, 31, 000 रुपये प्राप्त हुये। (ग) जी हाँ। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए विभाग के आदेश दिनांक 25.07.13 द्वारा राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया। राज्य शिक्षा सेवा गठन के फलस्वरूप वर्तमान में स्वीकृत पदों को समायोजित करने एवं नवीन पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में एकजाई रूप से सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण चयन परीक्षा निरस्त कर दी गई। इस संबंध में कोई न्यायालयीय प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ख" अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क राशि चालान के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा की गयी है। उक्त राशि के संदर्भ में कोषालय नियमों के अनुसार आवेदकों से आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर जिन अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने के लिए अपेक्षित अभिलेख तथा शुल्क वापसी हेतु अपेक्षित जानकारी उपलब्ध काराई जाएगी, उन्हें शुल्क वापसी में होने वाले व्यय राशि को काटकर भुगतान किया जाएगा।

रतलाम जिला अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालयों की जानकारी

46. (क्र. 2109) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिला अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किये गये थे? (ख) यदि हाँ तो किस वर्ष में किन-किन स्थानों पर किन-किन विद्यालयों को उत्कृष्ट घोषित कर, घोषित करने के दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना बजट किन-किन वर्षों में स्वीकृत होकर उससे क्या-क्या कार्य किये गये? साथ ही उपरोक्त उत्कृष्ट विद्यालयों के शैक्षणिक सुधार हेतु क्या-क्या गुणात्मक, सकारात्मक कार्य

किये जाकर उनसे शिक्षा के सुधार में किस-किस प्रकार के परिणाम परिलक्षित हुए? (ग) जिले के समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों को उपरोक्तानुसार घोषित किये जाने से लेकर प्रश्न दिनांक तक परिणाम मूलक समस्त निर्माण कार्यों, शैक्षणिक कार्यों एवं किये गये विभिन्न कार्यों से अवगत कराएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

केन्द्र/प्रदेश पोषित योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन

47. (क्र. 2110) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिले में केन्द्र/प्रदेश पोषित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो केन्द्र/प्रदेश की किन-किन योजनाओं का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन होकर उस पर कितना-कितना बजट प्राप्त होकर किस-किस प्रकार से किन-किन कार्यों हेतु क्या-क्या व्यय किया जा रहा है? (ग) वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्तानुसार कार्यों/योजनाओं/निर्माण/सामग्री इत्यादि पर कितना बजट प्राप्त होकर क्या-क्या कार्य किये गये? (घ) रतलाम जिले की वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की उपरोक्तानुसार समस्त भौतिक सत्यापन सहित स्थितियों से अवगत कराएं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) रतलाम जिले की वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का उल्लेख **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** इनका सत्यापन समय-समय पर जिला, विकासखण्ड एवं क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत शासन स्तर से भी समय-समय पर सर्वेक्षण कराया जाता है।

मण्डल संयोजकों की पदोन्नति

48. (क्र. 2139) श्री हर्ष यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग में क्षेत्र संयोजक से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रशासन) एवं क्षेत्र संयोजक से जिला संयोजक के पद पर पदोन्नति की अर्हताकारी सेवा अवधि क्या है? क्या क्षेत्र संयोजक एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की संयुक्त सूची तैयार कर पदोन्नति के प्रस्ताव प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग को भेजे जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक से पूर्व किस-किस वर्ष में ऐसी पदोन्नति की सूची लोक सेवा आयोग को भेजी गई? पदोन्नति के पद पर रिक्त होने के बावजूद किस-किस वर्ष सूची नहीं भेजी

गई? क्यों? कब तक भेजी जावेगी? प्रश्नांश (क) अनुसार पदोन्नति प्रस्ताव न भेजे जाने से 25 वर्षों से कार्यरत मण्डल संयोजकों को पदोन्नति न मिल पाने हेतु कौन उत्तरदायी है? (ग) कब तक विभाग रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति कर मण्डल संयोजक को लाभांवित करेगा? यदि हाँ तो समय सीमा बतावें? और यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विकासखण्ड अधिकारी से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी हेतु अर्हताकारी सेवा अवधि 03 वर्ष है एवं क्षेत्र संयोजक के पद हेतु अर्हताकारी सेवा 05 वर्ष है। पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतिवर्ष पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कराने का प्रावधान है। (ख) दिनांक 01/01/2013 की स्थिति में दिनांक 08/05/2014 को पदोन्नति प्रस्ताव म.प्र; लोक सेवा आयोग को भेजे गये। वर्ष 01/01/2012 की स्थिति में प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी विकास से चाहे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जावेंगे। (ग) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने पर। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब होगी इसकी समय सीमा बताना संभव नहीं है।

विभाग में गैर सरकारी संगठनों से कराये जा रहे कार्य

49. (क्र. 2146) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो कि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से कराये जाते हैं? किन-किन योजनाओं में वर्तमान में कौन से कार्य NGO के माध्यम से संपादित कराये जा रहे हैं? इन कार्यों में वर्षवार कितना व्यय किया गया है? विगत पाँच वर्षों का विवरण, जिलावार, संस्थावार दें? (ख) विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान से कार्य कर रही ऐसे कौन-कौन से N.G.O. हैं जो सतना, भोपाल व रायसेन जिले में विभाग से संबंधित कार्य वर्तमान में कर रहे हैं? इन्हें प्रदत्त कार्य व अब तक किये गए भुगतानों का जिलावार, कार्यवार/प्रोजेक्टवार विवरण दें? (ग) उक्त तीनों जिलों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के नाम-पते, उनके द्वारा अब तक संपन्न कार्य का विवरण उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अमानक दवाओं के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

50. (क्र. 2147) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन/विभाग को प्रदेश में अमानक दवाओं की खरीदी व वितरण के मामले को लेकर कब-कब किन-किन के द्वारा शिकायत/ज्ञापन/मांगपत्र/सूचना आदि दिये गए? प्रकरणवार किनके द्वारा जाँच की जाकर निराकरण किया गया? (ख) प्रदेश में अमानक दवाओं की खरीदी,

वितरण व गुणवत्ता जाँच को लेकर विभाग द्वारा उक्त अवधि में क्या-क्या ठोस कदम उठाकर किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की है ताकि आम जनता को अमानक दवाओं के घातक परिणामों से बचाया जा सके? (ग) क्या विभाग द्वारा उन शासकीय सेवकों को अनावश्यक परेशान और प्रताडित किया जा रहा है, जिन्होंने जनहित में अमानक दवाओं के मामले को शासन के संज्ञान में लाया? यदि हाँ तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों में सेवारत अतिथि शिक्षकों की जानकारी

51. (क्र. 2156) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन प्राथमिक/ माध्यमिक/ हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) में शैक्षणिक सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में कितने अतिथि शिक्षक रखे गए? (ख) अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति/रखे जाने हेतु शासन के क्या नियम/निर्देश है? नियम/निर्देशों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि क्या उक्त अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने में उक्त नियमों का पालन किया गया? यदि नहीं, किया गया तो क्यों? शासन इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या कई स्कूलों में हेडमास्टर/प्राचार्य/शिक्षकों द्वारा अपने ही स्कूलों में अतिथि शिक्षक रख कर भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया है? जानकारी दें? (घ) क्या कई अतिथि शिक्षक अन्य कार्य भी करते हैं? जिसके कारण संबंधित विद्यालय में पढ़ाने नहीं आते हैं और बिना पढ़ाए मानदेय प्राप्त करते हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार। (ख) अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी नियम निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अतिथि शिक्षक नियमानुसार रखे गये हैं, अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शिक्षण कार्य से भिन्न समय में अन्य कार्य कर सकते हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चालू सत्र में विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी एवं शिक्षकों की जानकारी

52. (क्र. 2158) श्री रामसिंह यादव :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में किन-किन प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् थे, एवं इन विद्यालयों में कितने-कितने शिक्षक पदस्थ हैं? (ख) उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को जो मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है? उनका भुगतान समूह संचालकों को क्या विद्यालय में अध्ययनरत् कुल छात्र/छात्राओं के मान से दिया जाता है अथवा प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर मासिक भुगतान किया जाता है? (ग) क्या अनेक स्कूलों में समूहों को मध्यान्ह भोजन का भुगतान स्कूल में अध्ययनरत् कुल विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया है? जब कि मध्यान्ह भोजन केवल उपस्थित छात्र/छात्राओं ने लिया है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जाँच कराकर समूहों को अधिक भुगतान की वसूली करेगा? (घ) स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में मध्यान्ह भोजन कराने के क्या नियम/निर्देश हैं? क्या शिवपुरी जिले में इन नियमों का पालन किया जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिवपुरी जिला अंतर्गत कुल 2262 प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या-162721 एवं शिक्षक संख्या-6386, कुल 703 माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या-109569, शिक्षक संख्या- 2083, कुल 83 हाईस्कूल में छात्र संख्या- 15557 एवं शिक्षक संख्या- 383 तथा कुल 52 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र संख्या- 26069 एवं शिक्षक संख्या 566 है। (ख) जी हाँ, जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का मासिक भुगतान समूह संचालकों को छात्र उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। (ग) जी नहीं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ।

बैगा विकास अभिकरण बैगा जाति को लाभांवित किया जाना

53. (क्र. 2192) श्री रामपाल सिंह :क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के सोहागपुर एवं गोहपारू जनपद पंचायत में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जाति के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है? (ख) क्या शहडोल जिले के जयसिंह नगर एवं ब्यौहारी जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में बैगा जाति के लोग निवास कर रहे हैं? यदि हाँ, तो विभिन्न ग्रामों में उनकी संख्या जनपद पंचायतवार कितनी है? (ग) यदि ब्यौहारी एवं जयसिंह नगर जनपद पंचायत में बैगा जाति के लोग निवास कर रहे हैं, तो अब तक उनके आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हेतु उक्त जनपद पंचायत में बैगा विकास अभिकरण की योजना क्यों नहीं लागू की गयी? क्या भविष्य में उक्त जाति के लोगों के लिये बैगा विकास अभिकरण के तहत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। अभिकरण की स्थापना की गई है (ख) जातिवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध/ प्रकाशित न होने से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (ग) गणवेश प्रदाय, विशेष केन्द्रीय सहायता व अन्य जनजातीय संवर्ग हेतु संचालित योजनाओं का लाभ ब्यौहरी व जयसिंहनगर के बैगा जनजाति के परिवारों को भी मिल रहा है। भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत ही चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर निवासरत इन बैगा परिवारों को भी संरक्षण सह विकास योजना अंतर्गत लाभांशित किया जा सकेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृति

54. (क्र. 2193) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के तहसील मुख्यालयों में आदिम जाति के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्तर के लिये नये छात्रावास की स्वीकृति एवं निर्माण का शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? (ख) यदि नहीं तो क्या छात्र-छात्राओं के हित में ऐसे छात्रावास बनाने की स्वीकृति वर्ष 2015-16 में दी जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) संस्था स्वीकृत न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी ब्लॉक में चिकित्सकों की कमी

55. (क्र. 2221) श्री संजय उड़के : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी ब्लॉक के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, कर्मचारियों के कितने स्वीकृत पद हैं? (ख) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक एवं कर्मचारी पदस्थ हैं एवं कितने कब से रिक्त हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

स्वास्थ्य विभाग में एन.जी.ओ. द्वारा काउन्सलरों की भर्ती

56. (क्र. 2259) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी ग्वालियर के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल डबरा एवं भितरवार में टी.बी. के क्षेत्र में वर्तमान में कब से कौन सा एन.जी.ओ. कार्य कर रहा है? एन.जी.ओ. द्वारा कितने काउन्सलरों की भर्ती की गई? किस दिनांक को विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया तथा क्या शैक्षणिक योग्यता

रखी गई, काउन्सलरों का वेतन छुट्टियां, कार्य का लक्ष्य का ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इस एन.जी.ओ. द्वारा काउन्सलरों की नियुक्ति के नियुक्ति पत्र, काउन्सलरों को दिये गये? काउन्सलरों द्वारा कितने डॉट्स केंद्र बनाये गये, डॉट्स में बॉक्स काउन्सलरों द्वारा कहाँ रखे गये हैं? इस एन.जी.ओ. के कार्य करने की सूचना क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी ग्वालियर तथा बी.एम.ओ. को दी गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर के अधीन सिविल हॉस्पिटल डबरा एवं भितरवार में टी.बी. के क्षेत्र में कैथलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2011-12 से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। (इनके कार्य हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर द्वारा कोई एम.ओ.यू. नहीं किया गया, इनका कार्य हेतु भुगतान ग्लोबल फण्ड द्वारा किया जाता है।) एन.जी.ओ. द्वारा किसी भी काउन्सलरों की भर्तीना की जाकर वॉलेन्टियरों से कार्य कराया जा रहा है, क्रमशः डबरा ग्रामीण क्षेत्र में 05 तथा भितरवार में 04 वॉलेन्टियर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया गया। इनका चयन एन.जी.ओ. प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्रीय जनसमुदाय से किया गया। इनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक रखी गई। वॉलेन्टियरों का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। इनके कार्य का मूल्यांकन कर एन.जी.ओ. द्वारा भुगतान किया जाता है (वॉलेन्टियरों के कार्य हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है।) इनकी कोई छुट्टियां निर्धारित नहीं है। एन.जी.ओ. द्वारा मासिक कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य दिया जाता है। इनके कार्य का ब्यौरा:- 1. ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक बैठक (कम्युनिटी बैठक)। 2. अक्षय संवाद (घर-घर जाकर टी.बी. की जानकारी देना)। 3. संभावित क्षय रोगी को नजदिकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाँच हेतु भेजना। 4. खकार का नमूना एकत्रित कर नजदिकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाँच हेतु भेजना। साथ ही टी.बी. रोग के जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार करना। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार सिविल हॉस्पिटल, डबरा एवं भितरवार में एन.जी.ओ. द्वारा काउन्सलरों की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः प्रश्नांश ख की जानकारी निरंक है। एन.जी.ओ. के कार्य करने की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी, ग्वालियर तथा बी.एम.ओ. को दी गई है।

ग्वालियर जिला में अनु.ज.जाति के हितग्राहियों को अनुदान

57. (क्र. 2260) श्रीमती इमरती देवी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में अनुसूचित जनजाति (सहरिया) के हितग्राहियों को वर्ष 2011-12 से 2012-13 तथा 2013-14 में परिवार मूलक योजना अंतर्गत स्वरोजगार हेतु किस ग्राम के कितने-कितने हितग्राहियों को किस कार्य हेतु कितनी अनुदान राशि स्वीकृत कर प्रदाय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सहरिया जाति के उक्त हितग्राहियों में से

किस ग्राम के किस हितग्राही को उक्त वर्षों में राशि स्वीकृत होने के बाद प्रश्न दिनांक तक राशि, सामग्री जानवर देकर किस कारण लाभांवित नहीं किया गया है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 में सहरिया जाति के उक्त हितग्राहियों को स्वीकृत राशि से लाभांवित होने का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) हितग्राहियों द्वारा बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण स्वीकृत होने के बाद भी राशि खाते में नहीं भेजी जा सकी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' पर अनुसार है। (ग) भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक 07.10.2014 द्वारा गठित समिति से जानकारी संकलित की जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं शासन की योजनाओं के आवंटन में दुरुपयोग

58. (क्र. 2295) श्री महेन्द्र सिंह सिसौंदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में विभाग को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 केन्द्र एवं राज्य से कितनी पुस्तकें, सामग्री एवं विभिन्न मदों में राशि प्राप्त होती है? क्या उसका समय पर आवंटन होता है? गत तीन वर्षों में प्राप्त सामग्री एवं राशि के वितरण के लेखों की जानकारी दें? (ख) क्या गुना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान एवं केन्द्र तथा राज्य शासन की अन्य योजनाओं में बच्चों के लिए प्राप्त सामग्री गत दो वर्षों से वितरण की है या नहीं? यदि हाँ तो गुना जिले की ऐसी कितनी पुस्तकें एवं सामग्री गुना शहर के गायत्री मंदिर के पीछे जाटपुरा स्कूल के कमरों में कितने दिनों से रखी है उन्हें कब तक आवंटित करेंगे? (ग) क्या केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त स्कूली बच्चों की सामग्री पुस्तकें आदि को किसी एक स्कूल में रखने का प्रावधान है तो गुना शहर के जाटपुरा के नाम से गायत्री मंदिर के पीछे वाले स्कूल में क्यों और कितने दिनों से सामग्री रखी है? क्या इस स्कूल के बच्चे खुले मैदान में पढ़ते हैं? इसके लिए कौन दोषी है? कब तक कार्यवाही होगी? (घ) क्या केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त सामग्री एवं राशि का गुना जिले में गत तीन वर्षों के प्राप्त एवं आवंटन समय से नहीं करने की जाँच और कार्यवाही की है? यदि नहीं तो कब तक करेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) गुना जिले को विगत तीन वर्षों में प्राप्त पुस्तकें एवं सामग्री तथा उनके वितरण का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वर्षवार योजनावार प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उपरोक्तानुसार प्राप्त पुस्तकें सामग्री एवं राशि का समय पर आवंटन प्राप्त हुआ है एवं समय पर ही वितरण किया गया है। (ख) प्रश्नाधीन सामग्री गत दो वर्षों में समय पर वितरित की गयी है। विकासखण्ड गुना हेतु शहर के

जाटपुरा नाम से गायत्री मंदिर के पीछे वाले स्कूल के दो कमरों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजनान्तर्गत प्राप्त पुस्तकों हेतु भण्डारण केन्द्र बनाया गया है। जहाँ विगत वर्षों में प्राप्त पुस्तकों में से अवितरित 15, 987 पुस्तकें रखी हुई हैं। जिन्हें आगामी वर्ष की मांग के विरुद्ध समायोजित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र में वितरण किया जावेगा। (ग) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के भण्डारण हेतु पर्याप्त मात्रा में स्थान वाले शासकीय भवन जो सुरक्षा एवं आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त हो, को भण्डारण केन्द्र बनाया जाता है। जाटपुरा विद्यालय स्थान, बिजली, पानी तथा मुख्य मार्ग से पहुंच की दृष्टि से सुविधाजनक है। इस आधार पर इसे भण्डारण केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सभी छात्र कक्षाओं में बैठकर अध्ययन करते हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश क के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आदिवासी बाहुल्य ग्रामों, मजरो एवं टोलों में विद्युतीकरण

59. (क्र. 2306) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के छपारा एवं घनौरा विकास खण्ड में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कितने ग्रामों, मजरे, टोले पर विद्युतीकरण का कार्य निविदाओं के माध्यम से पूर्ण करवाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में जिन ठेकेदारों के द्वारा कार्य किए गए हैं? उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किस एजेंसी ने कब-कब किया है? (ग) क्या अधिकांश पोल एवं कंडक्टर निर्धारित मापदण्ड के नहीं लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी नहीं, समस्त पोल एवं कंडक्टर (ट्रान्सफार्मर) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही लगाये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

आदिम जाति कल्याण विभाग से विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त आवंटन

60. (क्र. 2307) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2014 तक सिवनी जिले में योजनावार, शीर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? त्रैमासिक प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कितनी राशि आहरित की गई है, तथा कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि का विवरण किस-किस संस्था/फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सिवनी के नाम से कितने बैंक खाते हैं? खाते का प्रकार, बैंक का नाम, खाता नम्बर की जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' तथा 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य

61. (क्र. 2318) श्री जितू पटवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति विभाग कलेक्टर कार्यालय इंदौर द्वारा वर्ष 2013-14 एवं सत्र 2014-15 में इंदौर जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में विकास कार्य किये जाने हेतु कितने प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी दें? (ख) सत्र 2013-14 एवं सत्र 2014-15 में विभाग द्वारा इंदौर जिले हेतु प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, तथा कितनी राशि का आवंटन किया गया है? वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी दें? (ग) उपरोक्त वर्षों में आवंटित राशि में से कौन-कौन से विकास कार्य, कितनी राशि से पूर्ण किये गये हैं कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं, तथा कौन से कार्य बाकी हैं? बाकी कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें? (घ) क्या प्रश्नकर्ता की विधानसभा राऊ इन्दौर के पालदा एवं नरलाय क्षेत्र में विकास कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कितनी राशि आवंटित की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में

आदिवासी विकास विभाग से सम्बन्धित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' तथा एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो तथा 'ब' अनुसार है। (ग) उपरोक्त वर्षों में आवंटित राशि से पूर्ण, प्रगतिरत एवं बाकी कार्यों की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' तथा तीन अनुसार है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है।

पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित पुस्तकें

62. (क्र. 2319) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2013-14 एवं 2014-15 में म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा कुल कितनी किताबें छपवाई हैं? वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में कुल कितनी-कितनी किताबें जिलेवार वितरित की गई हैं? वर्षवार जानकारी दें? (ग) प्रदेश में जिला स्तर पर कितनी-कितनी किताबें वितरण उपरांत स्टॉक में शेष बची हैं? (घ) क्या शेष बची पुस्तकें जिलेवार वापस मंगवाई जाती हैं? वर्तमान स्थिति से अवगत कराये?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिविल अस्पतालों में चिकित्सक, महिला चिकित्सक/नर्स के स्वीकृत

63. (क्र. 2328) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पताल सेंवड़ा/भाण्डेर/सामु. स्वास्थ्य केन्द्र इन्दरगढ़ एवं प्राथमिक स्वा. केन्द्रों पर चिकित्सक/महिला चिकित्सक/नर्स/कंपाउण्डर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनके विरुद्ध कितने अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में पदों पर कार्य कर रहे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी विगत कितने वर्षों से कहाँ-कहाँ कार्यरत हैं? कृपया उनके नाम/पद/स्थापना स्थल एवं उनके कार्यकाल का विवरण उपलब्ध कराया जावे एवं जो पद रिक्त हैं वे कब से रिक्त हैं? (ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनके अटैचमेंट किये गये हैं, जिनका वेतन कहीं और से आहरित हो रहा है, तथा वे कार्य अन्यत्र स्थानों पर कर रहे हैं? उनके नाम/पद एवं अटैचमेंट के कार्यकाल का विवरण उपलब्ध कराया जावे? (घ) वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में जिला स्तर से कौन-कौन से पदों के लिये नियुक्तियां की गई हैं? अभ्यर्थियों के नाम/उनका धारित पद/पदस्थी स्थल, उनका वेतनमान तथा वे कौन से कार्यक्रम के तहत एवं कितनी अवधि के लिये संविदा अथवा स्थाई रूप से भर्ती किये गये हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर। (ग) डॉ वीरसिंह खरे, चिकित्सा अधिकारी, एवं श्रीमती शांती अहिरवार, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का संलग्नीकरण आदेश दिनांक 23.02.2015 के द्वारा निरस्त किया गया। जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में दतिया जिले अंतर्गत विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत निश्चित मानदेय पर संविदा नियुक्तियां की गई हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।

व्याख्याता प्रिंटिंग को शा.उ.मा.शाला मेडिकल गढ़ा में पदस्थ किया जाना

64. (क्र. 2337) श्री तरुण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री राजेश कुमार वर्मा व्याख्याता (प्रिंटिंग) व्यावसायिक शिक्षा शा.उ.मा.वि. गढ़ा मेडिकल कॉलेज परिसर में कब से पदस्थ है? क्या प्रिंटिंग ट्रेड संबंधी सामग्री उक्त शाला में नहीं होने के बाद भी संबंधित व्याख्याता को संबंधित शाला में क्यों पदस्थ किया गया है? (ख) क्या वर्णित (क) की शाला में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्र हैं ही नहीं फिर भी शासन संबंधित व्याख्याता को किस कार्य हेतु वेतन दे रहा है? (ग) कब तक वर्णित (क) के व्याख्याता को शासन के मंशानुसार व्यावसायिक शिक्षा से पूर्ण शासकीय शाला में छात्रों का भविष्य बनाने हेतु पदस्थ कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) श्री राजेश कुमार वर्मा दिनांक 01-07-2010 से पदस्थ है। श्री वर्मा दिनांक 27-07-2012 से 01-08-2014 तक जिला शिक्षा केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। दिनांक 01-08-2014 से पुनः कार्यभार ग्रहण किया है, क्योंकि इस विद्यालय में इस हेतु रिक्त पद उपलब्ध था। (ख) योग्यता अनुसार व्याख्याता से शाला से संबंधित अन्य कार्य लिया जा रहा है। (ग) पदस्थापना के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकतानुसार समुचित निर्णय विभाग स्तर पर लिए जाते हैं।

बालक एवं कन्या छात्रावास खोले जाने हेतु प्रस्ताव

65. (क्र. 2344) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला रीवा द्वारा अपने पत्र क्र./जि.सं./छात्रा/14-15/5017/रीवा दिनांक 30.11.2014 द्वारा आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल को विकासखण्ड हनुमना में बहेराडाबर, मुनघई एवं हटा में बालक एवं कन्या छात्रावास खोले जाने हेतु प्रस्ताव सम्प्रेषित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि उत्तर जी हाँ तो इनकी स्वीकृति प्रदाय कर कब तक संचालित कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। अपितु जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, रीवा के पत्र क्रमांक/जि.सं./छात्रा./14-15/5017 दिनांक 30/10/2014 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (ख) संस्था स्वीकृत न होने के कारण संचालित किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रम विद्यालयों की जानकारी

66. (क्र. 2345) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत कितने श्रम विद्यालय संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विद्यालय वार विद्यालय में कार्यरत कर्म. की जानकारी एवं

छात्र संख्या नाम एवं पते के विवरण सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इन श्रम विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को शासन से क्या-क्या सुविधाएं मिलती है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत कुल आठ श्रम विद्यालय संचालित हैं। (ख) प्रश्नांश क के संदर्भ में चाही गयी जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं विद्यालयवार छात्रों की जानकारी नाम एवं पते सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से जिला पंचायत द्वारा मध्याह्न भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है।

अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों की व्यवस्था

67. (क्र. 2379) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला, ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर गैर आरक्षित वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिये कितने आवासीय छात्रावास शासन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो मन्दसौर जिले के इस प्रकार के छात्रावासों की जानकारी दी जावे? (ग) जिला विकासखण्ड एवं तहसील स्तर पर गैर आरक्षित वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिये आवासीय छात्रावासों के निर्माण के संबंध में शासन की कोई योजना है? (घ) मंदसौर जिले में तथा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के छात्रावासों का निर्माण व संचालन कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बालिका शिक्षा, समावेशित शिक्षा एवं बालक छात्रावास योजना के तहत गैर आरक्षित वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिए पृथक से छात्रावास संचालित नहीं किए जाते हैं। (ख) उत्तरांश - क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बालिका शिक्षा योजना अंतर्गत सभी वर्ग के शिक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए, समावेशित शिक्षा योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कक्षा 1 से 8 तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तथा आवासीय बालक योजनांतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष के शाला त्यागी, अनाथ एवं बेघर ऐसे परिवार जिनके पड़ोस में स्कूल नहीं है तथा वनक्षेत्र में निवासरत हैं, जिनको परिवहन सुविधा देना व्यवहारिक नहीं है, ऐसे बालक जिनको देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। निराश्रित/प्लेटफार्म/घूमने वाले उपेक्षित बालकों के लिए छात्रावास संचालन हेतु भारत सरकार से प्रतिवर्ष स्वीकृति प्राप्त की जाती है। बालिका शिक्षा योजना अंतर्गत गैर आरक्षित वर्ग की 9+ आयु वर्ग की शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बालिकाएं, समावेशित योजना अंतर्गत गैर आरक्षित वर्ग के निर्धन विद्यार्थी तथा आवासीय बालक योजनांतर्गत शाला त्यागी, बेघर एवं अनाथ बालक भी प्रवेश ले सकते हैं। अतएव इस संबंध में पृथक से शासन की कोई योजना नहीं है। (घ) उत्तरांश- 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पदों की पूर्ति

68. (क्र. 2380) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के समस्त चिकित्सालयों में वर्ष 2005 से प्रशनांकित दिनांक तक प्रथम, द्वितीय श्रेणी एवं विशेषज्ञों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों से प्रतिवर्ष कितने एम.बी.बी.एस. ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनकी संख्या दी जावे? (ग) इतनी संख्या में चिकित्सा ग्रेजुएट प्रदेश में होने के बावजूद प्रदेश के चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने का क्या कारण है, तथा इन पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) औसतन वार्षिक लगभग 350। वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक कुल 1971 चिकित्सकों नियुक्ति आदेश शासकीय चिकित्सालयों हेतु जारी किये गये हैं। (ग) सामान्यतः एम. बी. बी. एस. स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले चिकित्सक उच्च शिक्षा (स्नातकोत्तर) कारणों से सेवार्ये उपलब्ध नहीं कराते तथा कुछ चिकित्सक बंधपत्र की राशि जमा कर बंधपत्र से विमुक्त हो जाते हैं। चिकित्सकों की रिक्त पद की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की जासकेगी। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "बयालीस"

छात्रावासों के निर्माण में विलम्ब

69. (क्र. 2393) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रावास पोरसा, मुरैना एवं नूराबाद (मुरैना) का निर्माण 2007 एवं 2006 से प्रारंभ होकर वर्तमान तक पूर्ण नहीं हो सका है क्यों? जानकारी दी जावे? (ख) क्या निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से लागत मूल्य दोगुना होने की संभावना है? इस कार्य में विलंब होने के लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी जानकारी दी जावे? (ग) मुरैना जिले में बनाये जा रहे प्री-मैट्रिक छात्रावासों के निर्माण समय पर नहीं होने से कितनी अधिक राशि शासन को देनी होगी? शासन किस पर इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करेगा व कार्यवाही करेगा जानकारी दी जावे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रीमैट्रिक छात्रावास नूराबाद का भवन पूर्ण हो चुका है। कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं है। प्रीमैट्रिक छात्रावास पोरसा एवं संभागीय कन्या छात्रावास मुरैना का भवन निर्माण एजेन्सी द्वारा समय पर कार्य न करने से अपूर्ण है। (ख) निर्माण एजेन्सी के अधिकारियों पर कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की

जाना है। (ग) मुरैना जिले में 02 प्रीमेट्रिक छात्रावास भवन निर्माणाधीन हैं। वास्तविक राशि की गणना भवन निर्माण पूर्ण होने पर बताना संभव होगा।

श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

70. (क्र. 2419) डॉ. मोहन यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने श्रमकार्डधारी श्रमिक हैं? पंचायतवार संख्या बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार किन-किन श्रमकार्डधारियों को शासन की किन-किन योजना से कब-कब लाभान्वित किया गया? पंचायतवार एवं नामवार जानकारी प्रदाय करें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा कुल 1, 204 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। पंचायतवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निम्नानुसार योजनांतर्गत लाभान्वित किया गया है जो कि टेबल 1 में नीचे दिया गया है तथा योजनावार, पंचायतवार तथा नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 3 अनुसार है। टेबल 1

क्रमांक	योजना	लाभान्वित श्रमिक
1.	प्रसूति सहायता योजना	210
2.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	43
3.	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	03
4.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	3290

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

71. (क्र. 2420) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं इनमें से कितनों की पदोन्नति की जाना कब से प्रस्तावित है? पदोन्नति नहीं किये जाने के

क्या कारण हैं? (ख) क्या इन्दौर-उज्जैन संभाग में उज्जैन के अलावा अन्य जिलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? किन्तु उज्जैन में नहीं इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं अधिकारियों की नाम सहित जानकारी प्रस्तुत करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) उज्जैन जिले में चतुर्थ श्रेणी के 330 कर्मचारी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। इनमें से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवपूर्ण करने वाले 04 पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति दिनांक 01-01-2015 से की जाना प्रस्तावित है। नगरीय निकाय/पंचायत निर्वाचन आचार संहिता लागू होने से पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हुई है। (ख) जी नहीं। निर्वाचन आचार संहिता के लागू होने से पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

विभाग द्वारा सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि

72. (क्र. 2438) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी में वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक सामग्री क्रय हेतु प्रदाय आवंटन की राशि, मद का नाम, क्रय की सामग्री का विवरण, व्यय राशि की संपूर्ण जानकारी वर्षवार पृथक-पृथक दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

बगैर ड्रग लाइसेन्स प्राप्त संस्थाओं के खरीदी की जाँच

73. (क्र. 2462) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2013-14 में गाँज बैण्डेज किस-किस संस्था से कितनी-कितनी राशि का क्रय किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वास्थ्य विभाग को गाँज बैण्डेज प्रदाय संस्था को ड्रग लायसेन्स प्राप्त है? यदि हाँ, तो ड्रग लायसेन्स की प्रति प्रस्तुत की जाएँ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बगैर ड्रग लायसेन्स प्राप्त संस्थाओं से गाँज बैण्डेज क्रय किया गया हो तो नियम विरुद्ध आदेश प्रदाय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) स्वास्थ्य विभाग में जिलों द्वारा वर्ष 2013-14 में गाज-बेण्डेज किस संस्था से कितनी राशि का कुल किया गया जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) गाज बेण्डेज का क्रय म.प्र. भंडार क्रय नियम के अन्तर्गत, म.प्र. हाथकरघा एवं हस्त शिल्प संचालनालय एवं म.प्र. खादी ग्रामोद्दोग बोर्ड से किये जाने का प्रावधान है। (ग) "ख" में उल्लेखित संस्थाएँ म.प्र. शासन का उपक्रम हैं। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आर.टी.ई. के तहत वंचित एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का प्रवेश

74. (क्र. 2493) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर.टी.ई. के तहत उज्जैन जिले में किस-किस स्कूल ने सत्र 2011-12 से 2014-15 तक कक्षावार 25 प्रतिशत प्रवेश दिया गया है? संख्या उपलब्ध करावें? किन विद्यालयों ने प्रवेश नहीं दिया की भी सूची कारण सहित उपलब्ध करावें? आर.टी.ई. के तहत जिन विद्यालयों में नर्सरी, के.जी. फर्स्ट, के.जी. सेकण्ड एवं कक्षा 1 है, वहाँ क्या चारों कक्षाओं की निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत में प्रवेश का प्रावधान है? क्या कोई विद्यालय 25 प्रतिशत से अधिक प्रवेश देता है, तो उसे फीस प्रतिपूर्ति की जावेगी? (ख) पहली बार 2011-12 में नर्सरी में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देने के बाद किसी कारण से सीट खाली होने पर अगली कक्षा में उस खाली सीट पर प्रवेश दिया जावेगा? (ग) वर्ष 2015-16 की स्थिति में जिन विद्यालयों में नर्सरी, के.जी. फर्स्ट, के.जी. सेकण्ड एवं कक्षा 1 एवं 2 है, वहाँ उन पांचों कक्षाओं की प्रत्येक कक्षा की निर्धारित छात्र संख्या का 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जावेगा अथवा सिर्फ कक्षा नर्सरी/कक्षा 1 का 25 प्रतिशत? (घ) फीस प्रतिपूर्ति में विद्यालय द्वारा लिये जाने वाले कौन-कौन से शुल्क यथा परीक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, गतिविधि शुल्क, शिक्षण शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है? स्पष्ट उल्लेख करें? 75 प्रतिशत उपस्थिति न होने की स्थिति में फीस प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, ऐसी स्थिति में क्या विद्यालय छात्र से फीस लेने की पात्रता रखता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार निःशुल्क प्रवेश न देने वाले अशासकीय विद्यालयों की कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जी हाँ। जी हाँ। (ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा यथा नर्सरी/के.जी.1/के.जी.2 में न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। कक्षा एक से नीचे की कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देने के बाद किसी कारण से सीट खाली होने पर उस खाली सीट पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। (ग) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। यदि स्कूल में प्री स्कूल में भी शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी/के.जी.1/ के.जी.2 में भी अधिनियम का उक्त प्रावधान लागू होगा। (घ) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य द्वारा बनाये गये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में ये प्रावधानित हैं कि स्कूल प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र के पूर्व

विद्यालय द्वारा दी जाने वाली फीस अधिसूचित करेगा। यह अधिसूचित फीस भी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये विचार में ली जायेगी। जी नहीं।

अध्यापक संवर्ग की स्थानान्तरण नीति व विसंगतियां

75. (क्र. 2521) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवकों हेतु निर्धारित महिला, विकलांग पारस्परिक संविलियन/स्थानान्तरण नीति क्या वर्तमान में लागू नहीं है? यदि नहीं तो विगत 01 वर्ष में इस नीति के तहत आगर जिले में कितने अन्तर्जिला /अन्तर्निकाय स्थानान्तरण किए गए? सूची सहित विवरण देवें? (ख) क्या महिला, विकलांग व पारस्परिक संविलियन/स्थानान्तरण नीति को पुरुषों के लिए भी लागू किये जाने की प्रक्रिया चल रही है? यदि हाँ तो नीति कब तक प्रारम्भ की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि पदोन्नति प्राप्त अध्यापक व नवनियुक्त अध्यापक (संविदा से अध्यापक बने) को नवम्बर की स्थिति में प्रदाय अन्तरिम राहत में विसंगतियाँ हैं? यदि हाँ, तो इसे दूर करने के लिए क्या कोई कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? (घ) राज्य शासन द्वारा एरिया एजुकेशन ऑफिसर (ए.ई.ओ) की नियुक्ति हेतु ली गई परीक्षा का परीक्षफल सार्वजनिक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इस अपारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही एवं न्यायालय में ए.ई.ओ. के संबंध में लंबित याचिकाओं के चलते ए.ई.ओ. की नियुक्ति हो जाएगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार से व कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अध्यापक संवर्ग में स्थानान्तरण की कोई नीति लागू नहीं है, अपितु विभागीय आदेश दिनांक 22-09-14 एवं 28-10-14 के द्वारा अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला, निःशक्तजन तथा पारस्परिक केवल जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत एक निकाय में संविलियन की अनुमति ऑनलाईन किये जाने का प्रावधान किया गया है। आगर जिले में किसी भी अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति को अन्तर्जिला/अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांशप्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अंतरिम राहत का भुगतान शासन आदेशानुसार किया जा रहा है। अंतरिम राहत के भुगतान में विसंगति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) न्यायालयीन निर्णय के प्रकाश में कार्रवाई प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सीहोर जिले के इछावर विधानसभा के पारदी जाति की आरक्षण का लाभ

76. (क्र. 2573) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में इछावर विधानसभा में निवासरत पारदी जाति को पूर्व में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था? कब से जारी नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों? (ख) सीहोर जिले की पारदी जाति किस श्रेणी में आती है? इनके

लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है? (ग) क्या म.प्र. के अन्य जिलों में अनु.जनजाति के अंतर्गत इन्हें आरक्षण प्राप्त हैं? अगर हाँ, तो कहाँ-कहाँ और क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) पारदी जाति नाम आरक्षित वर्ग की किसी श्रेणी में अधिसूचित नहीं है। (ख) सीहोर जिले की पारदी जाति आरक्षित वर्ग की किसी श्रेणी में नहीं है। (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य बीमारी सहायता निधि का उपयोग

77. (क्र. 2574) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में सीहोर एवं होशंगाबाद जिले में कितने हितग्राहियों को राज्य बीमारी सहायता निधि, बाल हृदय उपचार योजना एवं मुख्यमंत्री, चिकित्सा स्वैच्छानुदान सहायता से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विधानसभार जानकारी दें? (ख) अस्पतालवार हितग्राहियों की सूची, नाम पते एवं प्रदान की गई राशि की सूची प्रदान करें? किन-किन बीमारियों के लिए राशि प्रदान की गई, उल्लेख करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्याख्याता/प्राचार्य की गोपनीय चरित्रावली का संधारण

78. (क्र. 2583) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने व्याख्याता उ.मा.वि. प्राचार्य हाई स्कूल एवं प्राचार्य उ.मा.वि. में कार्यरत हैं, जिलेवार, संवर्गवार संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली संधारण का दायित्व किस अधिकारी का है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समस्त शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली का संधारण संबंधित अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? (घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) संलग्न परिशिष्ट पर। (ख) प्राचार्य उ.मा.वि./प्राचार्य हाईस्कूल की गोपनीय चरित्रावली जिला शिक्षा अधिकारी एवं व्याख्याता की गोपनीय चरित्रावली संकुल प्राचार्य द्वारा संधारित की जाती है। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्र

79. (क्र. 2584) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालापीपल एवं पोलायकला के अंतर्गत कितने उपस्वास्थ्य केन्द्र आते हैं? केन्द्रवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में से कौन-कौन से उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्र किन भवनों में संचालित हो रहे हैं? केन्द्रवार जानकारी दें? क्या भवन के अभाव में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं? (घ) भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन कब तक निर्माण कर लिये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालापीपल में 19 एवं पोलायकला में 26 में उप स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** (ग) प्रश्न भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।** जी नहीं, भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र किराये अथवा अन्य भवनों में संचालित हैं। (घ) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "चवालीस"

मातृ दर एवं शिशु मृत्यु दर

80. (क्र. 2597) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में गत 5 वर्षों में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर क्या रही है? वर्षवार, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें? (ख) शासन द्वारा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि का व्यय, किस-किस मद में किया गया? (ग) क्या प्रदेश के 65 प्रतिशत 5 वर्ष तक के बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं? यदि हाँ, तो शासन की राशि के अपव्यय के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में गत 5 वर्षों में मातृ मृत्यु दर वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्ष 2010-11 में 310 प्रति लाख जीवित जन्म, वर्ष 2011-12 में 277 प्रति लाख जीवित जन्म तथा वर्ष 2012-13 में 227 प्रति लाख जीवित जन्म है। मातृमृत्यु दर की तहसीलवार एवं जिलेवार जानकारी प्राप्त नहीं की जाती। संभावित वर्षवार मातृमृत्यु दर की स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। एस.आर.एस. डाटा के अनुसार शिशु मृत्यु दर वर्ष 2009 में 67 प्रति हज़ार जीवित जन्म, वर्ष 2010 में 62 प्रति हज़ार जीवित जन्म, वर्ष 2011 में 59 प्रतिहज़ार जीवित जन्म, वर्ष 2012 में 56 प्रति हज़ार जीवित जन्म तथा वर्ष 2013 में 54 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। शिशु मृत्यु दर की तहसीलवार जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार जिलेवार शिशुमृत्यु दर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य में विगत 5 वर्षों में निम्नानुसार राशि का उपयोग किया गया:-

वर्ष	मातृ स्वास्थ्य	शिशु स्वास्थ्य
2009-10	153689178	291226876
2010-11	177251479	271864640
2011-12	37140450	256368915
2012-13	423491024.50	276735692
2013-14	2905857637.50	362330179

(ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में शिक्षा के गुणवत्ता

81. (क्र. 2600) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में शिक्षा के गुणवत्ता स्तर की वृद्धि के लिए वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से अध्यापन कार्य करने की क्या योजना बना रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर हाँ है तो, योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के समान आदिवासी विकास विभाग के नियंत्रणाधीन आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालय की उ.मा. शालाओं में योजना क्रियांवित है।

शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दूरभाष आधारित प्रणाली

82. (क्र. 2621) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 45 एवं 46 में शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर विकास की दिशा में हमने प्रयास किये हैं, परंतु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अभी भी इस चुनौती को देखते हुए शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर तथा मोबाइल, दूरभाष आधारित प्रणाली प्रारंभ की जावेगी? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) में संबंधित प्रणाली का उपयोग हेतु किस प्रकार से कौन-कौन व्यक्ति अधिकृत होंगे? (ग) यदि उपरोक्त (क) हाँ तो उपरोक्त प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र दिमनी में क्या-क्या गतिविधियां हुईं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) मोबाईल आद्यारित प्रणाली के अंतर्गत आई.वी.आर.एस. पद्धति का पायलट रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज विकासखण्ड में किया जा रहा है। उपस्थिति की जानकारी के प्रेषण के लिये शाला के प्रधानाध्यापक, प्रेषित जानकारी के सेम्पल आधार पर सत्यापन के लिये जनशिक्षक एवं संकुल प्राचार्य, जानकारी संग्रहण तथा रिपोर्टिंग के लिये काल-सेंटर अदियकृत है। (ग) पायलट रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज विकासखण्ड में किया जा रहा है। निरंक।

शालाओं में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता

83. (क्र. 2622) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 51 में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये संविदा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है? (ख) यदि हाँ तो विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना अथवा विकासखण्ड मुरैना व अम्बाह में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति हेतु कितने संविदा शिक्षकों की नियुक्ति कहाँ-कहाँ की गई की जानकारी शाला नाम/विषय आदि सहित दी जावे? (ग) बिंदु क्रमांक 51 के तहत शालाओं में शौचालय तथा पेयजल की मूलभूत व्यवस्थाएँ करना भी सरकार का लक्ष्य है? यदि हाँ तो इस हेतु विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना अथवा विकासखण्ड मुरैना व अम्बाह में किन-किन शालाओं में शौचालय एवं पेयजल की मूलभूत व्यवस्थाएँ की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

बड़वानी में अध्यापकों की पदस्थापना

84. (क्र. 2634) श्री बाला बच्चन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत कितनी पदोन्नतियाँ की गई? संवर्गवार जानकारी देवें? (ख) क्या पदोन्नत अध्यापकों की पदस्थापना में निकाय परिवर्तन किए जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो नियम की छायाप्रति देवें? यदि नहीं, तो बड़वानी जिले में पदोन्नति उपरांत किए गए निकाय परिवर्तन को अवैध मानते हुए ऐसी पदस्थापना को शासन कब तक समाप्त करेगा? (ग) क्या जनपद निकायों से नगरीय निकाय में पदोन्नत किए गए अध्यापकों के कारण नगरीय निकाय के अध्यापक पदोन्नति से पद रिक्तता के कारण वंचित हो गए हैं? यदि हाँ, तो इनकी संख्या बतावें? (घ) क्या निकाय परिवर्तन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो कब तक करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बड़वानी जिले में विगत पाँच वर्षों में अध्यापक संवर्ग की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	सहायक अध्यापक से अध्यापक	अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक
2011	452	37
2013	262	75
2014	145	20
योग	859	132

(ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ख के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बड़वानी जिले में छात्रवृत्तियां का वितरण

85. (क्र. 2635) श्री बाला बच्चन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 में बड़वानी जिले में कब-कब और कितनी छात्रवृत्तियां वितरित की गईं? विधानसभावार बतावें? (ख) शिक्षा सत्र के दौरान किस माह तक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के शासन के निर्देश हैं? (ग) क्या बड़वानी जिले में शिक्षा सत्र एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात भी छात्रवृत्तियों का वितरण किया गया? यदि हाँ, तो कारण बतावें? वितरित छात्रवृत्ति के बिल व्हाउचर्स, बैंक देयक एवं छात्रों के बैंक खातों में भुगतान संबंधी प्रमाणित दस्तावेज दें? (घ) शिक्षा सत्र के दौरान समय पर छात्रवृत्ति भुगतान न होने के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में बड़वानी जिले में विधानसभावार निम्न राशि वितरित की गई हैं। अ- पोस्टमैट्रिक महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति - आदिवासी विकास विभाग द्वारा वितरित की गई है। तिथिवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार है।

विधान सभा क्षेत्र	वितरित राशि लाखों में
1. विधान सभा क्षेत्र बड़वानी	333.64
2. विधान सभा क्षेत्र राजपुर	75.69
3. विधान सभा क्षेत्र सैंधवा	151.71
4. विधान सभा क्षेत्र पानसेमल	27.94
5 अन्य	0.42
योग	589.40

ब- राज्य छात्रवृत्ति - राज्य छात्रवृत्ति समेकित छात्रवृत्ति अंतर्गत लोक शिक्षण विभाग द्वारा वितरित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

विधान सभा क्षेत्र	वितरित राशि लाखों में
1- राजपुर	7261344/-

2- बडवानी	6958788/-
3- पानसेमल	6353676/-
4- सेंधवा	9681792/-
योग	30255600/-

(ख) पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति प्रथम चरण में सितम्बर माह में 50 प्रतिशत, दिसम्बर-जनवरी में 40 प्रतिशत तथा परीक्षा के बाद 10 प्रतिशत प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। राज्य छात्रवृत्ति का वितरण माह फरवरी तक किये जाने के निर्देश है। (ग) जी हाँ। आदिवासी विकास विभाग द्वारा वितरित शासकीय महाविद्यालयों की छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष में ही वितरित की गई। अशासकीय संस्थाओं से प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष उपरान्त वितरित की गई है। प्रमाणित दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। लोक शिक्षण विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति समेकित छात्रवृत्ति योजना में प्रथम बार ऑनलाईन सिस्टम द्वारा बैंक खातों में भुगतान किया गया है, अतः वित्तीय वर्ष उपरान्त वितरित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

खरगोन जिला चिकित्सालय द्वारा रेफर मरीजों की संख्या

86. (क्र. 2661) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिला चिकित्सालय द्वारा इंदौर के लिए कितने मरीज रेफर किए गए कारण सहित माहवार बताएँ? (वर्ष 2014-15) रेफर मरीजों की संख्या सहित बताएँ? (ख) भविष्य में मरीजों को बाहर रेफर नहीं किया जावे इसकी कोई योजना/प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हाँ तो जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2014-15 में जिला चिकित्सालय खरगोन से इंदौर के लिये रेफर किये गए मरीजों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मरीजों को रेफर किये जाने का मुख्य कारण बीमारियों की जटिलता है। (ख) जी हाँ। प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने हेतु विभाग प्रयासरत है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

स्कूलों का उन्नयन

87. (क्र. 2677) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमोर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत - माध्यमिक शाला अन्दवा, घूमन, रिमारी, खुटवा, डभौरा, जनकहाई, पल्हान, डेल्ही आदि विद्यालयों का क्या हाई स्कूल में उन्नयन हेतु कार्यवाही की जा रही है यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत प्रदान की जायेगी? (ख) प्रश्न (क) के ही संदर्भ में- उक्त माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन न होने के कारण क्या छात्र-छात्राओं

की शैक्षणिक सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है यदि हाँ, तो जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये क्या शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार किया जायेगा यदि हाँ, तो समय सीमा बताये?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा। निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों की स्थापना

88. (क्र. 2678) श्री दिव्यराज सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत-ग्राम पंचायत घूमन, लोहगड, लूक (सांगी बस्ती), बडाछ (रिमारी) विकास खण्ड जवा एवं ग्राम पंचायत राजगढ़ विकास खण्ड सिरमौर में क्या अनुसूचित जाति जनजाति छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय की स्वीकृति एवं संचालन हेतु कार्यवाही चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में उक्त ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित न होने के कारण क्या अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है? यदि हाँ तो क्या शीघ्र आवासीय संस्थान की स्वीकृति प्रदान कर संचालन कराया जायेगा? यदि हाँ तो समय सीमा बतायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति के आवासीय विद्यालय की स्वीकृति/संचालन की कार्यवाही नहीं चल रही है। (ख) संबंधित ग्राम पंचायतों के सर्वे अनुसार 6 से 10 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बच्चे विद्यालय में दर्ज हैं। कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं है। अतः आवासीय विद्यालय न होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है।

जबलपुर जिले की विभिन्न शालाओं में शौचालय निर्माण

89. (क्र. 2696) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा के अंतर्गत कितनी प्राथमिक व माध्यमिक शालाएँ शौचालय विहीन हैं? इनमें कितनी-कितनी बालक व कन्या शालाएँ हैं? तहसीलवार व शहरी शालाओं की पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) प्रश्नांकित शालाओं में नवीन शौचालय का निर्माण करने के संबंध में शासन ने जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को कब क्या निर्देश जारी किये हैं, तथा नवीन शौचालय निर्माण व शौचालय का रखरखाव मरम्मत आदि के लिये कब-कब, कितनी राशि आवंटित की गई है? (ग) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित शालाओं में से शैक्षणिक सत्र 2014-15 में कितनी शालाओं में नवीन शौचालय का निर्माण कराने हेतु जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर ने कब, कितनी

राशि की क्या योजना बनाई एवं इस योजना अंतर्गत प्रति शौचालय लागत निर्माण अवधि सहित सूची देवे? (घ) मार्च 2014 तक कुल कितनी शालाओं में कितनी लागत से शौचालय का निर्माण कराया गया एवं कितनी शालाओं में दिसम्बर 2014 तक शौचालय निर्माण न होने के क्या कारण है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) पाटन विधानसभा के अंतर्गत कोई भी शाला शौचालय विहीन नहीं है। शेषांश की जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश 'क' के अनुसार एवं शौचालय रखरखाव, मरम्मत हेतु कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार। (घ) मार्च 2014 तक 213 शालाओं में कुल राशि 1,04,85,704/- की लागत से शौचालय निर्माण कराया गया है। शेष उत्तरांश 'क' के अनुसार।

जबलपुर जिले में संचालित जननी एक्सप्रेस

90. (क्र. 2697) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. प्रोग्राम के तहत जननी एक्सप्रेस के संचालन हेतु अनुबंधित करने बावद कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? (ख) जबलपुर जिले में अनुबंधित कितनी जननी एक्सप्रेस संचालित है? अनुबंध व गाइड लाइन के तहत किन-किन अनुबंधित वाहनों में कौन-कौन सी सुविधाएं हैं एवं कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं हैं एवं क्यों? इसकी जाँच कब-कब किसने की है और कब किस पर क्या कार्यवाही की गई? वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 तक की जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश (ख) में कौन-कौन से वाहन कब किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिये मासिक किस दर पर अनुबंधित किये गये हैं? इन्हें किराये की कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया है? वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवे? (घ) क्या शासन प्रश्नांकित जननी एक्सप्रेसों के अनुबंध में की गई अनियमितताओं की जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जबलपुर जिले में वर्ष 2013-14 में 20 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित थे तथा वर्ष 2014-15 में 26 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं। अनुबंध व गाइड लाइन के अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं हैं- (1) वाहन के पीछे की सीट लंबी लगी है। (2) वाहन के उपर नीली रंग की लाईट। (3) वाहन में चढ़ने हेतु सीढ़ी। (4) एक फोल्डिंग स्ट्रेचर। (5) वाहन में अंदर ड्रायवर तथा पीछे के हिस्से के बीच पर्दा। (6) वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम लगा है। समय-समय पर जाँच, विकासखंड स्तर पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय एवं प्रभारी अधिकारी रांझी के द्वारा की गई है, जो सही पाई गयी। इस कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय

में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) अनुबंध में अनियमितता की कोई जानकारी/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

छात्रावास/आश्रम में कार्यरत मजदूर

91. (क्र. 2726) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्तमान में बैतूल जिले में संचालित किस आश्रम एवं किस छात्रावास में कौन-कौन चौकीदार, रसोईया, भृत्य सफाईकर्मी किस दिनांक से कार्यरत हैं? उसे वर्ष 2014 में किस दर से प्रतिमाह कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया? (ख) वर्ष 2014 में कलेक्टर द्वारा दैनिक मजदूरों के लिए क्या दर निर्धारित की उस दर से मजदूरी का भुगतान न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है इन कर्मियों की अंशकालीन दर का निर्धारण किसके द्वारा किस दिनांक को किया गया आदेश की प्रति सहित बतावें? (ग) चौकीदार, भृत्य, सफाईकर्मी एवं रसोईये से आश्रम एवं छात्रावास में प्रतिदिन कितने घण्टे कार्य लिया जाता है? इन कर्मियों को 8 घण्टे से अधिक कार्य किए जाने पर भी अंशकालीन कर्मी माने जाने का क्या कारण है? (घ) वर्ष 2014 में श्रम विभाग बैतूल द्वारा दैनिक मजदूर या अंशकालीन मजदूरों से संबंधित कौन-कौन सी जानकारी किस दिनांक को चाही गई थी वह श्रम विभाग को किस दिनांक को उपलब्ध करवाई गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है। (ग) विभागीय छात्रावास@आश्रमों में जो कर्मचारी नियमित एवं पूर्ण कालिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचार कार्यरत है, उनसे प्रतिदिन आठ घंटे कार्य लिया जाता है। अंशकालिक@सफाईकर्मियों से आवश्यकतानुसार दो से तीन घण्टे कार्य लिया जाता है। (घ) वर्ष 2014 में श्रमपदाधिकारी बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक1781-1785 दिनांक27/11/2014 एवं विभाग द्वारा श्रम पदाधिकारी बैतूल को दिनांक16/02/2015 द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

रख रखाव, मरम्मत हेतु प्राप्त आवंटन

92. (क्र. 2727) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों के रख रखाव, मरम्मत, पुराने भवनों के विद्युतीकरण हेतु विभाग को गत तीन वर्षों में कितना आवंटन प्राप्त हुआ उसमें से कितनी राशि प्रश्नांकित तिथि तक खर्च की गई कितनी राशि सरेण्डर की गई कितनी राशि विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध हैं? (ख) उपरोक्त राशि में से किसे, किस कार्य के लिए कितनी राशि का कार्य आदेश किस दिनांक को जारी किया गया, उसे किस दिनांक को कितनी राशि का भुगतान किया गया कितनी राशि का भुगतान किया जाना किन कारणों से

वर्तमान में लम्बित हैं? (ग) उपरोक्त अवधि में किस कार्य की किस दिनांक को कितनी लागत की प्रशासकीय स्वीकृति किस अधिकारी ने जारी की, तकनीकी स्वीकृति किस अधिकारी के द्वारा जारी की गई किस कार्य का कार्य आदेश जनवरी 2015 तक किन कारणों से जारी नहीं किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2014-15 में छात्रावास/ आश्रमों के सुदृढीकरण मद में उपलब्ध आबंटन से स्वीकृत कार्यों की निविदायें आमंत्रित की जाकर खोली गई हैं। पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने से निविदा स्वीकृति की कार्यवाही लंबित होने से कार्यादेश प्रदाय नहीं किये गये हैं।

आयुष विभाग में कंपाउंडर एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पदोन्नति

93. (क्र. 2730) श्रीमती अनीता सुनील नायक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष विभाग में पदस्थ कंपाउंडर एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम क्या हैं एवं पदोन्नति के पात्रों को कब तक पदोन्नत किया जावेगा? (ख) क्या एलोपैथी कंपाउंडर एवं A.N.M. एवं आयुष कंपाउंडर एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ग्रेड पे में भिन्नता है? यदि हाँ, तो क्यों एवं इसे कब तक सुधारा जावेगा? समय-सीमा बताने का कष्ट करें? (ग) क्या उपर वर्णित एलोपैथी विभाग में पद A.N.M. द्वितीय श्रेणी में है एवं आयुष विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता चतुर्थ श्रेणी में ही है? यदि हाँ, तो ऐसी विसंगति क्यों एवं इसे कब तक दूर किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) म.प्र.शासन आयुष विभाग लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। एलोपैथी कंपाउंडर का पद स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। आयुष विभाग के कंपाउंडर का पद तृतीय श्रेणी का है तथा ए.एन.एम. का पद स्वास्थ्य विभाग में तृतीय श्रेणी का है तथा आयुष विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद चतुर्थ श्रेणी का होने से ग्रेड पे में भिन्नता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी हाँ। योग्यता एवं कार्य भिन्न भिन्न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय योजनाओं में उपलब्ध कराया गया ऋण

94. (क्र. 2743) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला अंत्यावसायी योजनांतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने-कितने आवेदन किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों पर विचार उपरांत किस-किस को लाभ पहुँचाया गया एवं किस-किस को कितनी राशि का ऋण किस-किस कार्य हेतु प्रदान किया गया? कार्यवार, हितग्राहीवार सूची दें? (ख) प्रश्नांक (क) स्वीकृत प्रकरणों में प्रकरणवार पृथक-पृथक हितग्राहीवार कितनी-कितनी सब्सिडी प्रदान की गई? (ग) क्या प्रश्नाधीन स्वीकृत प्रकरणों में से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में मुलचूल परिवर्तन हुआ? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत हितग्राहियों को? प्रश्नांश (क) के अनुसार सूची दें? (घ) क्या प्रश्नाधीन वर्षों में उक्त योजनाओं के संबंध में कलेक्टर कटनी को आवेदकों की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो आवेदकवार प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही की प्रति दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं (ख) जिला अंत्यावसायी योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों में संचालित योजनावार जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं।

छात्रों को दिये जा रहे छात्रवृत्ति के लाभ के संबंध में

95. (क्र. 2744) श्री संजय पाठक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में ऐसे कितने पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं जिन्हें विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? प्राथमिक शाला से लेकर उच्च शिक्षा तक के कितने छात्रों को? सूची दें? (ख) क्या प्रश्नाधीन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की कोई शिकायत विगत दो वर्षों में विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो आवेदकवार प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही की प्रति दें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) कटनी जिले में पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 53, 383 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या 149 है। (ख) जी हाँ, प्रश्नाधीन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की 02 शिकायतें विगत 2 वर्षों में विभाग को प्राप्त हुई। आवेदकवार प्राप्त शिकायतों एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

वन भूमि में निवासरत हरि./आदि. एवं अन्य को पट्टा प्रदाय करने बावत

96. (क्र. 2752) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन भूमि में निवासरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य को उनकी बसाहट के पट्टा देने के प्रावधान है? यदि हाँ तो, पट्टा आवंटन की नियमावली क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में रीवा जिले के उप वनमण्डल मऊगंज एवं हनुमना में वन भूमि में कुल कितने लोग निवासरत हैं? विवरण सहित बतावें? इन निवासरत लोगों में से कितने लोगों को विगत पांच वर्षों में पट्टा प्रदाय किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में जिन लोगों को पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है उन्हें कब तक पट्टा प्रदाय कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व वन भूमि में काबिज तथा 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व तीन पीढियों से काबिज क्रमशः जनजाति एवं वन निवासियों को वन अधिकार पत्र/हक प्रमाणपत्र देने का प्रावधान है। वन अधिनियम 2006 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत पट्टा आवंटन का नियम नहीं है। (ख) प्रश्नांश अन्तर्गत प्राप्त कुल 845 में से मऊगंज के 34 तथा हनुमना के 05 कुल 39 जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को हक प्रमाणपत्र वितरित किये गये। (ग) पात्र 301 दावों का पी.डी.ए. सर्वे किया जा रहा है। समस्त प्रक्रिया अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होने के कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभागीय आवास गृह का अनाधिकृत आधिपत्य

97. (क्र. 2782) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि रजिस्ट्रार, नर्सिंग, काउन्सिल के पद पर पदस्थ कर्मचारी को अधिष्ठाता, इंदौर के अधीन उपलब्ध विभागीय आवास गृहों में एक आवास गृह आवंटित हैं? यदि हाँ तो, संबंधित की काउन्सिल में पदस्थापना होने के पश्चात् क्या उक्त आवास गृह को आधिपत्य में रखने की विधिवत् अनुमति अधिष्ठाता, इंदौर द्वारा जारी की गई है? यदि नहीं तो क्या उक्त आवास गृह को अनाधिकृत रूप से आधिपत्य में रखा गया है? (ख) भोपाल में पदस्थापना के पश्चात् रजिस्ट्रार को आवंटित विभागीय आवास गृह के मासिक किराये की राशि किस-किस दिनांक को किस दर से विधिवत् वसूल की जाकर शासकीय कोष में जमा की गई? (ग) क्या विभागीय आवास आवंटन नियमों के प्रावधानों के अनुसार यदि आवास गृह आधिपत्य में रखने की अनुमति जारी नहीं की गई है? तो क्या किराये की राशि की वसूली सामान्य दर से दुगुनी बाजार दर पर वसूल की जाकर जमा की गई अथवा नहीं? यदि नहीं तो नियमानुसार मासिक किराये की राशि जमा न किये जाने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक राशि की वसूली हेतु कार्यवाही न करने वाले संबंधितों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) अनाधिकृत आधिपत्य रखने के आधार पर नियमानुसार आवास गृह के किराये की राशि बाजार दर से दुगुनी दर पर वसूल की जाकर शासकीय कोष में राशि जमा कराने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के आदेश क्रमांक 12557-62/भवन/आवास/2013, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी को पदस्थापना उपरांत शासकीय आवास गृह क्रमांक एच-1, एम.वाय. चिकित्सालय परिसर इन्दौर के आधिपत्य में दिनांक 22 मई, 2013 तक रखने की अनुमति प्रदान की गई थी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 2014 द्वारा नियम 45 बी के अन्तर्गत उक्त आवास गृह प्रतिनियुक्ति की अवधि तक आधिपत्य में रखने की अनुमति जारी की गई है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) माह जनवरी, 2015 तक सामान्य दर से आवास किराया भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया गया है। भोपाल में पदस्थापना के पश्चात् रजिस्ट्रार को आवंटित विभागीय आवास गृह के मासिक किराये की राशि आवास आवंटन नियमों के तहत 45 बी के अनुसार किराये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (ग) एवं (घ) नियमानुसार किराये की राशि की वसूली की जाएगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पन्ना जिले में कुपोषण नियंत्रण

98. (क्र. 2824) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा संचालित किन-किन

कार्यक्रमों, योजनाओं के लिए पन्ना जिले में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और अल्परक्तता रोकने के लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई? (ख) पन्ना जिले में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विगत दो वर्षों में क्या नतीजे रहे, तथा वर्तमान में कुपोषण से प्रभावित बच्चों और महिलाओं को स्वस्थ बनाने के लिए क्या प्रयास जारी है और उनसे कितने बच्चों तथा महिलाओं को लाभ मिल रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा पन्ना जिले में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और अल्परक्तता रोकने के लिए 2013-14 और 2014-15 में योजनाओं अंतर्गत याजना/कार्यक्रमवार आवंटन एवं व्यय निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना/कार्य	चौरई		अमरवाड़ा	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आर.सी.एच	123480455	103515657	142845892	80212285
2	एन. आर. एच. एम	84569599	66849655	116472399	59773366
3	ईम्यूनाईजेशन	11803279	10080715	11024004	5999467
	योग	226153333	180446027	270342295	145985118

(ख) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के वार्षिक, स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन हेतु पन्ना जिले में 6 पोषण पुर्नवास केन्द्र संचालित है। पन्ना जिले में प्रश्नांकित अवधि में 1911 गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार एवं पोषण पुर्नवास किया गया है तथा 42725 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां अल्परक्तता रोकने हेतु, वितरित की गई हैं।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

स्कूल भवन निर्माण

99. (क्र. 2825) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में ग्राम टाई के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र संख्या को देखते हुए स्थान की कमी के बारे में क्या शासन को जानकारी है? (ख) क्या टाई में विद्यालय भवन बनाने के किसी प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है, यदि हाँ, तो भवन कब तक बनाने की योजना है और यदि नहीं, तो क्या विद्यालय भवन बनाने के लिए शासन विचार करेगा और कब तक विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

100. (क्र. 2845) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परशुराम विद्यालय समिति बिरखड़ी तहसील रौन जिला भिण्ड द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय में कितने-कितने विद्यार्थी किस-किस कक्षा में अध्ययनरत हैं एवं कितना-कितना स्टाफ पदस्थ हैं? पदवार व नामवार विवरण दें? (ख) उक्त विद्यालय को दिनांक 01.04.2009 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार व राशिवार विवरण दें? (ग) क्या कलेक्टर भिण्ड के आदेश क्रमांक/क्यू/एससी-2/2014/6801/भिण्ड दिनांक 23.05.2014 के द्वारा कमेटी गठित कर जाँच कराई गई? यदि हाँ तो जाँच कमेटी द्वारा दिए गए जाँच प्रतिवेदन एवं उसके निष्कर्ष के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) परशुराम विद्यालय समिति बिरखड़ी, तहसील रौन, जिला भिण्ड में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में क्रमशः 15-15 कुल 30 छात्र अध्ययनरत है एवं तीन शिक्षक निम्नानुसार पदस्थ है:-

स.क्र. कर्मचारी का नाम

पद

1	श्री रामसिया झा	उच्च श्रेणी शिक्षक
2	श्री अहिरवरन सिंह कुशवाह	उच्च श्रेणी शिक्षक
3	श्री हाकिम प्रसाद शर्मा	पी.टी.आई.

(ख) प्रश्नांकित अवधि से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार राशिवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि
2009-2010	निरंक
2010-2011	135503@-
2011-2012	141391@-
2012-2013	1171419@-
2013-2014	137030@-
2014-2015	1271692@-

(ग) कलेक्टर द्वारा गठित समिति की जाँच पूर्ण नहीं हुई है, जाँच पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार द्वारा पद का दुरुपयोग

101. (क्र. 2846) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ अधिकारी का मूल विभाग, मूल पद क्या है तथा बोर्ड में वे कितनी समयावधि से प्रभारी रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थ हैं? (ख) बोर्ड रजिस्ट्रार किसके अधीन कार्य करता है, उसके अवकाश स्वीकृति का अधिकार किसे है? (ग) क्या यह सही है कि वर्तमान बोर्ड रजिस्ट्रार के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत की जाने पर, शिकायतकर्ता के विरुद्ध जाँच को प्रभावित करने के उद्देश्य से अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर धमकाने आदि की कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या बोर्ड रजिस्ट्रार का यह कृत्य वैधानिक है? यदि नहीं तो क्या शासन इनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने पर कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ डॉ. एस.सी. खाम्बरा का मूल पद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं विभाग आयुष विभाग है तथा बोर्ड में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1-15/2008/2/ 55 दिनांक 09 मई 2008 द्वारा रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ किया गया है आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) रजिस्ट्रार बोर्ड संचालनालय आयुष एवं म.प्र. शासन दोनोंके अधीन कार्य करता है। आकस्मिक अवकाश बोर्ड द्वारा एवं अर्जित अवकाश व चिकित्सीय

अवकाश, संचालनालय आयुष विभाग द्वारा स्वीकृत करने का अधिकार है। (ग) अधिवक्ता के माध्यम से विभाग में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अइतालीस"

अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का वेतनमान

102. (क्र. 2873) श्री नथनशाह कवरेती :क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का वेतनमान, शासन के नियमानुसार क्या हैं? शासन के आदेश की प्रति रखें साथ ही क्रमोन्नत वेतनमान एवं अंतरिम राहत के क्या प्रावधान है? (ख) क्या छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत क्रमोन्नत सहायक अध्यापक संवर्ग को माह सितम्बर 2013 से देयक अंतरिम राहत/नवीन वेतन संरचना में अध्यापक पद की अंतिम राहत राशि दी जायेगी? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 में क्रमोन्नति प्राप्त सहायक अध्यापक संवर्ग को 2250/- अंतरिम राहत दिये जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ तो अभी तक क्यों वंचित रखा गया है? कब तक दे दी जायेगी? समय सीमा बतायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

विद्युतीकरण/सी.सी. रोड़ की जानकारी बाबत

103. (क्र. 2900) श्री महेन्द्र सिंह :क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही है? योजनावार लाभांशित हितग्राहियों की संख्या देवें? (ख) उक्त विभाग द्वारा संचालित योजना वर्ष से अब तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है? ग्राम व राशिवार जानकारी बतावें? साथ ही वर्तमान में जो कार्य स्वीकृत है क्या पूर्ण करा लिये गये है? यदि नहीं तो ग्राम व राशिवार बतावें? (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खेतों हेतु विद्युतीकरण कराने की योजना कब लागू की गई थी? वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई के विरुद्ध कितनी राशि से वर्षवार विद्युतीकरण कराया गया ग्रामवार जानकारी दें? (घ) उक्त योजना के तहत सीमेंट, कंकरीट रोड़ों का कार्य योजना प्रारंभ से अब तक किन-किन ग्रामों में ग्राम पंचायत वार कितनी-कितनी लागत का कार्य स्वीकृत किये गये? ग्राम, स्थलवार जानकारी बतावें? क्या उक्त राशि का अनुमोदन कराया गया और किन-किन के द्वारा कराया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ग' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'घ' अनुसार है।

शासकीय चिकित्सालयों व निजी चिकित्सालयों को उपकरण खरीदी में दी गयी छूट

104. (क्र. 2902) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल जिले के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सीय उपकरण खरीदे गए हैं? यदि हाँ तो कौन-कौन से कितने-कितने मूल्य के? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त उपकरण किस एजेंसी के माध्यम से किन-किन फर्मों से खरीदे गये हैं? (ग) निजी चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सीय उपकरण खरीदे जाने पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा उनको क्या-क्या छूट प्रदान की जाती है? जानकारी दें? वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल जिले के कौन-कौन से चिकित्सालय इस योजना के माध्यम से उपकरण खरीद चुके हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) निजी चिकित्सालयों द्वारा उपकरण खरीदे जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा छूट नहीं दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालयों में अध्ययनरत अजजा के छात्रों को दी गई स्कालरशिप

105. (क्र. 2903) श्री विश्वास सारंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में स्थित सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों/तकनीकी महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में अध्ययनरत अजजा के छात्रों को वर्ष 13-14 व 14-15 में कितनी-कितनी स्कालरशिप प्रदान की गई? वर्षवार, महाविद्यालयवार, संकायवार प्रदान की गई स्कालरशिपवार जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में के तहत क्या यह सच है कि शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अजा एवं अजजा के छात्रों से ज्यादा निजी महाविद्यालय में उसी संकाय में अध्ययनरत छात्रों को स्कालरशिप प्रदान की गई है? यदि हाँ तो कितनी ज्यादा और क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के अंतर्गत ऐसे कितने मामले जानकारी में आये हैं कि एक छात्र दो-दो महाविद्यालय में प्रवेश लेकर दोनों स्थानों से स्कालरशिप ले रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री जान सिंह) : (क) भोपाल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) जी नहीं। चयनित पाठ्यक्रमों को छोड़ कर सभी पाठ्यक्रमों में शासकीय संस्था से ज्यादा स्कॉलरशीप भुगतान नहीं की गई है। मात्र चयनित 07 पाठ्यक्रमों में केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क की सीमा में भुगतान किया जा रहा है।

क्र.	पाठ्यक्रम	निर्धारित न्यूनतम शुल्क प्रतिवर्ष
------	-----------	-----------------------------------

1	एम.बी;बी.एस	3, 37, 000/-
2	बी.डी.एस	1, 35, 000/-
3	बी.ई.	37, 000/-
4	बी.फार्मा	37, 000/-
5	नर्सिंग	45, 000/-
6	पॉलीटेक्निक	22, 000/-
7	बी.एड;	25, 000/-

मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-15/2013/25-2/2041 भोपाल, दिनांक 11/09/2013 आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) भोपाल जिले अन्तर्गत ऐसे मामले प्राप्त नहीं हुए हैं।

मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना का क्रियान्वयन

106. (क्र. 2909) श्री आरिफ अकील :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश में 5 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक मिडिल स्कूल स्थापित किये जाने का वादा किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि 100 दिन की अपेक्षा लगभग 400 दिन व्यतित हो जाने के पश्चात भी वादा पूरा करने में नाकाम रहे? (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और यदि नहीं तो यह अवगत करावें कि प्रदेश में घोषणा के पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्तर के कुल कितने स्कूल थे और वर्तमान में कितने हैं तथा घोषणा के पालन में किस-किस जिले में कितने-कितने स्कूलों का निर्माण कराया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश- क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2012-13 में प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय 84, 057 तथा माध्यमिक विद्यालय 30,266 थे वर्तमान स्थिति में भी प्राथमिक विद्यालय 84057 तथा माध्यमिक विद्यालय 30,266 है। मापदण्ड पूर्ण करने वाली बसाहटों के 3 कि.मी. की परिधि में माध्यमिक शाला की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। वर्ष 2012-13 में 3112 हाई स्कूल एवं 2242 हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं वर्तमान (वर्ष 2014-15) में 2857 हाई स्कूल एवं 2800 हायर सेकेण्डरी स्कूल है। निर्माण के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। उत्तरांश-'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत राशि प्रदाय

107. (क्र. 2910) श्री आरिफ अकील :क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल है एवं उनमें से

कितनी स्कूल शौचालय विहीन हैं और ऐसे कितने विद्यालय हैं जो किराये के भवन या खुले मैदान में कब-कब से संचालित हो रहे हैं जिलेवार वर्षवार बतावें? (ख) क्या यह सही है कि स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय में उपयोगी शौचालय की उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने संबंधी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय सांसदों एवं विधायकों से उनकी निधि से स्कूलों में शौचालयों निर्मित कराने का आव्हान किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने स्कूलों में कुल कितनी राशि से शौचालय निर्मित किए जाने हैं तथा यह भी अवगत करावें कि स्वच्छ विद्यालय अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र से कितनी राशि प्राप्त हुई हैं? यदि नहीं तो राशि नहीं देने के क्या कारण है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रदेश में हाई@हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या 7370 है। इनमें से 2190 में शौचालय अनुपलब्ध अथवा अक्रियाशील है। प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित शासकीय हाई@हायर सेकेण्डरी स्कूलों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्रदेश में कोई भी शासकीय हाई@हायर सेकेण्डरी शालाएँ खुले मैदान में संचालित नहीं हो रही है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 23402 शौचालयों का नवीन निर्माण एवं 20566 अक्रियाशील शौचालयों के स्थान पर इस प्रकार कुल 43968 शौचालय निर्माण पुनर्निर्माण@जीर्णोद्धार किये जाने हैं। स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत केन्द्र से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शौचालय के पुनर्निर्माण@जीर्णोद्धार हेतु रूपये 1225.36 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। हाई@हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्रदेश के 2190 स्कूलों में 3466 शौचालय युनिट लगभग राशि रूपये 7194.91 लाख से निर्मित किये जाने हैं। शौचालय निर्माण की स्वीकृति लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 143 दिनांक 12-1-2015 से जारी की गई है। इसमें से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 10.44 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शेष शौचालयों की व्यवस्था राज्य बजट एवं अन्य स्रोतों से की गई है।

परिशिष्ट - "उनचास"

विभागीय विश्राम गृह का रख-रखाव पर व्यय

108. (क्र. 2937) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह दिसंबर/14 के सत्र में आजाकवि के नगर परिषद माण्डव में स्थित विश्राम गृह गंगा जमना का संचालन विभाग द्वारा नगर दण्डाधिकारी के माध्यम से होना बताया गया है एवं वर्ष 13-14 में आय मात्र 3700/- रूपये बताई गई है? (ख) क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त विश्राम गृह कई वर्षों से माण्डव के ही होटल व्यवसायी के सुपर्द है? व्यवसायी द्वारा एक रूम का एक दिन का किराया 3000/- वसूल किया जाता है, तथा उक्त विश्राम गृह में तीन रूम एवं हाल है? (ग) क्या शासन उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवाएगा, तथा शासन को प्रतिवर्ष लाखों का चूना लगाकर, झूठी जानकारी देने

वाले सहायक आयुक्त के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समयावधि बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रायवेट स्कूलों को मान्यता

109. (क्र. 2939) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा धार जिले में कितने प्रायवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है? विधानसभा क्षेत्रवार एवं विकास खण्डवार बताया जावे? धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के कितने मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रायवेट स्कूलों की मान्यता के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर मान्यता दी गई है? (ख) धरमपुरी तहसील अंतर्गत सरस्वती ज्ञान मंदिर चन्दावड, पगारा, बगवान्या, ढापला, बाल विकास मंदिर हाईस्कूल चन्दावड एवं बगडी फाटा आदि स्कूलों के कक्षावार दर्ज बच्चों के अनुसार कमरों की क्या-क्या व्यवस्था है? तथा कितने शिक्षक उक्त संस्थाओं में कब से कार्यरत है, तथा उनकी क्या योग्यता है? क्या उनकी मासिक उपस्थिति प्रतिमाह प्राप्त की जाती है तथा कितने कार्यरत शिक्षकों को वेतन का भुगतान खातों के माध्यम से किया जा रहा है? (ग) विधानसभा क्षेत्र के कितने प्रायवेट स्कूलों में एक ही कक्षा में या एक ही शिक्षक द्वारा दो तीन कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रामीण चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति

110. (क्र. 2957) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद स्वास्थ्य केन्द्रवार स्वीकृत हैं? (ख) उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1271 पदों के लिए जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "पचास"

कार्यपालन यंत्री NRHM द्वारा कराये जा रहे कार्य

111. (क्र. 2958) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सिविल निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री का पद कब सृजित किया गया? सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य के मापन मूल्यांकन हेतु विभाग के कितने उपयंत्री, सहायक यंत्री जिलेवार कहाँ-कहाँ कौन-कौन पदस्थ हैं? (ख) विगत दो वर्षों में कार्यपालन यंत्री द्वारा जिलेवार निर्माण कार्य की कितनी राशि की निवदाएँ जारी एवं स्वीकृत की गयी? उक्त निर्माण कार्य की प्रगति क्या है? निर्माण कार्य हेतु अब तक आयटम वार, कार्यवार कितना भुगतान किया गया? कार्य का मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? (ग) शा.जिला चिकित्सालय (महिला) एलिंगन में नवजात शिशु रोग वार्ड के विद्युतीकरण का ठेका किस फर्म को कितनी राशि का स्वीकृत किया गया था? उक्त कार्य कब पूर्ण किया गया? कार्य हेतु आयटमवार कितना भुगतान किया गया? मूल्यांकन अधिकारी कौन था?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनु. जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये योजनायें

112. (क्र. 2968) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में अनु. जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के श्रमिकों के तरक्की के लिए किन-किन योजनाओं में 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट उपलब्ध हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विकासखण्डवार 2012 से 2014 तक हितग्राहीवार, योजनावार लाभान्वित लोगों की सूची प्रदान करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विकासखण्डवार भ्रष्टाचार के लिए कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में 2012 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही हुई है एवं उन्हें दोषमुक्त या बहाल करने में क्या कार्यवाही हुई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

अनूपपुर जिला अंतर्गत औषधालय

113. (क्र. 2971) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा में कुल कितने औषधालय चल रहे हैं? क्या उनमें सब स्थानों पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) क्या यह सब आयुष औषधालय अपने भवन में संचालित हैं? क्या विभाग द्वारा नये भवन प्रस्तावित हैं? यदि हाँ तो स्थानों का उल्लेख करें? (ग) क्या यह सभी भवन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निर्मित होंगे? यदि नहीं तो इनका स्थान परिवर्तन कर ग्राम पंचायत मुख्यालय किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक स्थान परिवर्तन कर इनका निर्माण कार्य कराया जायेगा? (घ) क्या सभी पीएससी, मिनी पीएससी सिविल हास्पिटल परिसर अतिक्रमण मुक्त हैं? यदि नहीं तो कब तक मुक्त किये जायेंगे एवं पुनः यहाँ पर अतिक्रमण न हो उसके लिये क्या योजना बनाई जा रही है? क्या बाउण्ड्रीवाल बनाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो कब तक बन जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनूपपुर जिला चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पद

114. (क्र. 2972) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने स्वीकृत पद हैं? इन पदों पर कौन-कौन कब से पदस्थ है, तथा कितने पद प्रश्न दिनांक की स्थिति में रिक्त हैं? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें? (ख) विगत 3 वर्षों में अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति

शासन द्वारा दी गई है? यदि हाँ, तो कब एवं कितने भवनों की स्वीकृति दी गई है? विवरण दें, कब तक उनका निर्माण कर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।

विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा भारिया को डी.एड. कराने बावत्

115. (क्र. 2988) श्री प्रहलाद भारती : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा एवं भारिया के शिक्षित व्यक्तियों को न्यूनतम योग्यता होने पर शासकीय सेवा में बिना भर्ती परीक्षा पास किये सीधे नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है यदि हाँ, तो नियम/निर्देश उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह भी सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लागू होने के पश्चात् संविदा शिक्षक के पद हेतु न्यूनतम अर्हता डी.एड. न होने के कारण विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा एवं भारिया के लोगों को संविदा शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासन या विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण व्यक्तियों को डी.एड. कराने की कोई योजना है यदि नहीं तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को डी.एड. कराने की व्यवस्था की जाएगी, यदि हाँ, तो कब तक समय अवधि बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री जान सिंह) : (क) सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों को सीधी भर्ती हेतु, मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11/01/2010 के अनुसार "यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहरिया आदिम जनजाति जिला मंडला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर में बैगा आदिम जाति जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय@चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा" का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। (ग) मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-15/ 2013/25-2/2041 भोपाल दिनांक 11/09/2013 से मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के आधार पर अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति कर बी.एड. प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5537 आदिवासी विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों से प्रशिक्षण दिलाये जाने का प्रावधान है। विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थी भी इस योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सहायक शिक्षकों की पदोन्नति

116. (क्र. 2998) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में ऐसे कितने सहायक शिक्षक हैं जिनका सेवाकाल 30 वर्ष पूर्ण हो गया है और उन्हें जनवरी 2015 तक एक भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई? (ख) क्या ऐसे सहायक शिक्षकों को तीसरे समय मान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? (ग) ऐसे

सहायक शिक्षक जिनका सेवाकाल 35 वर्ष पूर्ण हो गया है और पूरे सेवाकाल में 2 वेतनमान ही प्राप्त हुये हैं उन्हें भी तीसरा समय वेतनमान दिया जायेगा एवं कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 609 सहायक शिक्षक है। (ख) नियमों में प्रावधान नहीं है। (ग) नियमों में प्रावधान नहीं है।

ई उपस्थिति के लिए इन्दौर जिले को पायलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना

117. (क्र. 2999) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग में ई उपस्थिति के लिए इंदौर जिले को पायलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो इंदौर जिले में 15.01.2015 तक कितने शिक्षकों द्वारा इसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई गई है? संकुलवार जानकारी दें? (ग) क्या यह योजना शिक्षकों के लिए स्वेच्छिक है? यदि हाँ तो संकुल प्राचार्यों/विकासखंड अधिकारी/जनशिक्षकों के द्वारा शिक्षकों पर एन्ड्राईड फोन खरीदने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? (घ) क्या शिक्षकों के ई उपस्थिति के लिए आवश्यक नेट पेक के लिए कोई राशि देने पर विचार किया जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई/अमरवाड़ा में भोजन अनियमितता

118. (क्र. 3009) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें अथवा उनके साथ आये व्यक्तियों को भोजन आदि उपलब्ध कराने, भोजन व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय करने के संबंध में क्या निर्देश हैं? निर्देशों की प्रति संलग्न करें? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में जनवरी 2012 से अगस्त 2014 तक कुल कितने मरीज भर्ती हुए? मरीजों के भर्ती की तुलना में निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उनके भोजन आदि पर कुल कितनी भोजन सामग्री लगनी चाहिए थी? कितनी लगी? (ग) क्या छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में जनवरी 2012 से अगस्त 2014 के मध्य भर्ती मरीजों की तुलना में शासनादेशों/निर्देशों के विरुद्ध जाकर भोजन सामग्री क्रय नियम/निर्देशों का पालन न करते हुए नियम विरुद्ध खरीदी की गयी डबल हस्ताक्षर प्रणाली से तथा आवश्यकता से अधिक खर्च बताकर भारी अनियमितता गयी है? (घ) क्या यह भी सही है कि छिन्दवाड़ा जिले के

सामुदायिक स्वास्थ्य चौक एवं अमरवाड़ा में जनवरी 2012 से अगस्त 2014 के मध्य भर्ती मरीजों के लिए क्रय किये गये भोजन सामग्री का नियम विरुद्ध बी.एम.ओ. के द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से ही चैक जारी कर संबंधितों को भुगतान किया गया है? यदि हाँ तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं? क्या शासन मरीजों के भोजन आदि पर किये गये खर्च में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार की प्रश्नकर्ता विधायक के उपस्थिति में जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला छिन्दवाड़ा के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शासन द्वारा स्वीकृत समस्त सुविधायें भर्ती मरीजों को दी जा रही है, जिसमें निःशुल्क औषधि, निःशुल्क जाँच एवं आवश्यकता पडने पर परिवहन सुविधा आदि प्रदान की जा रही है। साथ ही भर्ती मरीजों के साथ आये व्यक्तियों के लिये वर्तमान में कोई दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है। भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन प्रतिदिन के हिसाब से शासन के निर्देश की प्रति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है एवं भोजन सामग्री व्यवस्था हेतु शासन के नियमानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिस पर न्यूनतम दर वाली निविदाओं से वर्षभर भोजन सामग्री क्रय की जाती है। (ख) जिला छिन्दवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौरई एवं अमरवाड़ा में जनवरी 2012 से 2014 तक कुल भर्ती मरीजों की संख्या 23279 है। भर्ती मरीजों पर निर्देशों के अनुक्रम में भोजन आदि पर निम्न सामग्री लगाई गई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। प्रत्येक सामग्री किलोग्राम

वित्तीय वर्ष	गेहूँ	चालव	दाल	नमक	मिर्ची	धनिया	जीरा	हल्दी	गरम मसाला	तेल	सब्जी	गैस (पर सिलेण्डर 19 किग्रा.)
2012	1943	1165	767	78	77	78	39	39	39	390	1942	18
2013	1916	715	553	79	79	79	39	39	39	396	1682	11
2014	1792	511	452	75	75	75	37	37	37	379	1552	18
कुल	5651	2391	1772	232	231	232	115	115	115	1165	5176	47

नोट - वित्तीय वर्ष 2013 में सलाद 375 किग्रा एवं दलिया 434 किग्रा एवं वित्तीय वर्ष 2014 में सलाद 482 किग्रा एवं दलिया 682 किग्रा भर्ती मरीज को उपलब्ध कराया गया। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के अनुक्रम में जनवरी 2012 से अगस्त 2014 तक भर्ती मरीजों को शासन के आदेश/निर्देशों के पालन में भोजन, सामग्री क्रय की गई है। अन्य किसी सामग्री पर भर्ती मरीजों की तुलना में अधिक व्यय नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के अनुक्रम में क्रय की गई भोजन, सामग्री के देयकों का भुगतान जिला कोषालय, छिन्दवाड़ा द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से संबंधित विक्रेताओं को किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बावन"**परिवार नियोजक कार्यक्रम की जानकारी**

119. (क्र. 3010) पं. रमेश दुबे :क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से अगस्त 2014 तक किन-किन महिला एवं पुरुषों का नसबंदी किन-किन तिथियों में किया गया है? वर्षवार, व्यक्तिवार, उनके निवास का पता एवं प्रेकों के नाम पता सहित जानकारी दें? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में 2012-13 से अगस्त 2014 तक किन-किन के किस-किस अवधि तक के लिए मोविलिटी वाहन किन-किन के उपयोग हेतु रखे गये? वर्षवार वाहन स्वामी का नाम, पता सहित, वाहन का प्रकार, वाहन उपयोगकर्ता का नाम, पदनाम तथा वाहन रखे जाने के नियम निर्देश सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में रखे गये वाहन स्वामी को कितनी राशि भुगतान की गयी? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में रखे गये वाहनों का क्या कोई अनुबंध निष्पादित की गयी थी? यदि हाँ तो क्या अनुबंध की शर्तों का पालन किया जा रहा था? यदि नहीं तो नियंत्रण अधिकारी के द्वारा क्या एक्शन लिया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार। (घ) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला चिकित्सालय में दवाइयों का क्रय

120. (क्र. 3011) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बैतूल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (दिसंबर) तक कितनी दवाएँ क्रय की गईं? वर्षवार पृथक-पृथक आवंटित राशि की मदवार जानकारी दें? (ख) दवाई क्रय हेतु आवंटित बजट राशि से कितनी राशि की दवाएँ लोकल-परचेस की गई हैं, वर्षवार एवं फर्मवार बतावें? (ग) क्या इस हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी? तथा क्या इनका प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया था? (घ) यदि हाँ तो किन-किन समाचार पत्रों में तथा किन-किन फर्मों की निविदाएं प्राप्त हुईं? इनमें से किस-किस फर्म की निविदाएं स्वीकृत हुईं? वर्षवार जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला बैतूल अन्तर्गत जिला चिकित्सालय में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (दिसम्बर) तक की क्रय की गई दवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार है। वर्षवार/आवंटित बजट की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	मद	दवाओं हेतु आवंटन
1	2012-13	19-2210	6252971/-
		41-2210	3152508/-
2	2013-14	19-2210	8686800/-
		41-2210	3747283/-
3	2014-15	19-2210	5094200/-
		41-2210	1368900/-

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) औषधि क्रय हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी, तथा इनका प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया था। (घ) जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	वर्ष	समाचार पत्र का नाम	प्राप्त निविदाएँ (फर्म का नाम)	स्वीकृत निविदाएँ (फर्म का नाम)
1	2012-13 एवं 2013-14	दैनिक भास्कर भोपाल पत्रिका भोपाल राष्ट्रीय जनादेश बैतूल	1. आन्या मेडिकल सीहोर 2. मोहित हेल्थ केयर भोपाल 3. मेडिजोन भोपाल 4. केपिटल मेडिकल भोपाल 5. अपेक्स फार्मा भोपाल 6. शिवराम इंटरप्रा. भोपाल 7. खंडेलवाल मेडिकल छिंदवाड़ा 8. रिलायरा फार्मा भोपाल 9. संजय मेडिकल सीहोर	1. आन्या मेडिकल सीहोर 2. मोहित हेल्थ केयर भोपाल 3. मेडिजोन भोपाल 4. केपिटल मेडिकल भोपाल 5. अपेक्स फार्मा भोपाल 6. शिवराम इंटरप्रा. भोपाल 7. खंडेलवाल मेडिकल छिंदवाड़ा 8. रिलायरा फार्मा भोपाल

2	2014-15	वर्ष 2014-15 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद की खुली निविदाओं की स्वीकृत दरों पर औषधियां क्रय	
---	---------	---	--

आदिवासी विकास परियोजना बैतूल के संदर्भ में

121. (क्र. 3015) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिवासी विभाग परियोजनांतर्गत आदिवासी कृषकों के खेत तक विद्युतीकरण हेतु पंप ऊर्जाकरण मद स्वीकृत की जाती है? (ख) दि. 01.03.2013 से 31.01.15 तक बैतूल जिलान्तर्गत वर्षवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? तथा कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी गई? (ग) क्या कार्यों की स्वीकृति के लिए स्थानीय विधायकों द्वारा भी पत्र लिखे गये हैं? यदि हाँ तो इन पत्रों द्वारा अनुसूचित कार्य कब-कब स्वीकृत किए गए हैं? (घ) यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) 08 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तिरपन"

उज्जैन जिले में कार्य

122. (क्र. 3019) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विधानसभा क्षेत्रवार दि. 01-01-2012 से 31-01-15 तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए? उनकी स्वीकृति दि., लागत, कार्य पूर्णता दिनांक सहित बतावें? (ख) उपरोक्त में जो कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, अपूर्ण कार्यों में कितनी राशि आहरित की जा चुकी है एवं कितने प्रतिशत कार्य हुआ है, की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार देवें? (ग) उपरोक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) कार्यों पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण

123. (क्र. 3020) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में संवर्गवार/विषयवार शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनके समक्ष कितने पद रिक्त हैं? (ख) कितने स्थानों पर स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं? स्कूलवार सूची देवें? (ग) जिन स्थानों पर स्वीकृत पदों से कम शिक्षक पदस्थ हैं, उनकी सूची भी स्कूलवार देवें? (घ) शासन (ग) अनुसार रिक्त पदों को (ख) अनुसार समायोजन कर भरेगा? समय सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

रिक्त पदों पर पदोन्नति

124. (क्र. 3036) श्री उमंग सिंघार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 5 वर्षों से विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदनों में विभागीय अपर आयुक्त के 3 पद स्वीकृत दर्शाये जा रहे हैं? जिनमें एक पद भरा तथा 2 पद रिक्त है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी सही है तो पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा? उक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शाये गये पदों को भरने हेतु पदोन्नति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था? यदि हाँ तो पदोन्नति क्यों नहीं की गई? सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार उक्त स्वीकृत रिक्त पदों हेतु कब-कब पदोन्नति समिति की बैठक की जानी चाहिए थी? पूर्ण विवरण दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। 01 पद भरा है। 01 विभाग की संरचना से समाप्त करते हुए विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति संचालनालय को सौंपा गया है तथा 01 पद संचालक, राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग में सम्मिलित है, को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा उनके नवीन भर्ती नियमों सम्मिलित कर लिया गया है। (ख) उपरोक्त वर्णित स्थिति में पद रिक्त नहीं हैं। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।